चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित

20 अप्रैल–26 अप्रैल 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

आधार कार्ड ख़तरनाक है

क्या अब इस देश में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का कोई महत्व नहीं रह गया है? यह देश कैसे चलाया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह आदेश दिया कि आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से सभी प्रमुख सचिवों को पत्र लिखने के लिए भी कहा, ताकि किसी भी क़ीमत पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना न हो. सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि इस आदेश को नज़रअंदाज़ करने वालों को जेल भेजा जाएगा. एक तरफ़, सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड की वैधता पर सुनवाई चल रही है, जिसकी अगली तारीख 13 जुलाई, 2015 को है. बावजूद इसके, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना जारी है. आधार योजना से पैदा हुए ख़तरे से आगाह कर रही है चौथी दुनिया की यह रिपोर्ट...

मनीष कुमार

आधार कार्ड को वैधता प्रदान करने वाला बिल संसद में लंबित है. सारे नियम-क़ानूनों को ताक पर रखकर सरकार और सरकारी एजेंसियां पिछले दरवाजे से आधार कार्ड को लागू कर रही हैं. यह तो हद ही हो गई कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को चुनाव से जोड़ना शुरू कर दिया है. चुनाव आयोग राष्ट्रीय निर्वाचक नामावली परिशोधन एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम की शुरुआत कर आधार कार्ड को वोटर पहचान-पत्र के साथ जोड़ने का काम कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना सिर्फ़ चुनाव आयोग ने नहीं की, बल्कि केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारियों पर भी अब आधार कार्ड बनवाने का दबाव डाला जा रहा है. ऑफिस में उपस्थिति (एटेंडेंस) को आधार से जोड़ने का काम चल रहा है. यहां तक कि रक्षा मंत्रालय से जुड़े संस्थानों को भी आधार से जोड़ने की शुरुआत हो गई है. रेल मंत्रालय टिकट आरक्षण (रिजर्वेशन) को आधार से जोड़ने का काम कर चुका है. स्कूलों में प्रवेश (एडमिशन) के लिए आधार कार्ड, गैस सिलेंडर सब्सिडी के लिए आधार कार्ड, पेंशन के लिए आधार कार्ड, राशनकार्ड के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट के लिए आधार कार्ड, बैंक एकाउंट के लिए आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आधार कार्ड यानी हर जगह आधार कार्ड को धड़ल्ले से लागू किया जा रहा है. दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने शादी के पंजीकरण के लिए भी आधार कार्ड की मांग कर दी है. अब तो सांसदों और पूर्व सांसदों से आधार कार्ड बनवाने के लिए कहा जा रहा है. बताया जा रहा है कि कुछ दिनों के बाद जितने भी बच्चे पैदा होंगे, जन्म के तुरंत बाद यानी उसी वक्त उनके बायोमीट्रिक डाटा इकट्ठा कर लिए जाएंगे और आधार नंबर दे दिया जाएगा. मतलब यह कि सरकार पिछले दरवाजे से आधार को लागू कर रही है और जब भी कोर्ट में सरकार से इस बारे में पूछा जाता है, तो सरकार की तरफ़ से यही कहा जाता है कि यह अनिवार्य नहीं है. यह मामला अनिवार्य होने या न होने का नहीं है.

चौथी दुनिया पिछले चार सालों से आधार के बारे में सरकार और लोगों को आगाह करता आया है कि यह कार्ड ख़तरनाक है. यह न सिर्फ़ अवैध है, बल्कि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन भी करता है. दुनिया के किसी भी प्रजातांत्रिक देश में इस तरह की योजना नहीं चलाई जा सकती है. पाकिस्तान अकेला ऐसा देश है, जिसने यह ग़लती की है. क्या हम पाकिस्तान की तरह बनना चाहते हैं, जहां आईएसआई से ज़्यादा जानकारियां सीआईए के पास रहती हैं? देश की सरकार को अब तक यह बात क्यों समझ में नहीं आई है कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, चीन, कनाडा और जर्मनी जैसे देशों में भी इस तरह की योजना शुरू हुई थी, लेकिन जब वे इस योजना से पैदा होने वाले ख़तरे से अवगत हुए, तो वहां बीच में ही इस योजना को ख़त्म कर दिया गया. समझने वाली बात यह है कि आधार कार्ड बनाने और उसके ऑपरेशन में डिजिटल डाटा का इस्तेमाल होता है. यह कार्ड बनाने के लिए लोगों की आंखों की पुतलियों और अंगूठे का निशान आदि जैसे बायोमीट्रिक डाटा लिए जाते हैं. फिर उसे पासपोर्ट, बैंक एकाउंट और फोन से जोड़ दिया जाता है. लोगों की व्यक्तिगत जानकारियां एक सर्वर में एकत्र की जाती हैं, जिस पर विदेशी निजी कंपनियों का अधिकार है. समस्या यह है कि जिन कंपनियों को भारत सरकार ने ये अधिकार दिए हैं, उनका प्रबंधन ऐसे लोगों के हाथों में है, जिनके रिश्ते विदेशी खुफिया एजेंसियों से रहे हैं. दूसरी समस्या यह है कि डिजिटल डाटा आसानी से कॉपी किए जा सकते हैं. जिन लोगों ने डिजिटल डाटा एक बार दे दिया, तो समझिए कि वे सुरक्षित नहीं हैं. लोगों की सारी व्यक्तिगत जानकारियां किन लोगों के हाथों में चली जाएंगी और उनका वे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बारे में सोचते ही पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है. भारत में यूआईडी कार्ड की कहानी विप्रो नामक कंपनी...

(शेष पृष्ठ 2 पर)

मोदी सरकार इन सवालों का जवाब दे

1. 23 सितंबर 2013, 26 नवंबर 2013 और 24 मार्च 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देश के नागरिकों पर आधार कार्ड जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता है. फिर भी सरकारी एजेंसियां इसे अनिवार्य क्यों बना रही हैं?
2. देशवासियों के पर्सनल सेंसिटिव बायोमीट्रिक डाटा विदेश भेजे जा रहे हैं या नहीं?
3. क्या आधार से जुड़े डाटा के इस्तेमाल और उनके ऑपरेशन का अधिकार विदेशी निजी कंपनियों को दिया गया है? इन कंपनियों का इतिहास क्या है? क्या इन कंपनियों के रिश्ते विदेशी खुफिया एजेंसियों से हैं?
4. आधार योजना का काम सरकारी एजेंसियों के बजाय विदेशी कंपनियों के हाथों में क्यों है?
5. आधार के नागरिक इस्तेमाल को सैन्य इस्तेमाल से क्यों जोड़ दिया गया?
6. सरकार क्यों नहीं बताती कि इस योजना पर कितना पैसा ख़र्च होगा?
7. आधार को लेकर संसद में बिल लंबित है. बिल को बिना पास किए यह योजना क्यों जारी है?
8. लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा यूआईडी योजना पर पुनर्विचार करने की बात कहती रही. चुनाव के बाद भाजपा का स्टैंड क्यों बदल गया?
9. भाजपा ने चुनाव से पहले कहा था कि आधार योजना को लेकर पार्टी की दो चिंताएं हैं, एक तो इसका क़ानूनी आधार और दूसरा सुरक्षा का मुद्दा. क्या उक्त चिंताएं अब ख़त्म हो गई हैं?
10. पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट के मुताबिक़, क्या आधार योजना राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने जैसा और नागरिकों की संप्रभुता और निजता के अधिकार पर हमला नहीं है?
11. इस योजना की शुरुआत कब और कैसे हुई और किस आधार पर हुई? यूपीए सरकार को नंदन नीलेकणी द्वारा दिया गया प्रस्ताव कहां है? उसे अविलंब सार्वजनिक किया जाए.

आधार कार्ड
वह सच, जो छिपा दिया गया | P-2

आधार कार्ड
यूआईडी कार्ड नाज़ियों की याद दिलाता है | P-2

आधार कार्ड
देश को गिरवी रखने का षड्यंत्र | P-9

आधार कार्ड ख़तरनाक है

पृष्ठ 1 का शेष

के प्रस्ताव से शुरू होती है, जिसे उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सखा नंदन नीलेकणी चला रहे थे. इस दस्तावेज़ का नाम था, स्ट्रेटिजिक विजन ऑन द यूआईडीएआई प्रोजेक्ट. मतलब यह कि यूआईडी की सारी दलीलें, योजना और उसका दर्शन इस दस्तावेज़ में है. बताया जाता है कि यह दस्तावेज़ अब ग़ायब हो गया है. विप्रो ने यूआईडी की ज़रूरत को लेकर 15 पृष्ठों का एक और दस्तावेज़ तैयार किया, जिसका शीर्षक है, डज इंडिया नीड ए यूनिक आइडेंटिटी नंबर. इस दस्तावेज़ में यूआईडी की ज़रूरत को समझाने के लिए विप्रो ने ब्रिटेन का उदाहरण दिया. इस प्रोजेक्ट को इसी दलील पर हरी झंडी दी गई थी. हैरानी की बात यह है कि ब्रिटेन की सरकार ने अपनी योजना को बंद कर दिया. उसने यह दलील दी कि यह कार्ड ख़तरनाक है, इससे नागरिकों की निजता (प्राइवेसी) का हनन होगा और आम जनता जासूसी की शिकार हो सकती है. अब सवाल यह उठता है कि जब इस योजना की पृष्ठभूमि ही आधारहीन और दर्शनविहीन हो गई, तो फिर सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि वह इसे लागू करने के लिए सारे नियम-क़ानूनों और विरोधों को दरकिनार करने पर आमादा है? कांग्रेस सरकार के जाने के बाद भी यह योजना क्यों लागू है?

सबसे बड़ा ख़तरा यह है कि जितनी भी बायोमीट्रिक जानकारियां हैं, उनकी देखरेख और ऑपरेशन विदेशी कंपनियों के हाथों में है. उन कंपनियों का रिश्ता ऐसे देशों से है, जो जासूसी कराने के लिए कुख्यात हैं. बायोमीट्रिक जानकारियां उन कंपनियों के हाथों में है, जिन्हें विदेशी खुफिया एजेंसियों के रिटायर्ड अधिकारी चलाते हैं. क्या हम जानबूझ कर अमेरिका और विदेशी एजेंसियों के हाथों अपने देश को ख़तरे में डाल रहे हैं? कुछ समय पहले एक खुलासा हुआ था कि अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी एनएसए जिन देशों के इंटरनेट और फोन रिकॉर्ड इकट्ठा कर रही है, उनमें पहला नंबर भारत का है. मजेदार बात यह है कि अमेरिकी सरकार के खुफिया निदेशालय ने भी एक तरह से जासूसी कराने के आरोपों को स्वीकार किया था. निदेशालय ने कहा था कि वह सार्वजनिक तौर पर इस बात का जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि यह उसकी खुफिया नीति का ही एक हिस्सा है. कांग्रेस सरकार को अमेरिका के इस दुस्साहस, ऐसी निगरानी और जासूसी के ख़िलाफ़ कड़ा विरोध जताना चाहिए था, लेकिन हुआ ठीक उल्टा. यूपीए सरकार के तत्कालीन विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद विरोध करने के बजाय अमेरिकी हरकत को सही ठहराने के लिए उल्टी-पुल्टी दलीलें देने लग गए. सलमान खुर्शीद ने कहा कि यह जासूसी नहीं है, यह तो महज कंप्यूटर अध्ययन और कॉलों के पैटर्न का विश्लेषण है. अगर यह जासूसी नहीं है, तो सलमान खुर्शीद को बताना चाहिए कि जासूसी क्या होती है? सरकार बदल गई, लेकिन रवैया नहीं बदला. तो क्या यह मान लिया जाए कि देश में कांग्रेस की सरकार हो या फिर भाजपा की, विदेशी एजेंसियों के सामने हमने घुटने टेक दिए हैं या उन्हें रोकने में हम सक्षम नहीं हैं? हक़ीक़त तो इससे भी ज़्यादा खौफनाक है. भारत सरकार को इस बात की ख़बर तक नहीं है कि हमने आधार योजना लागू करके देश को ख़तरे में डाल दिया है.

ग़ौरतलब है कि अमेरिका के जासूसी प्रकरण पर उसकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी (एनएसए) के साथ काम करने वाले एडवर्ड स्नोडेन ने पिछले दिनों कई खुलासे किए थे. उन्होंने बताया था कि आज के इन्फार्मेशन वारफेयर में भारत कई देशों के निशाने पर है. स्थिति ख़तरनाक है और इससे निपटने की ज़रूरत थी. लेकिन, भारत सरकार ने इससे ठीक उल्टा काम किया. आधार योजना के तहत योजना आयोग ने एर्नेस्ट एंड यंग, साफ्रान ग्रुप, एसेंचर, इन-क्यू-टेल एवं मोंगो डीबी जैसी कंपनियों से करार किए. ये वही कंपनियां हैं, जिन्हें हमने आधार से जुड़े बायोमीट्रिक डाटा की देखरेख और इस्तेमाल का अधिकार दे दिया है. यह देश की सुरक्षा और लोगों के मौलिक अधिकारों के साथ सरासर मज़ाक है. ये कंपनियां उन देशों की हैं, जिनका गठजोड़ पूरी दुनिया पर निगरानी के लिए नेटवर्क तैयार कर रहा है. स्नोडेन ने ही अमेरिकी और ब्रिटिश जासूसी कार्यक्रम का सनसनीखेज ब्यौरा मीडिया को लीक किया था. स्नोडेन के खुलासे के मुताबिक़, अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनएसए एक्स-कीस्कोर (X-Keyscore) नामक जासूसी कार्यक्रम चलाती है. इस कार्यक्रम के तहत दुनिया भर से डाटा हैक करके जानकारियां एकत्र की जाती हैं. 2008 में एक्स-कीस्कोर की एक प्रशिक्षण सामग्री में एक नक्शा पेश किया गया था, जिसमें दुनिया भर में लगे सर्वर का ब्यौरा था. चौंकाने वाली बात यह है कि उस नक्शे के मुताबिक़, उनमें से एक अमेरिकी जासूसी सर्वर भारत की राजधानी नई दिल्ली के किसी समीपवर्ती इलाके में लगा हुआ प्रतीत होता है.

अब सवाल यह है कि अमेरिका के इस खुफिया कार्यक्रम को चलाता कौन है? टेक्नोलॉजी कहां से आती है? सर्वर कौन लगाता है? डाटा चुराने की प्रणाली कौन स्थापित करता है? समझने वाली बात यह है कि जिन कंपनियों को यूआईडी ने हमारी जानकारियां सुपुर्द की हैं, वे वही कंपनियां हैं, जो दुनिया भर में निगरानी प्रणाली स्थापित करने में माहिर मानी जाती हैं. दूसरे विश्व युद्ध के बाद और भारत की आज़ादी से पहले एक नेटवर्क विकसित हुआ था. इसके गठन का एकमात्र उद्देश्य दूसरे देशों की निगरानी करना था. इसमें अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनएसए, इंग्लैंड के गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर्स, कनाडा की कम्युनिकेशन सिक्योरिटी इस्टैब्लिशमेंट, ऑस्ट्रेलिया का सिग्नल डायरेक्टोरेट और न्यूजीलैंड का गवर्नमेंट कम्युनिकेशन सिक्योरिटी ब्यूरो आदि शामिल हैं. अब इस गुट में कई और देश भी शामिल हो चुके हैं. समझने वाली बात यह है कि ये कंपनियां कई देशों में सक्रिय हैं. इनके पास वे तमाम तकनीक उपलब्ध हैं, जिनसे ये किसी भी देश की इंटरनेट कंपनियों के डाटा एकत्र कर सकती हैं, सर्वर हैक कर सकती हैं और फोन सुन सकती हैं. इन कंपनियों की पहुंच कई देशों में है और ये किस तरह और किस स्तर पर काम कर सकती हैं, इसी का खुलासा स्नोडेन ने किया था. सवाल यह है कि उस खुलासे के बाद भारत सरकार ने क्या किया? यह किसी को नहीं मालूम है. एक तरफ़ देश की सरकार है, जो देश की सुरक्षा को लेकर निष्क्रिय है और दूसरी तरफ़ देश की संसद है, जहां वोट बैंक की राजनीति के अलावा कुछ नहीं होता. क्या यह सरकार और संसद का दायित्व नहीं है कि वह इन विषयों पर चर्चा करे और उचित कार्रवाई करे, ताकि यह भरोसा हो सके कि देश सुरक्षित है?

ऐसे माहौल में क्या संसद चुप बैठी रहेगी? क्या भारत को स्वयं को सुरक्षित करने के लिए क़दम नहीं उठाने चाहिए? लेकिन, हम बिल्कुल उल्टे फ़ैसले लेते हैं. ऐसी क्या वजह है कि सरकार देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने पर आमादा है? जबकि यशवंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति भी इसका विरोध कर चुकी है. समिति ने विशिष्ट पहचान अंक (नंबर) जैसे ख़ुफ़िया उपकरणों द्वारा नागरिकों पर सतत नज़र रखने और उनके जैवमापक रिकॉर्ड तैयार करने पर आधारित तकनीकी शासन की पुरजोर मुखालफत की और इसे बंद करने का सुझाव दिया था. यूपीए सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया. लेकिन आज तो भाजपा की सरकार है, तो फिर इन सवालों पर क्यों चुप्पी है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ जाकर आधार योजना को लागू करने और उसे अनिवार्य बनाने पर सरकार आख़िर क्यों आमादा है? सवाल तो यह भी पूछा जाना चाहिए कि क्या अब तक एकत्र किए गए बायोमीट्रिक डाटा को प्राधिकरण ने किसी विदेशी कंपनी के साथ साझा (शेयर) किया गया है? कितना डाटा अब तक विदेशी कंपनियों को हाथ लग चुका है? अगर ये जानकारियां विदेशी एजेंसियों के हाथ लग चुकी हैं, तो इसका एक मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का कोई मतलब नहीं है, जिसमें उसने कहा कि ये जानकारियां किसी के साथ साझा (शेयर) नहीं की जा सकती हैं. और, यह भी मान लेना चाहिए कि हम विदेशी खुफिया एजेंसियों की निगरानी में आ चुके हैं.

नरेंद्र मोदी सरकार को आधार योजना पर पुनर्विचार करना चाहिए. अगर नहीं, तो कम से कम इतना उपकार वह ज़रूर कर दे कि देश की जनता और संसद को बता दे कि इस योजना को किस क़ानून के तहत लागू किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने के पीछे कौन सी वजह है? इससे पहले यह बताया जाए कि लोगों की आंखों की पुतलियों, अंगूठा निशान और बाकी बायोमीट्रिक जानकारियां किस क़ानून के तहत इकट्ठा की जा रही हैं? सरकार यह भी बताए कि लोगों के बायोमीट्रिक डाटा हम किन-किन देशों और कंपनियों को सौंपने का पाप कर रहे हैं? साथ ही उन कंपनियों के इतिहास के बारे में भी बताया जाए, जिन्हें खुफिया एजेंसियों के लोग चला रहे हैं. बड़ी-बड़ी बातें करना आसान है, समाधान ढूंढना कठिन है. क्या हम भारत में एक मेल सर्वर नहीं बना सकते? क्या हम ऐसी व्यवस्था नहीं बना सकते, जिसमें देशवासियों के बायोमीट्रिक डाटा विदेश न भेजने पड़ें? इन तमाम सवालों के जवाब अगर सरकार के पास नहीं हैं, तो विपक्ष ही देश की जनता को सच्चाई बताए. अगर विपक्ष को भी नहीं पता है, तो देश में संविधान और क़ानून का राज ख़त्म करने के पाप में सत्ताधारी दल और विपक्ष, दोनों बराबर के हिस्सेदार होंगे. ■

manishbph244@gmail.com

वह सच, जो छिपा दिया गया

चौथी दुनिया ने पहले भी आधार कार्ड को लेकर एक रिपोर्ट छापी थी, जिससे यह साबित हुआ कि किस तरह यूआईडीएआई ने देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने कार्ड बनाने के लिए तीन कंपनियों को चुना-एसेंचर, महिंद्रा सत्यम-मोर्फो और एल-1 आईडेंटिटी सोल्यूशन. इन तीनों कंपनियों पर ही इस कार्ड से जुड़ी सारी ज़िम्मेदारियां हैं. जब इन तीनों कंपनियों पर ग़ौर करते हैं, तो डर-सा लगता है. एल-1 आईडेंटिटी सोल्यूशन का उदाहरण लेते हैं. इस कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में ऐसे लोग हैं, जिनका अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए और दूसरे सैन्य संगठनों से रिश्ता रहा है. एल-1 आईडेंटिटी सोल्यूशन अमेरिका की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनियों में से है, जो 25 देशों में फेस डिटेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट आदि जैसी चीजें बेचती है. अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के सारे काम इसी कंपनी के पास हैं. यह पासपोर्ट से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस तक बनाकर देती है. इस कंपनी के डायरेक्टरों के बारे में जानना ज़रूरी है. इसके सीईओ ने 2006 में कहा था कि उन्होंने सीआईए के जॉर्ज टेनेट को कंपनी के बोर्ड में शामिल किया है. जॉर्ज टेनेट सीआईए के डायरेक्टर रह चुके हैं और उन्होंने ही इराक के ख़िलाफ़ झूठे सुबूत इकट्ठा किए थे कि उसके पास महाविनाश के हथियार हैं. अब कंपनी की वेबसाइट पर उनका नाम नहीं है, लेकिन जिनके नाम हैं, उनमें से किसी का रिश्ता अमेरिका के आर्मी टेक्नोलॉजी साइंस बोर्ड, तो किसी का रिश्ता आर्म्ड फोर्स कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन, आर्मी नेशनल साइंस सेंटर एडवाइजरी बोर्ड और ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी जैसे संगठनों से रहा है. इस सवाल का जवाब सरकार को देना चाहिए कि यूआईडी वर्ल्ड बैंक की ई-ट्रांसफॉर्म इनिशिएटिव (ईटीआई) का हिस्सा है या नहीं? यह प्रोजेक्ट 23 अप्रैल, 2010 को वाशिंगटन में शुरू किया गया. सरकार को यह बताना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट का मक़सद क्या है, जिसे दुनिया के कई देशों में लागू किया जा रहा है. वर्ल्ड बैंक के इस प्रोजेक्ट में एल-1 आईडेंटिटी सोल्यूशन, आईबीएम, इनटेल और माइक्रोसॉफ्ट की भी भागीदारी है. एल-1 आईडेंटिटी सोल्यूशन की यह हक़ीक़त सरकार ने जनता से क्यों छिपाकर रखी कि इस कंपनी के बोर्ड में अमेरिकी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी रह चुके हैं. अब इस कंपनी का विलय साफ्रान नामक कंपनी में हो चुका है. यूआईडी का विरोध सरकार के अंदर से हो रहा है. सरकार के नज़दीकी भी अब इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठाने लगे हैं. कई सामाजिक कार्यकर्ता, रिटायर्ड न्यायाधीश, अधिकारी, बुद्धिजीवी एवं विशेषज्ञ इसका विरोध कर रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन संसद में इसकी चर्चा तक नहीं हुई और न विपक्ष इस पर कोई दबाव बना रहा है. ■

यूआईडी कार्ड नाज़ियों की याद दिलाता है

अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में यूएस होलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम है. यहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों के नरसंहार से जुड़ी चीजें हैं. इस म्यूजियम में एक मशीन रखी है, जिसका नाम है, होलेरिथ डी-11. इस मशीन को आईबीएम कंपनी ने द्वितीय विश्व युद्ध से पहले बनाया था. यह एक पहचान-पत्र की छंटाई करने वाली मशीन है. तो सवाल यह उठता है कि इस मशीन का होलोकॉस्ट म्यूजियम में क्या काम? दरअसल, यहूदियों के नरसंहार से इस मशीन का गहरा रिश्ता है. हिटलर ने 1933 में जर्मनी में जनगणना कराई थी. यह जनगणना आईबीएम कंपनी ने की थी. इस कंपनी ने जर्मनी में न सिर्फ़ जनगणना की, बल्कि जातिगत जनगणना की. यहूदियों की गणना की और साथ में एक पहचान-पत्र भी दिया था. म्यूजियम में रखी यह मशीन पहचान-पत्र को बांचने का काम करती थी. इसी मशीन ने यहूदियों की पहचान की थी, उनका ठिकाना बताया था. अगर यह मशीन न होती, तो नाज़ियों को यहूदियों के नाम-पते की जानकारी न मिलती. नाज़ियों को यहूदियों की सूची आईबीएम कंपनी ने दी थी. आईबीएम और हिटलर के इस गठजोड़ ने इतिहास के सबसे ख़तरनाक नरसंहार को अंजाम दिया. यूआईडी योजना हमें हिटलर और यहूदियों के नरसंहार के उसी भयानक दौर की याद दिलाती है. 1933 और 2015 में एक बड़ा फ़र्क़ भी है. हिटलर के पास तो यहूदियों के घरों के पते थे, लेकिन यूआईडी के मामले में तो कोई छिप भी नहीं सकता. यूआईडी के साथ तो बैंक एकाउंट और मोबाइल फोन भी जोड़ा जा रहा है. ऐसी हालत में किसी का छिपना संभव नहीं है. क्या मोदी सरकार या कोई राजनीतिक पार्टी यह बात दावे के साथ कह सकती है कि भारत में यूआईडी का ग़लत इस्तेमाल नहीं होगा? जो हाल यहूदियों का जर्मनी में हुआ, वैसी स्थिति भारत में पैदा हो सकती है, ऐसा ख़तरा हमेशा बना रहेगा. सरकार जिस तरह से इस कार्ड को लागू करना चाहती है, उससे तो किसी भी व्यक्ति का छिपना मुश्किल हो जाएगा. इस कार्ड के लागू होते ही फोन या एटीएम के इस्तेमाल मात्र से किसी का भी पता-ठिकाना मालूम किया जा सकता है. क्या भारत सरकार इस बात की गारंटी दे सकती है कि अगर कभी नाजी या उससे भी ख़तरनाक किस्म के लोग सत्ता में आ गए, तो इस कार्ड का इस्तेमाल दंगा, हिंसा और हत्या के लिए नहीं किया जाएगा? इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता है. क्या यूआईडी या नेशनल पापुलेशन रजिस्टर वही कर रहे हैं, जो जर्मनी में किया गया? सवाल यह भी उठता है कि अगर देश के जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता और विशेषज्ञ इस तरह के ख़तरनाक सवाल उठा रहे हैं, तो उसका जवाब सरकार क्यों नहीं देती? इस कार्ड को लेकर संसद में बहस क्यों नहीं हुई? इस कार्ड को बनाने से पहले संसद को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया? इस कार्ड को लेकर कई भ्रांतियां हैं, जिन पर खुली बहस की ज़रूरत है. ■

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 07 अंक 07
दिल्ली, 20 अप्रैल–26 अप्रैल 2015
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय
संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार
एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन
सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-42296060, +91-8451050786, +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

बिहार

रालोसपा की रैली में नहीं जमा रंग

“रालोसपा जितनी बड़ी पार्टी है, उस हिसाब से गांधी मैदान में आए लोग काफी कम थे. कुछ और बेहतर किया जा सकता था, लेकिन संकट यह है कि रालोसपा अभी तक लोकसभा चुनाव के नतीजों के हैंगओवर से बाहर नहीं निकल पाई है. गांधी मैदान में दो लाख लोग इकट्ठा करने वाले हवाई दावे से बेहतर होता कि पार्टी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र चुनिंदा सीटों पर अपना संगठन मजबूत करती. रालोसपा के नेता यह सच स्वीकार कर लेते कि लोकसभा चुनाव की जीत नरेंद्र मोदी की जीत थी और जीत के जो बाकी तत्व थे, वे महज बहाना भर थे.”

सरोज सिंह

पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान पांच अप्रैल को एक बड़ी राजनीतिक कहानी का गवाह बनने को बेताब था, लेकिन रालोसपा की फीकी रैली ने गांधी मैदान की यह हसरत पूरी नहीं होने दी. खैर, गांधी मैदान के लिए यह कोई पहली और अकेली घटना नहीं थी, इसलिए सूबे के राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर चर्चा का बाज़ार नहीं सजा और गांधी मैदान ने रैली के आयोजकों से यह कहकर संतोष कर लिया कि अगर मेरे आंगन में बड़ी लाइन खींचनी हो, तो जतन भी बड़े करो, क्योंकि केवल हवा में तीर चलाकर और पुरानी परिस्थितिजन्य उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटने से अब काम चलने वाला नहीं है. नरेंद्र मोदी के नाम ने रालोसपा की गाड़ी चला तो दी, पर अगर उसे मंजिल तक पहुंचना है, तो हवा-हवाई दावे छोड़कर ज़मीन पर मेहनत हर हाल में करनी ही होगी. रालोसपा की गांधी मैदान रैली पर आएं, उससे पहले इस पार्टी के गठन, इसके संगठन और इसके काम करने के तरीके पर एक छोटी-सी चर्चा ज़रूरी है. उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के कामकाज के तौर-तरीकों पर सवालिया निशान लगाते हुए उनसे अलग होने और एक लोकतांत्रिक पार्टी खड़ी करने का सपना देखा. राजगीर के जदयू सम्मेलन में उपेंद्र कुशवाहा द्वारा दिया गया भाषण हर किसी को याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि बाहर के लोग आकर मलाई खाएं और पार्टी को खड़ा करने वाले कार्यकर्ता टकटकी लगाकर देखते रह जाएं, यह नहीं चलेगा. कार्यकर्ताओं के मान-सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा और उन्हें उनका वाजिब हक़ देना ही होगा.

यह बात नीतीश कुमार को इतनी खटकी कि नतीजे के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा को जदयू से बाहर होना पड़ा. लंबे समय से राजनीतिक बियावान में भटक रहे अरुण कुमार को भी उस समय एक मजबूत साथी की ज़रूरत थी और वक्त की नजाकत को समझते हुए दोनों ने एक साथ चलने का फ़ैसला किया. लोकसभा चुनाव में पचास हज़ार से भी कम वोट मिलने का मलाल अरुण कुमार को इतना सता रहा था कि उन्होंने समय की ज़रूरत को समझते हुए उपेंद्र कुशवाहा को रालोसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार किया और खुद प्रदेश के प्रमुख हो गए. ग़ौरतलब है, किसान महापंचायत के दिनों में उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक कद को लेकर अरुण कुमार की क्या राय थी, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है. खैर, पार्टी बनी और उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी टीम के साथ रात-दिन मेहनत करके रालोसपा को इस लायक बनाया कि दूसरी पार्टियां उसका नोटिस लेने लगीं. लोकसभा चुनाव आते-आते भाजपा जैसी पार्टी को भी लगा कि उपेंद्र कुशवाहा से सीटों का तालमेल किया जाए. तालमेल हुआ और रालोसपा ने अपने हिस्से में आईं तीनों सीटों पर जीत दर्ज की. पार्टी की असली दिक्कत उसके बाद से ही शुरू हुई. उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में मंत्री बन गए और सरकारी कामकाज एवं पहला अनुभव होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा समय दिल्ली में बिताना उनके लिए ज़रूरी हो गया. हालांकि, उपेंद्र कुशवाहा बीच-बीच में बिहार आते रहे, पर वह पहले की तरह पार्टी के कामों पर ध्यान देने में असमर्थ हो गए.

प्रदेश में रालोसपा को विधानसभा चुनाव के लिए खड़ा करने की ज़िम्मेदारी अरुण कुमार पर थी, पर उनका सारा ध्यान दिल्ली की राजनीति में लगा रहा. रालोसपा बिहार में केवल अख़बारी बयानों तक सीमित रह गई. उपेंद्र कुशवाहा ने हालात को समझा, तो फिर से ज़िला स्तरीय सम्मेलनों का आगाज किया गया, लेकिन गाड़ी का एक ही चक्का चल रहा था, दूसरा चक्का या तो चलना नहीं चाह रहा था या फिर पंक्चर था. जैसे-तैसे ज़िला स्तर के कार्यक्रम निपटाए गए और बिना किसी ठोस रणनीति के गांधी मैदान की रैली का ऐलान कर दिया गया. सभी जानते हैं कि गांधी मैदान की रैली को किसी भी राजनीतिक पार्टी की ताकत का मापदंड माना जाता है. इसलिए चुनावी साल में यह ज़रूरी था कि पूरी पार्टी को भरोसे में लेकर रैली की तैयारियां होतीं और गांधी मैदान में एक बड़ी लाइन खींचने की कोशिश की जाती. लेकिन, दुर्भाग्यवश ऐसा कुछ नहीं हुआ और उपेंद्र कुशवाहा अकेले अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए जो कुछ कर सकते थे, करने लगे. इस बीच सीमा सक्सेना के राष्ट्रीय सचिव के तौर पर धमाकेदार प्रवेश ने रालोसपा की लड़ाई पर्दे के बाहर लाकर खड़ी दी. बीस वर्षों से उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहे नागेश्वर स्वराज ने इस पर अपना कड़ा विरोध जताया और पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया.

ग़ौरतलब है कि सीमा सक्सेना नीतीश कुमार के खासमखास मंत्री श्याम रजक की साली हैं. स्वराज का विरोध इस बात को लेकर था कि जिस पैराशूट कल्चर का हम लोग विरोध करते रहे हैं, अब पार्टी धीरे-धीरे उसी को आत्मसात कर रही है. स्वराज को तो रैली के ठीक पहले कुछ आश्वासनों के साथ मना लिया गया, लेकिन मन खट्टा करके लौटा कार्यकर्ता क्या करेगा, यह सबको पता है. रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार को भी सीमा सक्सेना की एंट्री रास नहीं आई और उन्होंने अपना सारा गुस्सा पार्टी प्रवक्ता अभयानंद सुमन पर निकाल दिया. बताया जाता है कि अरुण कुमार उस होर्डिंग से नाराज़ थे, जिसमें सीमा सक्सेना एवं उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर बड़ी थी और नीचे अभयानंद सुमन एवं ललन पासवान के साथ उनकी (अरुण) तस्वीर लगा दी गई थी. अरुण कुमार उस घटना से इतने नाराज़ हुए कि रैली के अगले ही दिन उन्होंने अभयानंद सुमन को पार्टी से बाहर कर दिया. सुमन का मामला अब उपेंद्र कुशवाहा की अदालत में है. पार्टी के लोग कहते हैं कि हम यह कहकर नीतीश कुमार से अलग हुए थे कि जदयू में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है. लेकिन, कोई यह तो बताए कि बिना किसी नोटिस के अभयानंद सुमन को बाहर निकाल देना किस आंतरिक लोकतंत्र का उदाहरण है. पार्टी में कई ऐसे बड़े नेता हैं, जिन्हें अब तक कोई पद नहीं मिला और सीमा सक्सेना अचानक आती हैं और राष्ट्रीय सचिव बन जाती हैं.

जानकार सूत्र बताते हैं कि रालोसपा के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. उपेंद्र कुशवाहा और अरुण कुमार में बेहतर तालमेल न होने का खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ रहा है. जहां तक रैली का सवाल है, तो राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि एक लाख, दो लाख और पांच लाख की हवा-हवाई बातें करना बेमानी है. रालोसपा जितनी बड़ी पार्टी है, उस हिसाब से गांधी मैदान में जितने लोग आए, वे ठीकठाक ही थे. कुछ और बेहतर किया जा सकता था, लेकिन संकट यह है कि रालोसपा अभी तक लोकसभा चुनाव के नतीजों के हैंगओवर से बाहर नहीं निकल पाई है. गांधी मैदान में दो लाख लोग इकट्ठा करने वाले हवाई दावे से बेहतर होता कि पार्टी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र चुनिंदा सीटों पर अपना संगठन मजबूत करती. रालोसपा के नेता यह सच स्वीकार कर लेते कि लोकसभा चुनाव की जीत नरेंद्र मोदी की जीत थी और जीत के जो बाकी तत्व थे, वे महज बहाना भर थे. अगर ऐसा न होता, तो जहानाबाद में राजपूतों एवं भूमिहारों ने एक साथ मिलकर वोट न किया होता और रामकुमार शर्मा जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता सीतामढ़ी जैसी यादव बाहुल्य सीट से भारी मतों से न जीतता. इसी तरह भाजपा और लोजपा के भी कई नेता नरेंद्र मोदी लहर में गंगा नहा गए. इसलिए उस राजनीतिक हालात को आज के विधानसभा चुनाव के हालात से मिलाना राजनीतिक बेमानी है.

प्रस्तावित महाविलय के बाद लालू और नीतीश एक नई ताकत के साथ एनडीए के सामने होंगे. इसलिए रालोसपा के लिए यह वक्त संभलने का है. गांधी मैदान की रैली में जुटी भीड़ ने रालोसपा नेताओं को आगाह कर दिया है कि ज़मीनी सच्चाई समझने का वक्त आ गया है. पैर उतने ही फैलाए जाएं, जितनी बड़ी चादर है. अन्यथा परिणाम विपरीत जा सकते हैं. उपेंद्र कुशवाहा संगठन के माहिर खिलाड़ी हैं, इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि वह समय रहते पार्टी को फिर पटरी पर ले आएंगे. अगर ऐसा न हो पाया, तो फिर रालोसपा में गदर मचना तय है. ■

इस बीच सीमा सक्सेना के राष्ट्रीय सचिव के तौर पर धमाकेदार प्रवेश ने रालोसपा की लड़ाई पर्दे के बाहर लाकर खड़ी दी. बीस वर्षों से उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहे नागेश्वर स्वराज ने इस पर अपना कड़ा विरोध जताया और पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया. ग़ौरतलब है कि सीमा सक्सेना नीतीश कुमार के खासमखास मंत्री श्याम रजक की साली हैं. स्वराज का विरोध इस बात को लेकर था कि जिस पैराशूट कल्चर का हम लोग विरोध करते रहे हैं, अब पार्टी धीरे-धीरे उसी को आत्मसात कर रही है.

अरुण कुमार उस घटना से इतने नाराज़ हुए कि रैली के अगले ही दिन उन्होंने अभयानंद सुमन को पार्टी से बाहर कर दिया. सुमन का मामला अब उपेंद्र कुशवाहा की अदालत में है. पार्टी के लोग कहते हैं कि हम यह कहकर नीतीश कुमार से अलग हुए थे कि जदयू में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है. लेकिन, कोई यह तो बताए कि बिना किसी नोटिस के अभयानंद सुमन को बाहर निकाल देना किस आंतरिक लोकतंत्र का उदाहरण है. पार्टी में कई ऐसे बड़े नेता हैं, जिन्हें अब तक कोई पद नहीं मिला और सीमा सक्सेना अचानक आती हैं और राष्ट्रीय सचिव बन जाती हैं.

feedback@chauthiduniya.com

यूपी आकर गायब हो जाते हैं पाकिस्तानी, शासन तंत्र नाकाम

बदरंग अमन के सात रंग

भारत में भुगत रहे पाकिस्तानी हिंदू

एक तरफ़ भारत आकर पाकिस्तानी मुस्लिम यहां गुम होकर बड़े आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, अवैध रूप से भारत आए बांग्लादेशी वैध हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में धार्मिक अत्याचार और जबरन धर्मांतरण से त्रस्त जो पाकिस्तानी हिंदू भारत आए, वे यहां आकर भुगत रहे हैं. पाकिस्तान में अत्यंत अल्पसंख्यक समुदाय में तब्दील हो चुके हिंदुओं के साथ हो रहे बर्बर अत्याचार के कारण वे शरण लेने के लिए किसी तरह भाग कर भारत आते हैं, लेकिन यहां उनके साथ शासनिक-प्रशासनिक बदसलूकियां होती हैं, उन्हें शरणार्थी शिविरों में अल्प अवधि के लिए रोका जाता है और बदहाली भरी अवधि काटने के बाद जबरन पाकिस्तान भेज दिया जाता है. धर्मनिरपेक्षता पर बात-बहादुरी करने वाला कोई भी नेता पाकिस्तानी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के ख़िलाफ़ बोलने के लिए आगे नहीं आता और पाकिस्तानी मुसलमानों के यहां आकर लापता हो जाने के मसले पर शातिराना चुप्पी साधे रहता है. अत्याचार से विवश होकर भागे पाकिस्तानी हिंदुओं को भारत की नागरिकता देने का मसला भी अर्से से कांग्रेस के पेच में फंसा रहा है और अब लाल-फीताशाही की पेच में फंसा है. गुजरात सरकार की एक पहल पर अब जाकर केंद्र सरकार ने गुजरात या कुछ अन्य राज्यों में रह रहे पाकिस्तानी हिंदुओं को भारत की नागरिकता देने पर सहमति दे दी है. पहले मौजूदा सरकार ने ही उनकी वीजा अवधि बढ़ाने से इंकार कर दिया था. अब जब केंद्र ने सहमति दे दी, तो उसे नौकरशाही के जाल में उलझाया जा रहा है. अब यह सात साल के प्रवास का प्रावधान डाल दिया गया है कि जिन्हें भारत में रहते हुए सात साल से अधिक हो चुके हैं, उन्हें ही भारत की नागरिकता देने पर विचार किया जाएगा. आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में त्रासदी भोग रहे अल्पसंख्यकों का क्या हश्र हो रहा है. पाकिस्तान में कट्टरपंथी धार्मिक अत्याचार और जबरन धर्मांतरण के कारण सैकड़ों हिंदू परिवारों ने भारत में शरण ले रखी है. उन्हें विभिन्न शरणार्थी शिविरों में रखा गया है. कराची से आए हिंदू शरणार्थी राजकुमार जेसरानी का कहना है कि उनकी नागरिकता को लेकर सरकार और सरकारी तंत्र बिल्कुल उदासीन है. जेसरानी पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन विडंबना देखिए, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के कारण उन्हें भाग कर भारत आना पड़ा, लेकिन यहां उनकी कोई सुध नहीं ले रहा. डॉ. जेसरानी कहते हैं कि जो लोग भारत के क़ानून का सम्मान करते हैं और क़ानूनी तौर पर नागरिकता चाहते हैं, उनकी राह में तरह-तरह के रोड़े अटकाए जा रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी मुस्लिम भारत आकर गायब हो जाता है, उसकी सरकार को कोई फिक्र नहीं रहती. ■

प्रभात रंजन दीन

उत्तर प्रदेश में गायब पाकिस्तानियों की तलाश पुलिस और खुफिया एजेंसियों के लिए सिरदर्द बनती जा रही है, लेकिन इससे बेख़बर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भारत और पाकिस्तान के बीच अमन के सात रंग तलाश रहे हैं. मुख्यमंत्री जिस समय लखनऊ में अमन के सात रंग के तहत भारत-पाक जीवन पद्धति से जुड़ी प्रदर्शनी और खान-पान मेले का उद्घाटन कर रहे थे, क़रीब-क़रीब उसी समय उत्तर प्रदेश आकर गायब हुए पाकिस्तानियों की तलाशी के खुफिया संदेश जारी हो रहे थे. खुफिया एजेंसियां यह मानती हैं कि भारत में बदअमनी फैलाने के इरादे से ही यहां आने वाले पाकिस्तानी संदेहास्पद तरीके से गायब हो जा रहे हैं. भारत आकर गायब हो जाने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की खूबी यह है कि यहां गायब होने वाले पाकिस्तानियों को खोज निकालने के प्रति राज्य पुलिस और स्थानीय खुफिया एजेंसियों को तनिक भी चिंता नहीं रहती. राजनीतिक तुष्टिकरण की नीति का असर पुलिस और खुफिया एजेंसियों के कामकाज पर भी सिर चढ़कर बोल रहा है. देश भर में गायब होने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या हज़ारों में है, जबकि उत्तर प्रदेश में तक़रीबन पांच सौ पाकिस्तानी नागरिक लापता हैं.

राजधानी लखनऊ स्थित स्थानीय खुफिया इकाई (एलआईयू) के एसपी अजय कुमार0 रटा-रटाया संवाद कहते हैं कि लापता पाकिस्तानियों की तलाश की जा रही है और इसके लिए स्थानीय पुलिस की भी मदद ली जा रही है. राजधानी की सुरक्षा को लेकर एलआईयू पूरी तरह से मुस्तैद है. पुलिस अधिकारी बदलते रहते हैं, लेकिन संवाद वही रहता है, जिसे अर्से से सुना जा रहा है. इसी संवाद के समानांतर लखनऊ समेत अन्य कई शहरों में बांग्लादेशियों की एक पूरी फौज आकर बस गई है. सतर्क पुलिस व्यवस्था, चौकस खुफिया एजेंसियों और चाक-चौबंद शासन के बीच अकेले लखनऊ में ही लाखों बांग्लादेशी बाकायदा भारतीय नागरिक बनकर बस चुके हैं. उक्त अवैध लोग राजनीतिक दलों के लिए वैध मतदाता हैं, उनके पास बाकायदा बने हुए मतदाता पहचान-पत्र हैं, राशनकार्ड हैं और अब तो आधार कार्ड भी हैं. लखनऊ में एक लाख संदिग्ध बांग्लादेशियों के बसने के मामले की अर्सा पहले जांच भी हुई थी. उनमें से कई ने खुद को असम का रहने वाला बताया था. जांच के लिए टीमें असम भी गईं, जहां जानकारी मिली कि लखनऊ में रह रहे सात सौ बांग्लादेशियों ने असम में प्रवेश कर वहां की नागरिकता हासिल की और फिर लखनऊ पहुंच गए. उन्होंने लखनऊ में भी राशनकार्ड व मतदाता पहचान-पत्र समेत अन्य दस्तावेज तैयार करा लिए. वे आराम से अब भी लखनऊ में रह रहे हैं, पुलिस उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई.

यही हाल धीरे-धीरे पाकिस्तानियों के लिए भी हो जाएगा. पाकिस्तान से भारत की तबाही की सारी व्यवस्थाएं किए जाने के ख़तरे के बावजूद उत्तर प्रदेश की खुफिया एजेंसियों और नागरिकों पर भी कोई असर नहीं पड़ रहा. एजेंसियां आंख मूंदे रहती हैं और स्थानीय नागरिक पाकिस्तानियों को पलकों पर बैठाए और घरों में बसाए रखते हैं. नियम यह है कि किसी भी पाकिस्तानी के आने से पहले ही एलआईयू उसकी बाकायदा छानबीन करती है कि वह जिस जगह आना चाह रहा है, वहां कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं है. सत्यापन के बाद ही पाकिस्तानी को संबद्ध पते पर आने की मंजूरी मिलती है. जिस थाना क्षेत्र में पाकिस्तानी को आना होता है, वहां का भी ब्यौरा दर्ज किया जाता है. यहां आने के बाद पाकिस्तानी नागरिक को सबसे पहले एलआईयू में अपना ब्यौरा दर्ज कराना होता है. इसके बाद एलआईयू महीने में कई बार उसके यहां होने की पुष्टि करती है. किसी भी पाकिस्तानी के पासपोर्ट का विवरण और वीजा की अवधि का पूरा खाका एलआईयू के पास होता है. पाकिस्तानी नागरिक जिस रिश्तेदार या परिचित के यहां रुकता है, उसका भी पूरा विवरण एलआईयू और स्थानीय पुलिस के पास होता है. लेकिन, विडंबना यह है कि नियम होते हुए भी खुद पुलिस और खुफिया एजेंसियां उसकी परवाह नहीं करतीं. न कभी ऐसे पाकिस्तानी नागरिक की खोज-ख़बर ली जाती है और न उसके लापता होने पर संबंधित रिश्तेदार या परिचित को ही उसकी फरारी के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाता है.

इस लचर सुरक्षा व्यवस्था के कारण सैकड़ों पाकिस्तानी उत्तर प्रदेश आकर लापता हो गए और यह सिलसिला जारी है. एलआईयू या पुलिस ने कभी इस बात की तहकीकात नहीं की कि वीजा अवधि कब पूरी हो गई और संबंधित विदेशी नागरिक यहां से रवाना हो गया कि नहीं. एलआईयू या स्थानीय पुलिस को अपनी प्रतिष्ठा की भी चिंता नहीं कि उसके अस्तित्व को ठेंगा दिखाकर दुश्मन देश का नागरिक यहां आकर गुम हो जाता है और यहीं रह रहा होता है. लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में अपने एक रिश्तेदार के घर आया पाकिस्तानी नागरिक शम्सुद्दीन लापता हो गया है. वह पाकिस्तान के कराची का रहने वाला है. यहां छह महीने तक तो उसका पता चलता रहा, फिर अचानक वह गायब हो गया. पुलिस या खुफिया एजेंसियों ने भारतीय रिश्तेदार को भी इस फरारी के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया. अब पुलिस या खुफिया एजेंसियां इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि कराची निवासी शम्शुद्दीन एक अच्छा व्यक्ति था और भारत में लापता होकर वह समाज-सेवा कर रहा है. चौक इलाके में अपने रिश्तेदार के घर आए पेशावर के रफीउद्दीन ने भी यही किया. खुफिया विभाग का कहना है कि दो साल तक सत्यापन किया जाता रहा, लेकिन इसके बाद रफीउद्दीन का सुराग नहीं मिला. लापता रफीउद्दीन भारत में गायब रहकर क्या गुल खिला रहा होगा, इसके बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है. प्रदेश में जारी अलर्ट पर हरकत में आई खुफिया एजेंसियों के सामने कई चौंकाने वाले तथ्य बाहर आए हैं. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, केवल लखनऊ में पिछले कुछ वर्षों में डेढ़ सौ से अधिक पाकिस्तानी आए और उनमें से क़रीब 25 रहस्यमय तरीके से लापता हो गए. उनके पाकिस्तान वापस लौटने की कोई सूचना खुफिया एजेंसियों के पास नहीं है. एजेंसियां कहती हैं कि फरार पाकिस्तानियों की तलाश में वे जुट गई हैं और इसमें पुलिस की भी मदद ली जा रही है, लेकिन इस कथन में पूर्ण सत्यता का घोर अभाव है. खुफिया एजेंसियों के लोग यह भी कहते हैं कि राजधानी लखनऊ में रहने वाले 52 पाकिस्तानियों पर नज़र रखी जा रही है, जिनमें अधिकतर महिलाएं हैं. चार संदिग्ध आतंकी भी लखनऊ में रह रहे हैं. इनमें से हसनगंज खदरा के मशालची टोला में रहने वाले एक व्यक्ति को दिल्ली एटीएस ने गिरफ्तार किया था. वह पिछले दिनों जेल से रिहा होकर फिर लखनऊ आया है. उसने खदरा स्थित अपना मकान बेचकर मड़ियांव क्षेत्र में ठिकाना बनाया है. ऐसे ही तीन अन्य संदिग्धों की भी निगरानी की जा रही है. लखनऊ जेल में बंद कुछ संदिग्ध आतंकियों के मुलाकातियों पर भी नज़र रखी जा रही है. लखनऊ को सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील ज़िलों में रखा गया है. यहां आने-जाने वाले हर विदेशी की जानकारी भी जुटाई जा रही है.

पिछले कुछ अर्से में राजधानी लखनऊ आए तक़रीबन डेढ़ सौ पाकिस्तानियों में से 52 पाकिस्तानी लंबी अवधि के वीजा पर रह रहे हैं. स्थानीय खुफिया इकाई का कहना है कि उन पर निगरानी रखी जा रही है. लेकिन, जो 25 पाकिस्तानी गायब हो गए, वे निगाह में क्यों नहीं थे? इस सवाल का जवाब एलआईयू के पास नहीं है. आधिकारिक तौर पर बताया गया कि पाकिस्तान से यहां आकर लापता पाकिस्तानियों के आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की आशंका है. पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश आतंकवादियों की शरणस्थली रहा. अब लखनऊ भी उसमें शुमार हो गया है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से नौ पाकिस्तानियों को लापता हुए अर्सा हो गया. इसी तरह रामपुर से आठ, गाज़ियाबाद से तीन, हापुड़ से छह, गौतमबुद्धनगर एवं बागपत से एक-एक और बुलंदशहर से तीन पाकिस्तानी गायब हैं. सभी संबद्ध ज़िलाधिकारियों को गायब पाकिस्तानियों को सर्विलांस के ज़रिये ढूंढने के निर्देश दिए गए हैं. ऐसे लोगों पर भी नज़र रखी जा रही है, जो देखते-देखते धनी हो गए हैं. मदरसों और उन कश्मीरी छात्रों पर भी नज़र रखने के लिए कहा गया है, जो इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट कॉलेजों में पढ़ रहे हैं.

उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री आजम खान के क्षेत्र रामपुर में ऐसे सैकड़ों परिवार मिल जाएंगे, जिनकी रिश्तेदारी पाकिस्तान में है. देश विभाजन के वक्त भी रामपुर से ढेर सारे लोग पाकिस्तान चले गए थे. रामपुर के कई घरों में पाकिस्तानी बहुएं हैं, तो कई दामाद पाकिस्तानी हैं. हर साल यहां से सैकड़ों की संख्या में लोग पाकिस्तान जाते हैं और वहां से आते हैं. खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान से रामपुर आए आठ नागरिक गायब हो चुके हैं. खुफिया अधिकारी इसे पुराना मामला बताकर टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके (पाक नागरिक) गायब होने के संबंध में संतोषजनक क़ानूनी जवाब नहीं दे पाते. दूसरी तरफ़ का नज़ारा और भी विचित्र है. उत्तर प्रदेश सरकार की गतिविधियां देखकर यह नहीं लगता कि दुश्मन देश के नागरिकों के संदेहास्पद तरीके से प्रदेश में गुम हो जाने के बारे में उसे कोई चिंता है. प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पिछले दिनों लखनऊ स्थित पर्यटन भवन में अमन के सात रंग कार्यक्रम में बड़े उत्साह से शरीक हुए और उन्होंने इंडो-पाक लाइफ स्टाइल एक्जिबिशन और फूड फेस्टिवल का उद्घाटन किया. अखिलेश ने कहा कि दो देशों के लोगों के आपसी जुड़ाव से रिश्ता मजबूत होता है, इन रिश्तों की डोर से संस्कृतियों का आदान-प्रदान होता है, कारोबारी रिश्ता भी बनता है, सरकारें भी परस्पर संवाद करती हैं. इसलिए रिश्तों को स्थायित्व और मजबूती प्रदान करने के लिए लोगों का एक-दूसरे से जुड़ना ज़रूरी है. व्यवहारिकता से दूर किताबी बातें कहते हुए अखिलेश ने ऐसे मौक़े पर यह कहना उचित नहीं समझा कि रिश्तों की इसी डोर का इस्तेमाल कर पाकिस्तान भारत में बारूद के बीज बोता रहा है और उसकी यह हरकत आज भी जारी है. ■

पिछले कुछ अर्से में राजधानी लखनऊ आए तक़रीबन डेढ़ सौ पाकिस्तानियों में से 52 पाकिस्तानी लंबी अवधि के वीजा पर रह रहे हैं. स्थानीय खुफिया इकाई का कहना है कि उन पर निगरानी रखी जा रही है. लेकिन, जो 25 पाकिस्तानी गायब हो गए, वे निगाह में क्यों नहीं थे?

भारत पर आजम का बड़ा एहसान...

आजम खान के भारत विरोधी बयानों पर भाजपा सांसद महंत आदित्य नाथ ने जब यह कहा कि आजम खान जैसे लोगों को पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए, तो बड़ा बवाल मचा था. इस पर कई बार मर्यादा की सीमाएं लांघकर आजम खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया कि मोदी उन्हें पाकिस्तान कब भेजेंगे. लेकिन, आज जब आजम खान खुद यह बोल रहे हैं कि विभाजन के समय पाकिस्तान न जाकर उन्होंने भारत पर एहसान किया, तो ऐसे बयान पर कोई सुगबुगाहट नहीं हो रही है. आजम खान ने पिछले दिनों मथुरा में आयोजित एक कार्यक्रम में महात्मा गांधी के कंधे पर सांप्रदायिक सियासत की बंदूक रखकर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर धांय-धांय फायरिंग की. उन्होंने कहा कि वह और उनके समुदाय के अन्य लोग महात्मा गांधी को ही देखकर भारत में रुक गए और जिन्ना की बात नहीं मानी. आजम ने यह नहीं कहा कि वह और उनके समुदाय के अन्य लोगों के लिए भारत अपना देश और अपना घर था, जिसके कारण वे पाकिस्तान नहीं गए. आजम खान उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्यमंत्री हैं और वह विधानसभा में आधिकारिक तौर पर बता चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के 34 ज़िलों में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई सक्रिय है. इन ज़िलों में मेरठ भी शामिल है, जिसके आजम खान प्रभारी मंत्री हैं. मेरठ, कानपुर, आगरा, मथुरा, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और हापुड़ को पाकिस्तानी गतिविधियों के कारण अत्यंत संवेदनशील ज़िलों में शुमार किया गया है. ■

feedback@chauthiduniya.com

संस्थान के अंदर कई ऐसी फोटो मिलीं, जिनसे महिला की गतिविधियों का पता चलता है. इतना बड़ा बवाल होने के बावजूद एलबीएस प्रबंधन इस मामले में मीडिया कवरेज से नाराज़ है. यही नाराज़गी रूबी चौधरी की है. दोनों पक्ष मीडिया में अपने ख़िलाफ़ आई ख़बरों से इंकार कर रहे हैं. दिन में जहां रूबी खुले आम घूमकर पुलिस को बयान देने के लिए बुला रही थी, वहीं रात में उसकी गिरफ्तारी हो गई. यानी दिन में रूबी की स्थिति को लेकर पुलिस का रुख स्पष्ट नहीं था. जब उसने दिन में पत्रकारों को अपना बयान दिया, तो एलबीएस प्रबंधन घबरा गया और तुरंत पुलिस को उसकी गिरफ्तारी के संकेत दिए गए. गिरफ्तारी के बाद जब रूबी को दून महिला अस्पताल में लाया गया, तो पुलिस ने उसे पत्रकारों से बात नहीं करने दी.

झारखंड

सौ दिन की रघुवर सरकार काम कम बातें ज्यादा

मुख्यमंत्री रघुवर दास और अन्य भाजपा नेताओं को मालूम है कि इस बार वे बहुमत के अभाव का बहाना बनाकर बच नहीं सकते. इसलिए प्रचार माध्यमों में सरकार की कागजी उपलब्धियों के बखान में वे कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे. सौ दिन पूरे होने के अवसर पर सरकार ने बड़े-बड़े विज्ञापनों में अपनी उपलब्धियों की लंबी सूची जनता के सामने रखी. विज्ञापनों में स्थानीयता, ग्रेटर रांची, भ्रष्टाचार उन्मूलन, ईमानदार छवि, विकास योजनाओं, आदिवासी कल्याण और गुड गवर्नेंस आदि मुद्दों पर लिए गए फ़ैसले जोरदार ढंग से रखे गए हैं. लेकिन, हक़ीक़त यह है कि इनमें से एक-दो मुद्दों को छोड़कर बाकी पर अब तक नेताओं-अधिकारियों की बैठकों, दौरों और प्रेस कांफ्रेंस से ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है.

रंजीत

किसी भी सरकार के मूल्यांकन के लिए 100 दिन नाकाफी होते हैं, लेकिन उसकी दिशा और विजन के संकेत तो मिल ही जाते हैं. छह अप्रैल को झारखंड की रघुवर सरकार ने अपने कार्यकाल के सौ दिन पूरे कर लिए, लेकिन अब तक उसने किसी भी मोर्चे पर कोई ठोस शुरुआत नहीं की है. हां, इतना ज़रूर है कि मुख्यमंत्री रघुवर दास और भाजपा के नेता अच्छी-अच्छी बातें खूब कर रहे हैं. बैठकों, बयानों और भाषणों के ज़रिये जनता को छद्म एहसास दिलाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि सरकार राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए कृतसंकल्प है. जबकि सच्चाई यह है कि बिगड़ी क़ानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, मृतप्राय: प्रशासनिक ढांचा, खस्ताहाल बिजली व्यवस्था, दलाल संस्कृति, पलायन, लचर स्वास्थ्य सेवा एवं नक्सलवाद जैसी तमाम पुरानी समस्याओं के निदान की दिशा में सरकार अब तक कोई क़दम नहीं उठा सकी है. यही वजह है कि सरकार से आस लगाए बैठे विभिन्न संगठनों का धैर्य जवाब देने लगा है. अगले पखवाड़े से राज्य में एक बार फिर आंदोलनों की शुरुआत होने वाली है. शिक्षक संघ से लेकर बिजली यूनियन तक ने ताल ठोंक रखी है. बिजली कामगार, टेट उत्तीर्ण शिक्षक और पैरा शिक्षक आंदोलन की राह पर हैं. मदरसा शिक्षक भी आंदोलन के मूड में हैं. इसके अलावा अराजपत्रित महासंघ प्रोन्नति की मांग को लेकर आंदोलन करने वाला है, वहीं दूसरी ओर सचिवालय के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों में जबरदस्त नाराज़गी है. राज्य स्वास्थ्य सेवा (स्टेट हेल्थ सर्विस) के हज़ारों कर्मचारी भी चरणबद्ध आंदोलन करने वाले हैं.

मुख्यमंत्री रघुवर दास और अन्य भाजपा नेताओं को मालूम है कि इस बार वे बहुमत के अभाव का बहाना बनाकर बच नहीं सकते. इसलिए प्रचार माध्यमों में सरकार की कागजी उपलब्धियों के बखान में वे कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे. सौ दिन पूरे होने के अवसर पर सरकार ने बड़े-बड़े विज्ञापनों में अपनी उपलब्धियों की लंबी सूची जनता के सामने रखी. विज्ञापनों में स्थानीयता, ग्रेटर रांची, भ्रष्टाचार उन्मूलन, ईमानदार छवि, विकास योजनाओं, आदिवासी कल्याण और गुड गवर्नेंस आदि मुद्दों पर लिए गए फ़ैसले जोरदार ढंग से रखे गए हैं. लेकिन, हक़ीक़त यह है कि इनमें से एक-दो मुद्दों को छोड़कर बाकी पर अब तक नेताओं-अधिकारियों की बैठकों, दौरों और प्रेस कांफ्रेंस से ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है. बीस जनवरी को मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आला अधिकारियों के साथ बैठक के बाद लोगों को आश्वस्त किया था कि कोयला-लोहा चोरी और ज़मीन की दलाली करने वाले और भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को बर्खास्त किया जाएगा, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई. प्रदेश की मौजूदा राजनीति और प्रशासनिक ढांचे के मद्देनज़र इस बात की संभावना भी कम है कि आने वाले दिनों में कोई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. स्थानीयता को लेकर जो राजनीति गरमा रही है, वह इस आशंका को बल प्रदान करती है.

ग़ौरतलब है कि सरकार ने घोषणा कर रखी है कि राज्य के सबसे संवेदनशील मुद्दे स्थानीयता की नीति अप्रैल के अंत तक बना ली जाएगी, लेकिन इसे लेकर पक्ष-विपक्ष के बीच जो राजनीतिक दांव-पेंच शुरू हो गए हैं, उन्हें देखकर तो यही लगता है कि आने वाले कई महीनों तक स्थानीयता की आड़ में ही सरकार अपना गुजारा करेगी. पिछले 14 वर्षों में यह पहला अवसर है कि जब झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है. झारखंड विकास मोर्चा के छह विधायकों को अपने में मिला लेने के बाद अब भाजपा को गठबंधन साथी आजसू के सहयोग की भी ज़रूरत नहीं है. यही वजह है कि इस सरकार से लोगों की उम्मीद बहुत ज़्यादा है. प्रदेश की राजनीति के जानकारों का मानना है कि जनता का ध्यान विकास और गवर्नेंस के मुद्दे से हटाने के लिए स्थानीयता का सवाल गरमाए रखना सरकार के लिए सबसे सुरक्षित उपाय है.

हाल के दिनों में मुख्यमंत्री रघुवर दास के कुछ ऐसे बयान आए हैं, जो पार्टी लाइन से मेल नहीं खाते. बीते एक अप्रैल को उन्होंने अपने आवास पर आयोजित सरहुल मिलन समारोह में कहा कि झारखंड में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां बिहार-उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं, बल्कि झारखंडवासियों को ही मिलेंगी. पूर्व में नियुक्तियों में कुछ त्रुटियां रह गई थीं, जिन्हें वह मिलकर दूर कर रहे हैं.

इसके लिए सरकार स्थानीयता नीति बना रही है. उन्होंने कहा कि स्थानीयता नीति तय करने में राजनीति नहीं होगी, बल्कि लोगों से विचार-विमर्श करके नीति बनाई जाएगी. इसके लिए वह सर्वदलीय विमर्श करेंगे. आदिवासी संगठनों, राजनीतिक दलों एवं अनुसूचित जाति मोर्चा के लोगों से भी राय लेंगे. लेकिन, झारखंड नामधारी पार्टियों के तेवर देखकर तो यही लगता है कि राजनीति स्थानीयता के झूले पर ही झूलती रहने वाली है. पृथक झारखंड राज्य के लिए आंदोलन की अगुवाई करने वाले पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने एक बार फिर आर-पार की लड़ाई का ऐलान किया है. झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तो अघोषित तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को आंदोलन के लिए तैयार रहने का संदेश तक भिजवा दिया है.■

feedback@chauthiduniya.com

लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी

फर्जीवाड़े का ज़िम्मेदार कौन

राजकुमार शर्मा

प्रशासनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी इन दिनों बदनामी का शिकार है. एकेडमी के दागी अफसर अपने गोरखधंधों से इस चर्चित संस्थान के चेहरे पर कालिख उड़ेल रहे हैं. फर्जी आईएएस अफसर रूबी चौधरी का ताजा मामला सबके सामने है. संस्थान के उपनिदेशक सौरभ जैन पर आरोपों की झड़ी लगाने वाली रूबी गिरफ्तारी के पहले ही दिन अपने बयान से पलट गई. गिरफ्तारी से पहले मीडिया से बेझिझक मिलने वाली रूबी अब खामोशी है. रूबी का अपने बयान से पलटना काफी अहम माना जा रहा है. रूबी अब पूरे मामले के लिए खुद को ज़िम्मेदार ठहरा रही है. रूबी के अनुसार, उसे आईएएस अफसर बनने का शौक था, इसलिए वह संस्थान गई थी. उसने खुद फर्जीवाड़ा किया और दूसरों के समक्ष खुद को अफसर के रूप में पेश किया. अदालत में बहस के दौरान बचाव पक्ष के वकील मार्कंडेय पंत ने पुलिस के आरोप को सरकार की तरफ़ से लगाया गया झूठ का पुलिंदा बताया. उन्होंने रूबी पर लगाई गई धारा पर आपत्ति करते हुए कहा कि पुलिस ने रूबी पर खुद को फर्जी तरीके से एसडीएम के रूप में पेश करने का आरोप लगाया, जो सरासर झूठ है. पंत का कहना था कि अधिकारियों ने पुलिस पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए रूबी की ज़ुबान बंद करने के लिए यह मुकदमा दर्ज कराया. जब रूबी ने अपने साथ हुए अन्याय के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रार्थना-पत्र लिखा, तो पुलिस ने उसे लेने से इंकार कर दिया. बचाव पक्ष के वकील ने रूबी द्वारा लगाए गए आरोपों को गंभीर बताया.

वकील के अनुसार, ऐसी रिपोर्ट मिली है कि उनकी मुवक्किल को नौकरी का झांसा देकर छह माह से अधिक समय से संस्थान परिसर में रखा गया था. इसके बावजूद उसे गिरफ्तारी के बाद नैसर्गिक न्याय से दूर रखा गया है. वहीं सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि यह देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है. संस्थान की तरफ़ से मिली तहरीर के तुरंत बाद इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया. मुकदमा दर्ज होते ही एसआईटी का गठन किया गया. इसके बाद पुलिस ने जब सुबूत जुटाने शुरू किए, तो कई गंभीर तथ्य प्रकाश में आए. पुलिस को मौक़े से कई दस्तावेज़ी सुबूत मिले. आरोपी महिला के पास से फर्जी आईकार्ड भी मिला. संस्थान के अंदर कई ऐसी फोटो मिलीं, जिनसे महिला की गतिविधियों का पता चलता है. इतना बड़ा बवाल होने के बावजूद एलबीएस प्रबंधन इस मामले में मीडिया कवरेज से नाराज़ है. यही नाराज़गी रूबी चौधरी की है. दोनों पक्ष मीडिया में अपने ख़िलाफ़ आई ख़बरों से इंकार कर रहे हैं. दिन में जहां रूबी खुले आम घूमकर पुलिस को बयान देने के लिए बुला रही थी, वहीं रात में उसकी गिरफ्तारी हो गई. यानी दिन में रूबी की स्थिति को लेकर पुलिस का रुख स्पष्ट नहीं था. जब उसने दिन में पत्रकारों को अपना बयान दिया, तो एलबीएस प्रबंधन घबरा गया और तुरंत पुलिस को उसकी गिरफ्तारी के संकेत दिए गए. गिरफ्तारी के बाद जब रूबी को दून महिला अस्पताल में लाया गया, तो पुलिस ने उसे पत्रकारों से बात नहीं करने दी. राज्य युवा कल्याण परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष रवींद्र जुगरान के अनुसार, इस मामले में संस्थान के अधिकारियों की मिलीभगत है. आरोपी महिला रूबी चौधरी ने संस्थान के उपनिदेशक सौरभ जैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, वह वहां छह माह से संस्थान के अंदर रह रही थी. लिहाजा, पूरे मामले की सीबीआई जांच ज़रूरी है.

उत्तराखंड

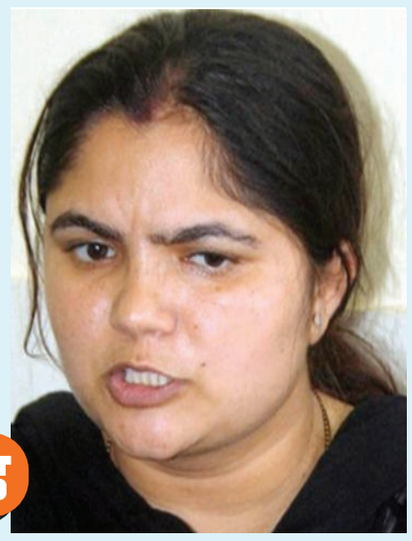

रूबी अब पूरे मामले के लिए खुद को ज़िम्मेदार ठहरा रही है. रूबी के अनुसार, उसे आईएएस अफसर बनने का शौक था, इसलिए वह संस्थान गई थी. उसने खुद फर्जीवाड़ा किया और दूसरों के समक्ष खुद को अफसर के रूप में पेश किया. अदालत में बहस के दौरान बचाव पक्ष के वकील मार्कंडेय पंत ने पुलिस के आरोप को सरकार की तरफ़ से लगाया गया झूठ का पुलिंदा बताया. उन्होंने रूबी पर लगाई गई धारा पर आपत्ति करते हुए कहा कि पुलिस ने रूबी पर खुद को फर्जी तरीके से एसडीएम के रूप में पेश करने का आरोप लगाया, जो सरासर झूठ है.

मामला प्रकाश में आने के बाद एलबीएस प्रबंधन ने सुरक्षा गार्ड देव सिंह को निलंबित कर दिया गया. पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बाद अदालत के समक्ष पेश किया. सवाल यह है कि एलबीएस एकेडमी में इतना कुछ चल रहा था और निदेशक राजीव कपूर को भनक कैसे नहीं लगी? छह माह तक रूबी अकादमी में बेरोकटोक रही, कई बार अंदर-बाहर आई-गई. यही नहीं, उसने साफ़ कहा कि सौरभ जैन ने नौकरी दिलाने के नाम पर उससे पांच लाख रुपये लिए और संस्थान में प्रवेश दिलवाया. रूबी के अनुसार, सौरभ जैन ने कहा था कि इसके लिए उन्होंने निदेशक राजीव कपूर से भी बात की है. हैरानी की बात यह है कि जब मामला खुला, तो निदेशक कपूर बोले कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी. सूत्रों के अनुसार, एकेडमी के प्रशासन से लेकर हर कामकाज निदेशक की अनुमति से चलता है. बिना उनकी अनुमति के किसी शख्स को अंदर आने नहीं दिया जाता. एकेडमी में जो अच्छा-बुरा या नया-पुराना होता है, उसकी पल-पल की जानकारी निदेशक तक पहुंचती है. कहीं भी कोई गड़बड़ होती है, तो निदेशक को तुरंत बताया जाता है. ऐसे में हैरानी की बात यह है कि रूबी छह माह तक एकेडमी में अनाधिकृत रूप से रही, खुलेआम घूमी, फोटो खिंचवाए और उसकी भनक निदेशक को नहीं लगी! यह कहीं न कहीं एकेडमी और निदेशक के मैनेजमेंट पर एक बड़ा सवाल है. देव सिंह की गिरफ्तारी के बाद एलबीएस एकेडमी के कर्मचारियों में भी आक्रोश दिख रहा है. कोई खुलकर बोलने की हिम्मत भले नहीं जुटा पा रहा हो, लेकिन अंदरखाने इस बात का मलाल हर किसी को है कि बड़ी मछली को बचाने के लिए छोटों को दबोचने का काम किया जा रहा है. देव सिंह पुत्र कुंवर सिंह अल्मोड़ा के भिकिया सैण ब्लाक के जमोली गांव का मूल निवासी है. वह अपने चाचा के सहयोग से अकादमी में नौकरी पर लगा और परिवार के साथ रहता था. मामला प्रकाश में आते ही आनन-फानन में पहले उसे निलंबित किया, घटना के तूल पकड़ते ही नजरबंद कर दिया गया और फिर पुलिस उठा ले गई.■

मदद के लिए आते हैं फोन कॉल्स तो

कफनचोर एनजीओ से रहें सावधान

नवजात की धड़कनें हमेशा के लिए खामोश हो गई हों, लेकिन एक कफनचोर एनजीओ उस बच्ची के इलाज के नाम पर आज भी चंदे की उगाही कर रहा हो, तो उसे आप क्या नाम देंगे? जी हां, जब हमने उस मृत बच्ची के मामा से इस मामले की पूरी जानकारी ली, तो यह सुनकर पहले तो वह आवाक रह गया. उसका कहना था कि वह एनजीओ संचालक विशाल को बच्ची की मौत की सूचना पहले ही दे चुका है. खुद को सामाजिक सरोकारों का सबसे बड़ा ठेकेदार समझने वाले ऐसे एनजीओ में से कफनचोर एनजीओ कितने हैं, जो किसी के इलाज के बहाने उसकी मौत पर चंदा उगाही जैसे जघन्य कृत्य कर रहे हैं? भारत में स्थित लगभग 20 लाख एनजीओ को प्रति वर्ष लगभग 950 करोड़ रुपये का डोनेशन देनेवाली केंद्र और राज्य सरकारों के पास क्या इस सवाल का जवाब है?

अरुण तिवारी

सर तीन महीने की बच्ची है कनिका. हापुड़ के छपकौली की रहने वाली है. उसके मां-बाप बहुत ही गरीब हैं सर. वे बहुत ही मजबूर हैं. पैसे का इंतजाम नहीं कर सकते. बच्ची मर जाएगी, क्योंकि उसके मां-बाप पैसा नहीं जुटा पाएंगे. बच्ची के दिल में छेद है और उसका इलाज एम्स में चल रहा है. आप उस बच्ची की मदद कीजिए सर. हम प्रगति फाउंडेशन से बोल रहे हैं. कुल 55 हजार रुपयों की जरूरत है. हमने लगभग 40 हजार रुपये जुटा लिए हैं. जितना जल्द हो सके, उस बच्ची की मदद के लिए पैसों की व्यवस्था करवाइए सर.

इसी फोन कॉल ने नोएडा के एक प्रगति फाउंडेशन के पूरे फर्जीवाड़े की पोल खोल कर रख दी. जरा सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसी कॉल आए कि किसी तीन महीने की बच्ची के दिल में छेद है और उसके ऑपरेशन के लिए पैसों की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से आप उस बच्ची की मदद के लिए यथासंभव पैसे देने का प्रयास करेंगे. अब अगर पैसे देने के बाद आपको यह पता चले कि जिस बच्ची की जान बचाने के लिए आपने पैसे दिए, उसकी धड़कनें तो काफी पहले ही खामोश हो चुकी हैं, तो बच्ची की मौत पर पैसे की उगाही करने वाली उस संस्था के प्रति आपकी प्रतिक्रिया कैसी होगी?

कुछ इसी तरह मानवता को शर्मशार कर रहा है नोएडा का एक एनजीओ-प्रगति फाउंडेशन. इस एनजीओ का कार्यालय नोएडा के सेक्टर 15 में स्थित है. इस एनजीओ का मालिक विशाल अरोड़ा है. यह एनजीओ कनिका नाम की मरहूम बच्ची के नाम पर लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहा है. हमारे पास भी इस एनजीओ के एक कर्मचारी की तरफ से बीते 3 अप्रैल को

कॉल आई कि कनिका का ऑपरेशन होना है और कुल 55 हजार रुपये की जरूरत है. हमने लगभग 40 हजार रुपये जमा कर लिए हैं. 15 हजार रुपये और चाहिए. हमने उस कर्मचारी से मदद का वादा किया और कहा कि आप बच्ची के इलाज से संबंधित कुछ जानकारी हमारी ईमेल आईडी पर भेज दीजिए. पहले तो हमारे दिमाग में यही बात आई कि अपने कार्यालय के सभी कर्मचारियों से पैसे इकट्ठा करके बच्ची के ऑपरेशन के लिए दे दिए जाएं. एनजीओ की तरफ से हमें इसकी जानकारी भेज दी गई. उस मेल में एक पीडीएफ था, जिसमें भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स, नई दिल्ली) के हृदय विभाग का ओपीडी पर्चा भी शामिल था. उस पर्चे से बच्ची के ऑपरेशन की बात की तस्दीक हुई. उस पीडीएफ में इस बात की भी जानकारी दी गई थी कि ऑपरेशन में कुल 55,000 रुपये की राशि ली जाएगी. उस मेल को पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में यह बात आई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह एनजीओ कोई फर्जीवाड़ा कर रहा है, क्योंकि बीते एक साल के दौरान ऐसे कई एनजीओ सामने आए हैं, जो लोगों की जिंदगी बचाने की दुहाई देकर अनाप-शनाप धन की उगाही करते हैं. ऐसे एनजीओ का भंड़ाफोड़ भी हुआ है. शक के आधार पर हमने एक बार फिर उस प्रगति फाउंडेशन को फोन किया और लड़की के किसी अभिभावक से बात कराने की बात कही, लेकिन एनजीओ की तरफ से यह कहते हुए इंकार कर दिया गया कि उनके पास किसी अभिभावक का मोबाइल नंबर नहीं है. हमने एक बार फिर एम्स के पर्चे को ध्यान से देखा, तो उसमें हमें बच्ची के एक अभिभावक का मोबाइल नंबर लिखा मिला. हमने उस नंबर पर फोन किया, तो जानकारी मिली कि यह कनिका के मामा कपिल का नंबर था. कपिल ने हमसे पूछा कि क्या आप नोएडा के किसी एनजीओ से फोन कर रहे हैं, तो हमने उसे पूरी बात बताई और यह भी बताया कि हम मीडिया से हैं. कपिल ने एनजीओ की इस करतूत पर हैरानी जताई. जब कपिल ने हमें बीती 12 फरवरी को कनिका की मौत के बारे में बताया, तो हम सन्न रह गए. मतलब, कनिका की मौत चंदे के लिए की गई कॉल से लगभग दो महीने पहले ही हो चुकी थी. हमने कपिल से पूछा कि क्या आपने कनिका की मौत की जानकारी एनजीओ वालों को दी थी, तो उसने बताया कि बच्ची की मौत के कुछ ही दिनों बाद उसने फोन करके प्रगति फाउंडेशन (एनजीओ) के संचालक विशाल अरोड़ा को इसकी जानकारी दे दी थी.

आइए, आपको इस स्टोरी के दूसरे पक्ष की जानकारी देते हैं. इस पूरी तफ्तीश के दौरान हम लगातार एनजीओ वालों के संपर्क में भी बने हुए थे और हमने उन्हें इस बात का भरोसा भी दिया कि उनकी पूरी मदद की जाएगी. प्रगति फाउंडेशन की तरफ से हमें निशांत नाम के एक कर्मचारी का लगातार फोन आता रहता था. दिन में उसके कई-कई फोन आते थे. सारी कॉल का एक ही मकसद कि अधिक से अधिक पैसे की उगाही कैसे की जाए. हमने अपनी तफ्तीश को और मजबूत करने के लिए 6 अप्रैल को एनजीओ वालों से कहा कि आप किसी आदमी को भेज दीजिए, जिसे हम पैसे दे देंगे. एनजीओ की तरफ से अभिनीत नाम का एक व्यक्ति आया. हमने उसे 100 रुपये दिए और उससे उस पैसे की रसीद ले ली. इस रसीद पर एनजीओ के डिटेल्स थे. अभिनीत जैसे ही वापस लौटा, हमारे पास तुरंत ही एनजीओ से फोन आया कि सर, आपने तो सिर्फ 100 रुपये ही दिए. हमने उनसे कहा कि हम यह तस्दीक करना चाहते थे कि पैसे सही जगह पहुंच रहे हैं या नहीं. जब हमने निशांत से विशाल अरोड़ा का नंबर मांगा, तो हमें उनका नंबर भी मिल गया. हमने विशाल अरोड़ा से भी बात की, तो उन्होंने बताया कि बच्ची की मदद के लिए वह प्रयासरत हैं. हमारे पास विशाल अरोड़ा से हुई बातचीत की पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है.

सवाल यह उठता है कि एक बच्ची, जिसकी जिंदगी बचाने के नाम पर आप चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बारे में आपको यह तक जानकारी नहीं है कि वह बच्ची जीवित है अथवा नहीं, तो आपकी नीयत पर संदेह तो पैदा करता ही है. आखिर आप पैसा किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं? इसमें एनजीओ यह भी जवाब दे सकता है कि हमें इसकी जानकारी नहीं थी? इसी के लिए हमने उस बच्ची के मामा से इसकी पूरी जानकारी ली. उसने हमें बताया कि मैं विशाल को इस बात की जानकारी दे चुका हूं, तो क्या यह चंदेबाजी सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए की जा रही है या फिर इसके पीछे कोई और खेल भी मौजूद है. आखिर किसी आदमी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का हक इन एनजीओ वालों को किसने दिया है? कहां है सरकार और उसकी मशीनरी? ऐसे बेलगाम एनजीओ पर जल्द ही सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो असहाय और जरूरतमंदों पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा और जिस दिन ऐसा होगा, समझिए उस दिन होठों को कर के गोल कोई ऑल इज वेल नहीं कहेगा, बल्कि उसके लिए वह दिन अंत का आरंभ होगा.■

feedback@chauthiduniya.com

गैर सरकारी संगठनों से जुड़े फर्जीवाड़े के कुछ अन्य मामले

बहुत दिन नहीं हुए, जब क्राइम ब्रांच ने पीएमओ के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहे ग्लोबल नीड फाउंडेशन नामक एनजीओ के फाउंडर को गिरफ्तार किया था. आरोपी की पहचान यशपाल सिंह तोमर (50) के रूप में हुई थी. कबूल नगर शाहदरा स्थित अपने घर पर लगी फैक्स मशीन में छेड़छाड़ कर उसने ऐसी सेटिंग की हुई थी कि जिस कंपनी में फैक्स भेजा जाता था, उन्हें ऐसा लगे कि यह फैक्स पीएमओ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऑफिस से ही भेजा गया है.

बिहार के छपरा में भी ऐसी एक घटना सामने आई थी, जिसमें महादलित बस्तियों में अल्पव्ययी शौचालय निर्माण में भारी फर्जीवाड़े की खबर आई थी. इसमें एक समाचार पत्र के लगातार सक्रिय रहने के बाद आखिरकार विभाग के पदाधिकारी सक्रिय हुए थे. जल एवं स्वच्छता समिति प्रकल्प के अध्यक्ष व सारण डीडीसी सुशील कुमार के आदेश पर पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता चंदेश्वर राम ने एनजीओ के सचिव दशरथ राय एवं पीएचईडी विभाग के तरैया कनीय अभियंता शालीग्राम सिंह के विरुद्ध इसुआपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. इसके अलावा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधनी में दो अलग एनजीओ चलाकर फर्जीवाड़ा करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को मामले की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन विभाग को निर्देश दिया है कि वह आवेदक की याचिका पर कार्रवाई कर इसकी जानकारी आठ सप्ताह के भीतर युगलपीठ को दे.

केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी के एनजीओ का मामला भी सामने आया था, जिसके बाद मध्यप्रदेश सरकार ने भी विकलांगों को कृत्रिम अंगों के वितरण को लेकर संबंधित विभाग से जानकारी एकत्रित करने को कहा था. सरकारी योजनाओं में फर्जीवाड़े व घोटाले के लिए चर्चित पश्चिमी सिंहभूम में संपूर्ण स्वच्छता मिशन के अंतर्गत बीपीएल-एपीएल के लिए बने शौचालयों में बड़ी गड़बड़ी सामने आई थी. कागजों में ही शौचालयों को पूर्ण दिखाकर न सिर्फ संबंधित एनजीओ ने सारी राशि उठा ली, बल्कि केंद्र सरकार से निर्मल ग्राम पुरस्कार भी झटक लिया. जिन गांवों को निर्मल ग्राम घोषित किया गया है, वहां शौचालय पूरे हुए ही नहीं. जहां हुए भी, वहां उनका होना न होना बराबर है. इस तथ्य का खुलासा होने के बाद पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने निर्मल ग्राम पुरस्कार के तहत मिलने वाली राशि पर रोक लगा दी है.

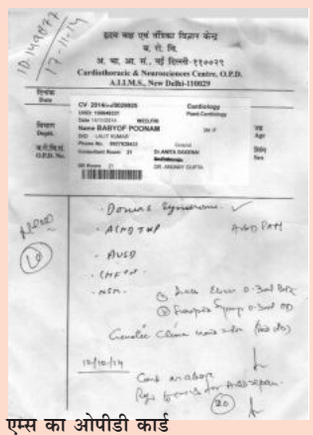
एम्स का ओपीडी कार्ड

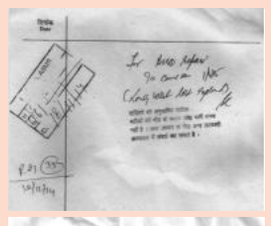

एनजीओ द्वारा दी गई रसीद

मेरी भांजी की मृत्यु 12 फरवरी को ही हो गई थी. हमने प्रगति फाउंडेशन से मदद की गुहार की थी, लेकिन अपनी भांजी की मौत के बाद हमने इसकी जानकारी विशाल अरोड़ा को दे दी थी. यह बात हमारी समझ से परे है कि उसकी मौत के बाद भी एनजीओ आखिर क्यों लोगों को फोन कर चंदे की मांग कर रहा है. यह बिल्कुल गलत है. अब, जब हमारी बच्ची ही जीवित नहीं रही, तो पैसे लेकर आखिर हम क्या करेंगे?

- कपिल कुमार (कनिका के मामा)

हमें इसकी जानकारी नहीं थी. आपके द्वारा बताए जाने पर ही हम यह जान पाए कि वह बच्ची मर चुकी है. हमलोगों ने यह सबकुछ जान-बूझकर नहीं किया है.

- विशाल अरोड़ा (संचालक, प्रगति फाउंडेशन)

(विशाल अरोड़ा के इस बयान से इस बात की पुष्टि होती है कि उनके एनजीओ को इस बात की चिंता थी ही नहीं कि कनिका जिंदा है या नहीं. उन्हें तो सिर्फ इस बात की चिंता थी कि पैसे की उगाही अधिक से अधिक कैसे की जाए. इस पूरे घटनाक्रम के दौरान उन्होंने यही जिक्र किया कि कनिका जिंदा है. जब अपनी तफ्तीश के आखिरी दिन हमने उन्हें यह बताया कि उनका एनजीओ झूठा बयान दे रहा है, तो उन्होंने अपना बयान बदल दिया और कहा कि उन्हें इसके बारे में नहीं पता था. यह बात हैरान कर देने वाली थी).

मध्य प्रदेश के सीधी ज़िले में भूमि अधिग्रहण के ख़िलाफ़ लंबे समय से सक्रिय उमेश तिवारी ने कहते हैं, हमें जब कभी देश भर में भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के संबंध में नीतिगत विचार–विमर्श के लिए बुलाया जाता है, तो हम वहां पहुंचते हैं. वहां जो भी निर्णय होते हैं, उन पर हम लौटते ही काम करना शुरू कर देते हैं. लेकिन, अचानक उन कार्यक्रमों एवं योजनाओं में बदलाव हो जाता है. उदाहरण के लिए, हम भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन की योजनाओं के संबंध में वर्धा गए. वहां से अन्ना हजारे के नेतृत्व में पीवी राजगोपाल की एकता परिषद की पदयात्रा शुरू हुई, लेकिन अन्ना जी ने बीच में वह यात्रा स्थगित कर दी. ऐसी स्थिति में समझ में नहीं आता है कि कार्यक्रम अथवा योजना स्थगित करने के निर्णय अचानक कैसे ले लिए जाते हैं?

फोटोः सुनील मल्होत्रा

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश विरोधी आंदोलन

बेहतर नेतृत्व और संवाद की ज़रूरत

नवीन चौहान

नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के विरोध के संदर्भ में बीते दो अप्रैल को दिल्ली के कंस्टीट्यूशन क्लब में जनसंगठनों और विभिन्न राजनीतिक दलों की एक बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि देश में हर स्तर पर सभी संगठन मिलकर विरोध प्रदर्शन करेंगे. बैठक ख़त्म होने के अगले ही दिन सरकार एक बार फिर भूमि अधिग्रहण अध्यादेश ले आई. बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया था कि यदि सरकार दोबारा अध्यादेश लेकर आती है, तो छह अप्रैल को देश भर में अध्यादेश की प्रतियां जलाकर सांकेतिक तौर पर विरोध किया जाएगा. दिल्ली के जंतर–मंतर पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नए अध्यादेश की प्रतियां जलाई गईं, जिसमें तक़रीबन 40–50 लोगों ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम में जनसंगठनों और वामदलों के कार्यकर्ता तो मौजूद थे, लेकिन उन अन्य राजनीतिक दलों के नुमाइंदे या कार्यकर्ता नज़र नहीं आए, जिन्होंने दो अप्रैल की बैठक में क़दम से कदम मिलाकर चलने का वादा किया था.

उदाहरण के लिए, जनता दल (यू) का कार्यालय जंतर–मंतर पर ही है. पार्टी कार्यालय के ठीक सामने अध्यादेश की प्रतियां जलाने का कार्यक्रम हुआ, लेकिन जद (यू) का कोई नुमाइंदा वहां मौजूद नहीं था. कंस्टीट्यूशन क्लब में जनसंगठनों के साथ संवाद कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद केसी त्यागी ने कहा था कि उनकी पार्टी संसद से सड़क तक भूमि अधिग्रहण के मसले पर आंदोलनकारियों के साथ है, लेकिन उनके अपनी पार्टी के ऐसे किसी भी कार्यक्रम में शिरकत करने की कहीं से कोई ख़बर नहीं आई. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किसान मोर्चा ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का विरोध किया. बड़ी संख्या में किसानों ने हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर एकत्र होकर केंद्र सरकार द्वारा लागू भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया और उसे वापस लेने की मांग की. इसी तरह लखीमपुर खीरी एवं बनारस में विरोध प्रदर्शन आयोजित हुए. मध्य प्रदेश के सीधी, मझौली, सिंगरौली, ग्वालियर एवं छिंदवाड़ा में जगह–जगह प्रदर्शन हुए. राजस्थान के भीलवाड़ा में राजस्थान किसान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मौन जुलूस निकाला और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा.

दरअसल, लीडरशिप इस आंदोलन में सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है. मध्य प्रदेश के सीधी ज़िले में भूमि अधिग्रहण के ख़िलाफ़ लंबे समय से सक्रिय उमेश तिवारी ने कहते हैं, हमें जब कभी देश भर में भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के संबंध में नीतिगत विचार–विमर्श के लिए बुलाया जाता है, तो हम वहां पहुंचते हैं. वहां जो भी निर्णय होते हैं, उन पर हम लौटते ही काम करना शुरू कर देते हैं. लेकिन, अचानक उन कार्यक्रमों एवं योजनाओं में बदलाव हो जाता है. उदाहरण के लिए, हम भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन की योजनाओं के संबंध में वर्धा गए. वहां से अन्ना हजारे के नेतृत्व में पीवी राजगोपाल की एकता परिषद की पदयात्रा शुरू हुई, लेकिन अन्ना जी ने बीच में वह यात्रा स्थगित कर दी. ऐसी स्थिति में समझ में नहीं आता है कि कार्यक्रम अथवा योजना स्थगित करने के निर्णय अचानक कैसे ले लिए जाते हैं? ऐसे में किसानों और आंदोलन से जुड़े लोगों के बीच ग़लत संदेश जाता है.

ग़ौरतलब है कि अन्ना हजारे को जंतर–मंतर पर 23–24 फरवरी को हुए आंदोलन का चेहरा बनाया गया था. वर्धा तक अन्ना हजारे उससे जुड़े रहे, लेकिन राजनीतिक दलों के साथ हुए संवाद के कार्यक्रम का वह (अन्ना) हिस्सा नहीं थे. अन्ना के संबंध में जब मेधा पाटकर से पूछा गया, तो उन्होंने कोई साफ़–साफ़ जवाब नहीं दिया. गोविंदाचार्य के भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन से जुड़ने की वजह से ही अन्ना के साथ अन्य राजनीतिक दल काम नहीं करना चाहते हैं. कंस्टीट्यूशन क्लब में भी इस आंदोलन को सेक्युलर बनाए रखने की बात भी कई बार कही गई थी. यदि अन्ना इस आंदोलन से अब भी जुड़े होते, तो छह अप्रैल को अध्यादेश की प्रतियां जलाकर विरोध करने का कार्यक्रम रालेगण सिद्धी में भी आयोजित होता, लेकिन ऐसी कोई सूचना नहीं आई. यही नहीं, दो अप्रैल को ही अन्ना समर्थकों की एक बैठक दिल्ली के आईटीओ स्थित एनडी तिवारी भवन में आयोजित न हुई होती, जिसे अन्ना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये संबोधित किया था.

दूसरी बात यह है कि आंदोलन से संबद्ध सभी संगठनों के बीच घोर संवादहीनता (कम्युनिकेशन गैप) है. कोई भी संदेश लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है. देश भर में जिन जगहों पर भी अध्यादेश की प्रतियां जलाने के कार्यक्रम आयोजित हुए, वहां किसान नदारद रहे. ऐसे में आशंका पैदा होती है और सवाल भी उठता है कि जिन लोगों के नेतृत्व में भूमि अधिग्रहण विरोधी लड़ाई लड़ी जा रही है, उनकी पहुंच किसानों तक है या नहीं? किसान भी प्रकृति की मार से परेशान हैं. उनके सामने फिलहाल बारिश और ओले की वजह से हुए नुक़सान की चिंता ज़्यादा है. उनके पास इसके अलावा फिलहाल किसी और बारे में सोचने का न तो समय है और न वे किसी आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं. और, जब तक किसान सीधे तौर पर इस आंदोलन से नहीं जुड़ेगा, तब तक इसमें तेजी नहीं आएगी और न सरकार अपने क़दम पीछे खीचेंगी. इसके लिए किसानों एवं जनसंगठनों को अपनी पहचान और अपनी पसंद–नापसंदगी से आगे बढ़कर ईमानदारी से एक साथ आवाज़ उठानी होगी. यदि ऐसा नहीं हुआ, तो सांप निकल जाएगा और किसान लकीर पीटते रह जाएंगे.

वाम मोर्चा ने कसी कमर

मोदी सरकार के नए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश और आलू किसानों की मौत पर ममता सरकार के ख़िलाफ़ वाम मोर्चा ने सात अप्रैल को कोलकाता में महाजुलूस निकाला. वाम मोर्चा के चेयरमैन विमान बोस के नेतृत्व में महाजाति सदन से शुरू हुए इस महाजुलूस में माकपा, भाकपा, आरएसपी, सीपीआई एवं फॉरवर्ड ब्लॉक के सहित सभी घटक दलों ने हिस्सा लिया. वाम मोर्चा नेताओं ने कहा कि सरकार ने पहले तो लोकसभा में ग़लत तरीके से भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल पास कराया और उसके बाद वह दोबारा अध्यादेश लेकर आई. उन्होंने सोनिया गांधी के नेतृत्व में चल रहे भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन का भी समर्थन किया.

सड़क पर उतरीं ममता

नए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के ख़िलाफ़ तृणमूल कांग्रेस ने अपनी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में आठ अप्रैल को कोलकाता के मौलाली मोड़ से गांधी मूर्ति तक जुलूस निकाला. कोलकाता नगर निगम और प्रदेश में निकाय चुनाव से ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस की इस धिक्कार रैली को निगम चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है. सिंगुर में टाटा के लिए हुए भूमि अधिग्रहण के ख़िलाफ़ आंदोलन करके ही ममता बनर्जी राज्य की सत्ता पर काबिज हुई थीं. इसलिए वह इस मुद्दे को किसी भी क़ीमत पर नहीं छोड़ना चाहती हैं. तृणमूल कांग्रेस के सांसद पहले ही संसद में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का विरोध करते रहे हैं. रैली में शामिल हुए लोगों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया. रैली से ठीक पहले राज्य के शिक्षा मंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव पार्थ चटर्जी ने मीडिया को बताया कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को उनकी पार्टी स्वीकार नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि जैसे ही अध्यादेश के ख़िलाफ़ ममता बनर्जी के नेतृत्व में सड़क पर उतरने का ऐलान किया गया, पार्टी मुख्यालय में सीबीआई का फोन आ गया. लेकिन, सीबीआई के नाम पर हमें डराया नहीं जा सकता.

दरअसल, पश्चिम बंगाल में आलू की बंपर पैदावार हुई है, लेकिन उसका सही दाम न मिलने की वजह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं. जबकि प्रदेश सरकार इसे सही कारण नहीं मानती. किसानों के हितों की बात करने वाली तृणमूल कांग्रेस भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रही है, लेकिन आलू किसानों पर लाठीचार्ज करा रही है. पिछले महीने से लेकर अब तक प्रदेश के 10 से ज़्यादा किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने की ख़बरें आ चुकी हैं. ममता बनर्जी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार न तो अच्छी है और न विश्वसनीय. सरकार को भूमि अधिग्रहण अध्यादेश वापस लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि कोई केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है, तो उसकी आवाज़ दबा दी जाती है. उसे सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और एनआईए द्वारा धमकियां दी जाती हैं. पिछली बार जब केंद्र सरकार अध्यादेश लाई थी, तब ममता बनर्जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में परिस्थितियां आपातकाल से भी बदतर हैं. उनकी सरकार किसी भी स्थिति में यह अध्यादेश अपने राज्य में लागू नहीं करेंगी. अध्यादेश को उन्होंने काला क़ानून और किसानों के साथ अन्याय बताते हुए इसका विरोध करने की बात कही थी.■

navinonline2003@gmail.com

आंदोलन किसी पार्टी के विरोध में नहीं: अन्ना

समाजसेवी अन्ना हजारे ने सात अप्रैल को ब्लॉग लिखकर बताया कि उनका भूमि अधिग्रहण बिल आंदोलन किसी पार्टी या पक्ष के विरोध में नहीं है. यह आंदोलन व्यवस्था परिवर्तन और किसानों की भलाई के लिए है. उन्होंने लिखा कि प्रकृति और मानवता का दोहन (शोषण) करके किया गया विकास शाश्वत विकास नहीं होगा. ऐसे विकास से कभी न कभी विनाश होगा. सरकार भूमि अधिग्रहण क़ानून बदल कर किसानों की ज़मीन बड़े पैमाने पर लेकर उस पर उद्योग लगाने की सोच रही है. ऐसा समझ में आया है कि 63,974 किलोमीटर रेलवे लाइन के दोनों तरफ़ की एक-एक किलोमीटर ज़मीन, 92,851 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ़ एक-एक किलोमीटर ज़मीन और 1,31,899 किलोमीटर लंबे राज्य महामार्गों के किनारे की ज़मीन अधिग्रहीत करके उन पर औद्योगिक कॉरिडोर बनाने की बात सरकार सोच रही है.

अन्ना ने कहा कि सरकार देश में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार न करे, ऐसा हम नहीं चाहते हैं, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र बढ़ाने से ही देश का सही विकास होगा, यह सोच ठीक नहीं है. सरकार को औद्योगिक और कृषि क्षेत्र के बीच संतुलन रखना चाहिए. जितना औद्योगिक क्षेत्र पर पैसा खर्च होता है, उतना ही कृषि क्षेत्र पर भी खर्च किया जाना चाहिए. रोज़गार सृजन के लिए प्रकृति के दोहन की ज़रूरत नहीं. उन्होंने कहा कि 1500 लोगों के हाथों को काम देने के लिए कंपनी स्थापित करने में कृषि से कई गुना ज़्यादा खर्च आता है, प्रकृति का दोहन होता है और प्रदूषण भी बढ़ता है. सिर्फ़ उद्योगों से देश का भविष्य बदल जाएगा, यह सोच सही नहीं है.

उन्होंने कहा कि आज नहीं, लेकिन 50, 75, 100, 200 वर्षों के बाद औद्योगिकरण की वजह से समस्याएं बढ़ती जाएंगी. सौ-दो सौ वर्ष बाद उन समस्याओं का सामना हमारी आने वाली पीढ़ियों को करना होगा. इसलिए सरकार को सिर्फ़ पांच साल नहीं, पांच सौ साल के बारे में सोच रखकर औद्योगिक और कृषि क्षेत्र के लिए नीतियां बनानी चाहिए. आज़ादी के 68 वर्षों बाद हमारे देश में जितनी औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ोत्तरी हुई, उतना ही बेरोज़-गारी का प्रश्न छूटता चला गया. औद्योगिकरण से जो पर्यावरणीय ह्रास हो रहा है, उसकी भरपाई कौन और कैसे करेगा? आज़ादी के बाद औद्योगिक क्षेत्र में

फोटोः प्रभात पाण्डेय

जितना निवेश किया गया, यदि उतना पैदा कृषि क्षेत्र में लगता और पैदावार बढ़ाकर कृषि आधारित उद्योग लगते, तो बेरोज़गारी बहुत हद तक ख़त्म हो जाती तथा लोगों को अपने गांव में रोज़गार मिल जाता. यही नहीं, औद्योगिक क्षेत्र में रोज़गार से आज जो पैसा उन्हें मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा मिलता. आज जबकि देश के सामने भूमि अधिग्रहण जैसा महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा है, ऐसे में कांग्रेस और भाजपा एक-दूसरे के ख़िलाफ़ आरोप-प्रत्यारोप में समय बिता रहे हैं. इससे पता चलता है कि देश के नव-निर्माण से ज़्यादा उन्हें सत्ता की चिंता है. बकौल अन्ना, हमारे ऊपर भी कई बार आरोप-प्रत्यारोप लगते हैं कि हमारा आंदोलन सरकार के विरोध में, पक्ष-पार्टी के विरोध में है. हमने पहले भी कई बार कहा कि हम किसी भी पक्ष, पार्टी, व्यक्ति के विरोध में आंदोलन नहीं करते. यह व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन है. कृषि प्रधान भारत में किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके विरुद्ध यह आंदोलन है. किसानों की भलाई के लिए यह आंदोलन है. ग़लत निर्णयों के चलते देश उद्योगपतियों के कब्जे में न चला जाए, इसलिए यह आंदोलन है. मुझे किसी से कभी वोट नहीं मांगना और न किसी से कुछ लेना है. जीवन में सिर्फ़ सेवा करनी है. आज तक सेवा करता आया हूं और शरीर में जब तक प्राण हैं, तब तक करता रहूंगा.■

कमल मोरारका

पेड न्यूज चिंता का एक विषय है. यह है क्या? पेड न्यूज का मतलब है संपादक, रिपोर्टर या प्रकाशक द्वारा पैसा लेकर ख़बर छापना. शायद इससे उन्हें कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता. लेकिन, जैसे ही पेड न्यूज के रूप में कोई ग़लत ख़बर छपती है, नुक़सान हो चुका होता है. मीडिया की छवि ख़राब हुई है. वह यह नहीं कह सकता कि हम बहुत ही पवित्र हैं और हम आलोचना से परे हैं. दरअसल, देश में प्रेस और न्यायपालिका दो ऐसी संस्थाएं हैं, जिनमें सुधार की ज़रूरत है. कार्यपालिका और विधायिका सभी देशों में और ख़ासकर भारत में कभी भी सम्मानित नहीं रहीं.

मीडिया आलोचना से परे नहीं है

यह निराशाजनक है कि हमारा पूरा मीडिया कुछ-कुछ नकारात्मक मोड में है. ऐसा क्यों है, मैं नहीं समझ पा रहा. मैं समझ सकता हूं कि लोकतंत्र में हम सबके अलग-अलग विचार हो सकते हैं. कोई सरकार का समर्थन कर सकता है, कोई आलोचना कर सकता है, तो कोई किसी एक विशेष पार्टी का समर्थन कर सकता है. लोकतंत्र में यह सब स्वीकार्य है. लेकिन, जब राष्ट्रीय मुद्दों की बात आती है, तो फिर आलोचना में मतभेद नहीं होना चाहिए. नवीनतम मामला यमन से भारतीयों को सुरक्षित निकाल लाने का है. विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने बहुत ही साहसपूर्वक काम किया. खुद जिबूती में तैनात होकर और यमन के साना में रहने का साहस दिखाकर उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कितनी जल्दी और कैसे सुरक्षित रूप से हम भारतीयों को वहां से निकाल सकते हैं. और न सिर्फ़ भारतीयों, बल्कि अन्य देशों के लोगों की मदद करने में भी उन्होंने पर्याप्त उदारता दिखाई.

यह सब सरकार के लिए, विदेश मंत्रालय के लिए और देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में माना जाना चाहिए. बजाय इसके, हम पाते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, जो व्यक्तिगत रूप से जनरल वीके सिंह के ख़िलाफ़ हैं. और, सेना के कुछ भूतपूर्व जनरल, जो वीके सिंह के उम्र तिथि विवाद पर अपने स्टैंड की वजह से उन्हें नापसंद कर रहे हैं, ऐसे लोग यदि व्यक्तिगत रूप से नापसंदगी ज़ाहिर कर रहे हैं, तो ठीक है, लेकिन प्रेस को वस्तुनिष्ठ होना चाहिए. जब पूरा देश उनके अच्छे कामों की सराहना कर रहा है, तब आप उनकी आलोचना कैसे कर सकते हैं? मैंने इंटरनेट पर देखा है कि हर आदमी उनकी भरपूर प्रशंसा कर रहा है, उन्हें हीरो के तौर पर देखा जा रहा है. यहां हमने देखा कि जनरल वीके सिंह ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए प्रेसटीट्यूट्स शब्द का इस्तेमाल किया. इसका उच्चारण असल शब्द के क़रीब है. मैंने सोशल मीडिया पर आप समर्थकों को आपटार्ड कहते देखा है. जाहिर है कि यह टार्ड शब्द कहां से आया है? यदि आपटार्ड स्वीकार्य है, तो फिर प्रेसटीट्यूट क्यों नहीं? प्रेस शब्द उस वास्तविक शब्द के बहुत क़रीब है, लेकिन तथ्य यह है कि आप इसे लेकर सड़क पर नहीं उतर सकते. आपने दूसरों को गाली देने या आलोचना करने के लिए जो प्रतिमान स्थापित किए हैं, वैसे ही आपको भी अपनी आलोचना या गाली सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए. टाइम्स नाउ पर छह-सात पैनलिस्ट थे. इनमें से ज़्यादातर मीडियाकर्मी ही थे. उनकी बातों से लग रहा था कि आख़िर प्रेस को ऐसा क्यों बोला गया. मैं नहीं समझता कि प्रेस को आलोचना से अलग क्यों रखा जाना चाहिए.

मैं खुद जन्म से ही एक कॉरपोरेट घराने से आता हूं. शुरू से सुनता रहा हूं कि कॉरपोरेट घराने ब्लैक मनी, ब्लैक मार्केटिंग और टैक्स चोरी में शामिल होते हैं. लेकिन, मैं कभी इससे आहत नहीं हुआ, क्योंकि ये आरोप मेरे ऊपर लागू नहीं होते थे और इसलिए मैं आहत नहीं होता था. यह किसी ने किसी वजह से कहा होगा और हो सकता है कि इसमें कुछ सच्चाई भी हो. कुछ कॉरपोरेट घराने ऐसे हों, जो इन कामों में शामिल हों और इस वजह से उनकी छवि खराब हुई हो, लेकिन इससे मैं कभी आहत नहीं हुआ, क्योंकि मैं कभी ऐसे कामों में शामिल नहीं रहा. यहां मेरी समझ से बाहर है कि टाइम्स नाउ पर बहस में शामिल पैनलिस्ट ने जनरल वीके सिंह की आलोचना क्यों शुरू कर दी? ठीक है, एक मंत्री होने के नाते वह संयम बरतते हुए ऐसे शब्दों को टाल सकते थे, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कह भी दिया, तो इससे कोई आसमान नहीं टूट पड़ा. ऐसा नहीं है कि आज का प्रेस यह दावा कर सकता है कि वह रिश्वतखोरी नहीं करता, भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होता और उसकी आलोचना नहीं की जा सकती.

पेड न्यूज एक चिंता का विषय है. यह है क्या? पेड न्यूज का मतलब है संपादक, रिपोर्टर या प्रकाशक द्वारा पैसा लेकर ख़बर छापना. शायद इससे उन्हें कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता. लेकिन, जैसे ही पेड न्यूज के रूप में कोई ग़लत ख़बर छपती है, नुक़सान हो चुका होता है. मीडिया की छवि खराब हुई है. वह यह नहीं कह सकता कि हम बहुत ही पवित्र हैं और हम आलोचना से परे हैं. दरअसल, देश में प्रेस और न्यायपालिका दो ऐसी संस्थाएं हैं, जिनमें सुधार की ज़रूरत है. कार्यपालिका और विधायिका सभी देशों में और खासकर भारत में कभी भी सम्मानित नहीं रहीं. लेकिन प्रेस और न्यायपालिका, जिन पर अन्य संस्थाओं की निगरानी की ज़िम्मेदारी है, वे ही अब संदेह के घेरे में हैं. अगर न्यायपालिका अपनी बेहतर छवि पेश नहीं कर पा रही है और प्रेस एक शब्द से आहत हो जाता है, तो यह सब मेरी समझ से बाहर है.

तो क्या ये आलोचनाएं सही थीं, इसलिए यह सब हंगामा हो रहा था? मैं समझता हूं कि यही वक्त है कि यह सब ट्वीटिंग वगैरह रुकनी चाहिए. अपने काम पर ध्यान दीजिए. मैं समझता हूं कि जनरल वीके सिंह के नेतृत्व में हमारे प्रशासन और लोगों ने बेहतरीन काम किया है. मैं समझता हूं कि संयुक्त राष्ट्र भारत के इस काम के लिए एक धन्यवाद प्रस्ताव पास कर सकता है. और, एक हम हैं कि अपनी आदत के मुताबिक अपने ही अच्छे कामों की आलोचना कर रहे हैं और उसे कमतर आंक रहे हैं. मैं समझता हूं कि यह सब फौरन बंद होना चाहिए. व्यक्तिगत रूप से मैं कह सकता हूं कि जनरल वीके सिंह ने बहुत ही उल्लेखनीय काम किया है. कम से कम कैबिनेट को चाहिए कि वह एक धन्यवाद प्रस्ताव लाए और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उनके काम के लिए धन्यवाद दे. हर किसी के वश का नहीं है कि वह जिबूती या साना में रहकर इस तरह का काम कर सके. ज़ाहिर है, वह एक पूर्व आर्मी चीफ हैं और इसलिए उन्हें इसका लाभ मिला. लेकिन, प्रेस द्वारा इस तरह से चरित्र हनन करना ग़ैर-ज़िम्मेदाराना और ग़ैर-ज़रूरी है और वह भी उस एक शब्द के लिए, जिसे उन्होंने खुद नहीं गढ़ा है. बहुत सारे लोगों ने उनसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया है. यह एक वास्तविक शब्द नहीं है. उन्होंने सिर्फ़ इसका इस्तेमाल आहत होकर किया कि एक तो अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डालकर यह काम किया. बावजूद इसके, प्रेस उन पर अनाप-शनाप आरोप लगा रहा है.

दूसरी बात न्यायपालिका की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की. इसका औचित्य संदेह से परे नहीं है. प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में न्यायपालिका से कहा है कि वह उन पीआईएल को, जो उनके (मोदी) विकास की धारणा की राह में रुकावट हों, न सुने. कम से कम मैं देश के मुख्य न्यायाधीश श्री एचएल दत्तू से अपेक्षा रखता हूं कि वह ऐसी किसी पीआईएल की सुनवाई से खुद को अलग कर लेंगे. उन्होंने खुद यह स्वीकारा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हैं और यदि पीआईएल पर अलग तरीके से सुनवाई होने लगी, तो न्यायपालिका पर कई सारे सवाल खड़े होने लगेंगे.

मैं समझता हूं कि सरकार को अपना काम करने दें, यह पांच साल के लिए चुनी गई है. श्री मोदी को संविधान के दायरे में रहते हुए अपने तरीके से अपना काम करने का पूरा अधिकार है. लेकिन, न्यायपालिका और प्रेस नागरिकों के हितों की निगरानी करने वाली संस्थाएं हैं और लोहिया जी ने इसे चौखंभा राज कहा था. न्यायपालिका और प्रेस दो ऐसी संस्थाएं हैं, जो भारत में लोकतंत्र की गरिमा को बचाए रखती हैं. इस तरह की सुविधा मध्य-पूर्व या हमारे आस-पास के बहुत सारे देशों में नहीं है. ऐसा केवल विकसित पश्चिमी लोकतंत्र में है. हमारे पास कुछ है, इसे बचाना चाहिए, इसे मजबूत बनाना चाहिए. बाहरी शक्तियों के बजाय हम खुद ही इसे नष्ट कर दें, इससे बचना होगा. हम यह नुक़सान बिना किसी कारण कर रहे हैं. आशा है कि सद्बुद्धि आएगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

विक्रम मल्लाह और फूलन देवी-7

हथियार कहां से आते हैं

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

डकैती की योजना प्राय: गांव के किसी बड़े आदमी के यहां ही बनती है, जो खुले रूप में डकैतों में शामिल नहीं होता है. यह आदमी जगह-जगह लोगों को संकेत शब्दावली में सूचना देता है. जैसे आज पूजा होगी, गंगा स्नान के लिए चलना है आदि. इस शरीफ आदमी द्वारा इंतजाम किए ट्रैक्टरों या जीपों में डाकू जाते हैं तथा इन्हें गांव से दूर खड़ा कर देते हैं. दो आदमी यह प्रदर्शित करते हैं कि ट्रैक्टर या जीप बिगड़ गई है. बाकी लोग गांव में चले जाते हैं तथा लौटते समय ही माल का बंटवारा कर लेते हैं व तितर-बितर हो जाते हैं. डाकू अपने अड्डों पर चले जाते हैं तथा शरीफ घरों में जाकर सो जाते हैं.

डाकुओं के पास हथियारों की कोई कमी नहीं होती. इनके पास प्रारंभ से ऐसे स्रोत चले आ रहे हैं, जो पुलिस के पास भी नहीं हैं. बागी समस्या की शुरुआत में रियासतों में लाइसेंस कोई समस्या नहीं थी. बागी राजे-रजवाड़े से ऊंची क़ीमत देकर हथियार खरीदते थे. इसके बाद उन्होंने हथियारों से हथियार छीने. पुलिस के लोगों ने भी हथियार बेचे. आज़ादी के बाद हैदराबाद पर कार्रवाई हुई. देश के एक वर्ग ने काफी हथियार डाकुओं के पास भिजवाए. कश्मीर पर हुई कार्रवाई के बाद भी इसी व्यापारी तबके ने हथियार उन्हें भिजवाए. बांग्लादेश के लड़ाई ने भी चंबल को हथियारों से पाट दिया. डाकुओं के संपर्क कितने गहरे हैं, इसका प्रमाण यह है कि फौज की फैक्ट्रियों से नया हथियार निकला, तो उसकी पेटियां पहले डाकुओं के यहां खुलीं. जब एसएलआर आई थी, तो उसकी पहली पेटी सोबरन के यहां खुली थी, ऐसा एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया. सोबरन ने एक लाख रुपये सप्लायर को एडवांस दिए थे.

सीमा पर छोटी-मोटी मुठभेड़ों के बाद हथियार अफसर दबा लेते हैं, जो बाद में डाकुओं को बेच दिए जाते हैं. एसएलआर व टीएमसी सेना के हथियार हैं, ये सीधे सेना के पास से ही डाकुओं के पास आते हैं. उनकी गोली भी बाज़ार में नहीं आती, अत: यह भी वहीं से आती है. अभ्यास में गोलियों का खर्च दिखाया जाता है, लेकिन वे बेच दी जाती हैं. 315 बोर की राइफलें डाकू छीन लेते हैं या थ्री नॉट थ्री की राइफल पुलिसवालों को मारकर ले लेते हैं. मलखान का हथियार सारा खरीदा हुआ है तथा विक्रम वगैरह ने मुख्यतय: छीना है, कुछ खरीदा भी है. इस समय अस्टरल 12 बोर की बंदूक 4,000, 315 बोर की राइफल 6,000, एसएलआर 12,000 और टीएमसी 8,000 रुपये में डाकू खरीद रहे हैं. कारतूस पांच से 15 रुपये के बीच खरीदे जा सकते हैं. कहते हैं, मानसिंह ने कभी कारतूस खरीदे ही नहीं. फौज के लोग उन्हें मुफ्त ही दे जाते थे. 12 बोर की बंदूक के कारतूस वह बड़े लोगों से मांग लेते थे.

आजकल बीएसएफ से बहुत सामान बाहर आ रहा है. टेकेनपुर (छतरपुर) में बीएसएफ का प्रशिक्षण केंद्र है. वहां से बहुत हथियार व कारतूस बाहर निकल रहे हैं, जिनसे सीधा फ़ायदा मलखान को हो रहा है. पुलिस खाली कारतूस ले लेती और भरे दे देती है. झूठी मुठभेड़ें दिखाकर भी पुलिस के कारतूस गिरोहों में पहुंचते हैं. लेकिन, डाकुओं को हथियार सप्लाई के सबसे बड़े केंद्र फौज के लोग ही होते हैं.

डाकुओं को उनकी जाति-बिरादरी, परिवार, राजनीतिक संरक्षण देने वालों से समर्थन मिलता है. उनसे लाभ कमाने वाला हर व्यक्ति उनका समर्थक होता है. बीहड़ों के आदिवासी उन्हीं की सहायता पर ज़िंदा रहते हैं. 72 में डाकुओं के आत्मसमर्पण के समय तो आदिवासी रोते थे तथा पेट पीटते थे कि अब हमारा क्या होगा. सन् 72 तक तथा कुछ हद तक 76 तक तो डाकू गिरोहों का ही हुक्म उनके इलाके में चलता था. जिसे वे कहते थे, उसी को वोट पड़ता था. राजनीतिक लोगों ने इसीलिए उनसे जातिगत व रिश्तेदारी पर आधारित सहयोग बनाया. डाकुओं को पुलिस का नकारात्मक समर्थन मिलता है. जैसे किसी थानेदार के रिश्तेदार किसी गिरोह के कार्यक्षेत्र में रहते हैं, तो वह उस गिरोह के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि तब डाकू उसके रिश्तेदारों पर हमला कर देंगे. जब वह थानेदार गिरोह से कभी मिलता है, तो गिरोह उसका दो या पांच हज़ार रुपये से तिलक कर देता है. पुलिस अक्सर छोटे गिरोहों से मिली हुई होती है और कमाई भी करती है. इसकी एक दिलचस्प कहानी धौलपुर क्षेत्र के एक गिरोह के सदस्य ने मुझे सुनाई. डाकुओं ने एक बनिए के लड़कों को पकड़ा तथा 28 हज़ार रुपये लेकर एक थाने की सीमा में उन्हें छोड़ दिया. जिस थाने में पकड़ छूटती है, वहां दो हज़ार रुपये देने होते हैं, यह नियम है. सदस्य के अनुसार, उसने दो हज़ार रुपये थानेदार को, दो हज़ार रुपये डीएसपी को और दो हज़ार रुपये एडिशनल एसपी को दिए. एक हज़ार रुपये मुखबिर खा गया तथा एक हज़ार रुपये इस कुल प्रक्रिया में खर्च हो गए. उस डाकू के अनुसार, 20,000 रुपये ही उन लोगों को मिले. ■

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

आधार कार्ड

देश को गिरवी रखने का षड्यंत्र

"मैं यहां सांसदों को भी बताना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह फ़ैसला किया है कि आधार कार्ड अनिवार्य नहीं किया जाएगा. सर्वोच्च न्यायालय इस बारे में दो-दो, तीन-तीन बार अपनी बात कह चुका है, लेकिन यह सरकार हर जगह आधार कार्ड को अनिवार्य बना रही है. इसका मतलब यह कि कहीं न कहीं कोई निहित स्वार्थ रहा है. और, सरकार ने अघोषित आदेश दिया है कि जो शख्स आधार कार्ड न दे, उसका कोई भी काम कोई विभाग न करे. क्या सर्वोच्च न्यायालय को अपने फ़ैसले के उल्लंघन की चिंता नहीं है? क्या सर्वोच्च न्यायालय के तमाम सम्मानीय जज आधार कार्ड की सच्चाई से अपरिचित हैं?"

हमारी संसद में बैठे लोगों के ऊपर अगर हम कुछ कहें, तो उनकी नाक-भौंह चढ़ जाती है. उन्हें लगता है कि वे देश के सर्वशक्तिमान लोग हैं और उनके ऊपर कुछ भी कहना देशद्रोह है. यह मनोविज्ञान तानाशाही का मनोविज्ञान है. और, यह तानाशाही का मनोविज्ञान उस देश में पनप रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है. हम अगर सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर कुछ कहें, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अपनी अवमानना मान लेता है. लेकिन, आज हम विनम्रतापूर्वक संसद से भी कुछ कहना चाहते हैं और सर्वोच्च न्यायालय से भी निवेदन करना चाहते हैं.

संसद में, जिनमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन शामिल हैं, बैठे लोगों को क्यों आधार कार्ड के पीछे का देशद्रोह नज़र नहीं आता? आधार कार्ड बनाने का फ़ैसला क्यों हुआ? आधार कार्ड किसके कहने पर बनाए जा रहे हैं? आधार कार्ड में क्या-क्या जानकारियां ली जा रही हैं और उन जानकारियों का नियंत्रण किसके पास है और वे कहां एकत्रित की जा रही हैं? क्या इस बारे में हमारे संसद सदस्य जानकारी रखना नहीं चाहते या जानकारी करना नहीं चाहते हैं? आख़िर ऐसा क्यों? देश के संसद सदस्यों की यह ज़िम्मेदारी है कि वे देश के ख़िलाफ़ होने वाली किसी भी गतिविधि को, किसी भी घटनाक्रम को, किसी भी अनियमितता को रोकें और सवाल उठाएं. देश के सांसद सिर्फ़ अपने चुनाव क्षेत्र के प्रति ज़िम्मेदार नहीं हैं. वह तो विधायक का काम है. देश के सांसद देश के प्रति ज़िम्मेदार हैं और जब देश के सांसद उस ज़िम्मेदारी का निर्वहन न करें, तो इसका मतलब है कि वे न केवल ग़ैर-ज़िम्मेदार हो रहे हैं, बल्कि ग़ैर-ज़िम्मेदार की परिभाषा से ज़्यादा कुछ और हो रहे हैं.

देश का मीडिया, देश की ब्यूरोक्रेसी और देश के सांसद आधार कार्ड के बारे में अपने-अपने निहित स्वार्थों की वजह से ख़ामोश हैं और यह ख़ामोशी देश को पूर्णतया आर्थिक और राजनीतिक गुलामी की ओर धकेल रही है. अगले बीस सालों में कौन देश का धारदार नेता हो सकता है, कौन ब्यूरोक्रेट महत्वपूर्ण पदों पर जा सकता है, कौन-कौन अफसर सेनाध्यक्ष हो सकते हैं, किन-किन खुफिया एजेंसियों में किसकी प्रोन्नति कब होगी और किससे कब क्या काम लिया जा सकता है, जैसी जानकारियां आधार कार्ड के ज़रिये हम आज विदेशियों के हाथों में भेज रहे हैं और हम विदेशियों को अपनी नियति सौंप रहे हैं, ताकि वे उस हिसाब से बिना अपनी सेना भेजे, सिर्फ़ पैसा और सुविधाएं उन लोगों को मुहैया कराएं, जो भविष्य में देश की सत्ता का संचालन करेंगे. वे (विदेशी) हमारे देश के मीडिया का संचालन करेंगे और हमारे देश की न्याय व्यवस्था का संचालन करेंगे. अब इसके लिए किसी और तरह की एजेंसी की ज़रूरत नहीं है. अब इसके लिए कुछ भी आवश्यक नहीं है.

यह सारा काम आधार कार्ड कर रहा है, जिसे मनमोहन सिंह सरकार ने नंदन नीलेकणी की लीडरशिप में शुरू कराया था. इस अंक में हमने आधार कार्ड को लेकर सारी जानकारी मुहैया कराई है और हम सरकार को चुनौती देते हैं कि वह इस जानकारी को ग़लत साबित करे. इसमें निकाले गए तथ्यों को ग़लत साबित करे. और, यह चुनौती हम सिर्फ़ इसलिए दे रहे हैं, क्योंकि हम इसे अपना कर्तव्य मानते हैं कि हमें देश की गिरवी रखी जाने वाली आज़ादी की हिफाजत में सार्थक योगदान करना चाहिए. हम नहीं चाहते कि यह आज़ादी कोई भी सरकार गिरवी रखे.

हम अपने देश के सांसदों को क्या कहें, ग़ैर-ज़िम्मेदार से आगे भी क्या कोई शब्द हो सकता है? क्या हम उन्हें राजनीतिक रूप से अनपढ़ कह सकते हैं? हम उन्हें देशद्रोही तो नहीं कहना चाहते, लेकिन काम देशद्रोह का हो रहा है. पूरा देश विदेशी कंपनियों के हाथों में गिरवी रखा जा रहा है, हमारी सारी जानकारियां उनके पास जा रही हैं और हमारे सांसद चुप हैं. संसद में इसके ऊपर सवाल उठाए नहीं जा रहे, संसद में इसके ऊपर बहस नहीं हो रही है.

क्यों इस बात से अनजान हैं दोनों सरकारें, मनमोहन सिंह की सरकार भी और नरेंद्र मोदी की सरकार भी कि देश की सारी जानकारियां विदेशियों को आख़िर किस वजह से दी जा रही हैं? इसमें मनमोहन सिंह सरकार के किस मंत्री का निहित स्वार्थ है? कौन अमेरिका के एजेंट की तरह काम कर रहा है या स्वयं नरेंद्र मोदी इस मुहिम की अगुवाई कर रहे हैं? मुझे बहुत आश्चर्य है, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तब उन्होंने कहा था कि अगर वह सत्ता में आए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आधार कार्ड को बैन (प्रतिबंधित) कर देगी. आधार कार्ड के ख़िलाफ़ संसद में सुषमा स्वराज के बयान हैं और वे बयान नेता विरोधी दल के नाते हैं. लेकिन नई सरकार बनने के बाद, नंदन नीलेकणी और अरुण जेटली की एक घंटे की मुलाक़ात के बाद पूरी सरकार हिंदुस्तान की तमाम जानकारियां आधार कार्ड के ज़रिये विदेशों को भेजने में लग गई है. मनमोहन सिंह सरकार से भी ज़्यादा तेजी से नरेंद्र मोदी सरकार आधार कार्ड का लक्ष्य पूरा करने में लगी हुई है. क्या इस सरकार को कुछ भी ग़लत नज़र नहीं आता? और, यही सवाल हम सांसदों से कर रहे हैं तथा उनसे कहना चाहते हैं कि अगर आप देशद्रोही की परिभाषा में नहीं आना चाहते और इतिहास में अपने नाम के आगे यह काला शब्द नहीं दर्ज कराना चाहते, तो आज आपको इस आधार कार्ड को लेकर संसद में बहस की मांग करनी चाहिए और सरकार से सारी जानकारी हासिल करनी चाहिए. क्यों संसद में बिल सरकार पास नहीं करा रही है, वह लंबित क्यों पड़ा हुआ है? भूमि अधिग्रहण बिल को पास कराने के लिए तो आप एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं, पर आधार कार्ड का बिल क्यों लंबित पड़ा हुआ है? किसके कहने से साठ हज़ार करोड़ रुपये किस फंड से निकाल कर आपने ख़र्च कर दिए? और, इसका नियंत्रण विदेशी कंपनियों को किसके कहने से सौंपा गया है?

मैं सांसदों से एक पत्रकार होने के नाते यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह देश के हित में है कि आप सारी सच्चाई जनता के सामने लाने के लिए सरकार पर न केवल दबाव डालें, बल्कि सरकार को इसके लिए विवश भी करें. अन्यथा यह माना जाएगा कि आप जिस भी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, वह पार्टी इस देश के लोगों की तो है ही नहीं, इस देश की भी नहीं है. और, जो इस देश के नहीं होते हैं, उन्हें ही देशद्रोही कहते हैं.

क्या हम सर्वोच्च न्यायालय से भी यह आशा करें. मैं यहां सांसदों को भी बताना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह फ़ैसला किया है कि आधार कार्ड अनिवार्य नहीं किया जाएगा. सर्वोच्च न्यायालय इस बारे में दो-दो, तीन-तीन बार अपनी बात कह चुका है, लेकिन यह सरकार हर जगह आधार कार्ड को अनिवार्य बना रही है. इसका मतलब यह कि कहीं न कहीं कोई निहित स्वार्थ रहा है. और, सरकार ने अघोषित आदेश दिया है कि जो शख्स आधार कार्ड न दे, उसका कोई भी काम कोई विभाग न करे. क्या सर्वोच्च न्यायालय को अपने फ़ैसले के उल्लंघन की चिंता नहीं है? क्या सर्वोच्च न्यायालय के तमाम सम्मानीय जज आधार कार्ड की सच्चाई से अपरिचित हैं? क्या सर्वोच्च न्यायालय के सम्मानीय जज अपनी ही अदालत में चल रही सुनवाई में आए तथ्यों को अनदेखा करना चाहते हैं? क्या वे सरकार को अपने ही द्वारा दिए गए ऑब्जर्वेशन के ख़िलाफ़ जाते हुए देखकर सख्ती से यह नहीं कह सकते कि सरकार ऐसा न करे. मैं सर्वोच्च न्यायालय से इसलिए यह अनुरोध कर रहा हूं, क्योंकि लोकतंत्र में बहुत सारी जगहों पर उसने एक आशा पैदा की है. इसलिए सर्वोच्च न्यायालय से यह अनुरोध है कि सरकार द्वारा उसके ऑब्जर्वेशन या उसके फ़ैसले की अनदेखी करने के मामले में, जो देश के हितों के साथ जुड़ा हुआ है, हस्तक्षेप करे.

ये बातें मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि ये सारे तथ्य देश की जनता के सामने नहीं हैं. जनता देश को बंधुआ बनाने के रास्ते पर ले जाने वाले क़दमों का बारीकी से विश्लेषण नहीं करती. पर अफ़सोस यह है कि न राजनेता इस काम को कर रहे हैं और न हमारे मीडिया के दोस्त. सबका कहीं न कहीं कोई हित है. इसलिए हमारा यह आग्रह है सांसदों से भी और सर्वोच्च न्यायालय से भी कि वे आधार कार्ड से जुड़े उन तमाम तथ्यों, जिनका हमने इशारा किया है इसी अंक में अपने आमुख में, के बारे में देश को फौरन जानकारी दें. वरना यह देश सांसदों और सर्वोच्च न्यायालय को कम से कम इस अक्षम्य अपराध के लिए क्षमा नहीं करेगा. ■

editor@chauthiduniya.com

नाइजीरिया को आदर की ज़रूरत है

भारत में एक बहुमुखी, लेकिन असंयमित रंगभेद मौजूद है. किसी भी भारतीय को, चाहे वे पशिचमी देशों में रह रहे हों या भारत में, अगर उन्हें ज़रा भी छेड़ेंगे, तो काले अफ्रीकियों के लिए उनके मन में अपमान की भावना ज़ाहिर हो जाएगी. ख़ास तौर पर जब वे अपनी भाषा में बात करते हैं, जिसे कोई दूसरा समझ नहीं सकता. दरअसल, भारतीय खुद को काला नहीं समझते. किसी मैरिज वेबसाइट या समाचार-पत्रों के मैट्रिमोनिअल यह यकीन दिलाने के लिए काफी हैं कि पुरुष मंगल ग्रह से आए हैं और यह कि भारतीय खुद को गोरा-चिट्टा मानते हैं. कम से कम उत्तर भारत की कल्पना में तो यही है.

मेघनाद देसाई

भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह ने विवादित बयान जारी करने में महारथ हासिल कर ली है. उन्होंने अपने हालिया बयान से प्रसिद्ध व्यक्तियों को अपमानित करने के क्रम में एक और कड़ी जोड़ ली है. जो भी हो, उन्होंने जो कहा है उसमें कुछ सच्चाई का अंश ज़रूर है, जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए. मैंने गिरिराज सिंह को यह कहते पढ़ा है कि भारतीय रंगभेदी होते हैं, ख़ास तौर पर तब, जब सवाल काले और सांवले रंग के लोगों का हो तो. उनका ख्याल है कि अगर राजीव गांधी ने एक श्वेत (गोरी) यूरोपीय महिला के बजाय किसी नाइजीरियाई महिला से शादी की होती, तो कांग्रेसी उसे अपना अध्यक्ष कभी नहीं चुनते. ज़ाहिर है, सोनिया गांधी और शेष कांग्रेसी इस बयान से क्रोधित हैं. लालू प्रसाद यादव ने इस बयान के विरोध में जो कहा, वह भी महिला विरोधी था, खास तौर पर सांवले रंग की महिलाओं के लिए. इसके बावजूद सच्चाई यह है कि जब राजीव गांधी ने सोनिया मानिओ से शादी की थी, तो दिल्ली के संभ्रांत वर्ग ने खूब नाक-भौं सिकोड़ी थी. सोनिया श्वेत ज़रूर थीं, लेकिन क्या सामाजिक हैसियत में वह राजीव गांधी से कम नहीं थीं? वे (लोग) कहते थे कि राजीव गांधी ने एक आया से शादी की है! बाद में भाजपा ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के विचार का बहुत विरोध किया था. ऐसा होने की स्थिति में पार्टी ने गंभीर परिणामों की धमकी दी थी. लिहाज़ा इस तथ्य के बावजूद कि वह नाइजीरियाई नहीं थीं और जीवन के 35 साल भारत में गुजारने के बाद भी उन्हें भारतीय नहीं स्वीकार किया गया.

भारत में एक बहुमुखी, लेकिन असंयमित रंगभेद मौजूद है. किसी भी भारतीय को, चाहे वे पश्चिमी देशों में रह रहे हों या भारत में, अगर उन्हें ज़रा भी छेड़ेंगे, तो काले अफ्रीकियों के लिए उनके मन में अपमान की भावना ज़ाहिर हो जाएगी. ख़ास तौर पर जब वे अपनी भाषा में बात करते हैं, जिसे कोई दूसरा समझ नहीं सकता. दरअसल, भारतीय खुद को काला नहीं समझते. किसी मैरिज वेबसाइट या समाचार-पत्रों के मैट्रिमोनिअल यह यकीन दिलाने के लिए काफी हैं कि पुरुष मंगल ग्रह से आए हैं और यह कि भारतीय खुद को गोरा-चिट्टा मानते हैं. कम से कम उत्तर भारत की कल्पना में तो यही है. भारतीय चेतना ऐसी है कि एशिया में रहने के बावजूद हमारी निगाहें पश्चिम की ओर केंद्रित रहती हैं. हमारी कल्पना यूरोपीय कल्पना है. इसके बावजूद जब कोई यूरोपीय भारत के सार्वजनिक जीवन का हिस्सा बनना चाहता है, तो जेनोफोबिया (विदेशियों के प्रति घृणा का भाव) आगे आ जाता है. भारतीयों को पश्चिमी देशों के लोगों से ईर्ष्या तो हो सकती है, लेकिन वे अपने घर पर अपनी श्रेष्ठता दर्ज कराना चाहते हैं. इसलिए इतने वर्षों तक सोनिया के प्रति विस्तृत नेहरू परिवार और कांग्रेस में पूर्वाग्रह जारी रहा. आपको याद होगा कि शरद पवार कांग्रेस से बाहर चले गए थे, क्योंकि वह किसी विदेशी को पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनने देना चाहते थे. कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की उनके प्रति अकड़ उस समय तक जारी रही, जब तक उन्होंने पार्टी की डूबती नैय्या पार नहीं लगा दी.

बॉलीवुड ने भी इस रवैये का चित्रण किया है. यहां वर्षों से गोरी औरत एक अनोखी चीज़ रही है, जो स्थानीय हीरो को सच्चाई के रास्ते से भटकाने के लिए उस पर डोरे डालती है. किशोर साहू की फिल्म मयूरपंख, जिसमें ओडेटी फ़र्गुसन थीं या फिल्म शेक्सपियर वाला, जिसमें केंडल बहनें और शशि कपूर थे, किसी को याद नहीं होंगी, लेकिन हिंदी फिल्मों में आपको कोई अफ्रीकी हिरोइन या किसी उप-सहारा देश की पृष्ठभूमि वाली कोई फिल्म नहीं मिलेगी. यहां तक कि सांवली भारतीय हिरोइनें भी दुर्लभ हैं. व्ही. शांताराम ने एक सांवली हिरोइन संध्या को तीन बत्ती चार रास्ता में कास्ट किया था, लेकिन दर्शकों ने उसे पसंद नहीं किया. पौराणिक कथाओं में कृष्ण सांवले हो सकते हैं, लेकिन राधा का गोरा होना ज़रूरी है. इन सबके बावजूद भारतीयों द्वारा अफ्रीकियों को गंभीरता से लेने के और भी कई कारण हैं. नाइजीरिया में अभी-अभी परिवर्तनकारी लोकतांत्रिक चुनाव हुए हैं. स्वतंत्र नाइजीरिया के 55 वर्षों के इतिहास में यह पहला मौक़ा है, जब शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरित हुई है. नाइजीरिया अफ्रीका का न केवल सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, बल्कि इसमें सभी उप-सहारा देशों में सबसे पहले एक समृद्ध अर्थव्यवस्था बनने की संभावना मौजूद है. यहां पेट्रोल भंडार मौजूद हैं. यह देश गृहयुद्ध, कुशासन और भ्रष्ट सैन्य शासकों के वर्षों के कुचक्र से निकल आया है. नाइजीरिया का एक लोकतांत्रिक देश बनने का संघर्ष पाकिस्तान से बहुत समानता रखता है. सैन्य शासकों ने देश का कोई भला नहीं किया है. यहां लोकतंत्र को और अधिक मजबूती देने की आवश्यकता है. यह बहुत बड़ा देश है, जो उत्तर के मुस्लिम बाहुल्य और दक्षिण के ईसाई बाहुल्य दो क्षेत्रों में बंटा हुआ है. जिस तरह तालिबान पाकिस्तान के लिए मुसीबत बने हुए हैं, उसी तरह बोको हराम नाइजीरिया के मुसलमानों को आतंकित कर रहा है. फ़िलहाल नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. वह 30 साल पहले कुछ दिनों के लिए एक सैन्य तानाशाह थे. उन्होंने अपनी छवि सुधारी और एक नए डेमोक्रेट के तौर पर लोगों के बीच गए तथा उन्हें वोट देने के लिए राज़ी किया. नाइजीरिया के लोगों ने पिछली बातें भुलाकर बुहारी के सुधार के वादों और भविष्य में भ्रष्टाचार मिटाने की उनकी लड़ाई में अपना विश्वास जताया है. दरअसल, यह भारतीयों के लिए जानी-पहचानी बात है. इसलिए गिरिराज सिंह के बयान के बावजूद नाइजीरिया को भारत की तवज्जो और आदर की ज़रूरत है. ■

feedback@chauthiduniya.com

हीट स्ट्रोक तेज गर्मी की वजह से होता है. इसमें तेज धूप में ज्यादा देर रहने से चक्कर आने लगता है. मन मिचलाना, रक्तचाप एकाएक कम हो जाना और तेज बुखार भी हीट स्ट्रोक के लक्षण है. इससे बचने के लिये तेज धूप में निकलने से पहले सिर को ढंक लें, ढीले कपड़े पहने और ढेर सारा पानी पियें. साथ ही तेज और सीधी धूप में एक जगह ज्यादा देर तक न खड़े हों.

बैगा समुदाय आधारभूत सुविधाओं से महरूम

विनोद पटेरिया

डिन्डोरी मध्य प्रदेश का वह जिला है, जहां की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य के अधिकारी अपना सिर नहीं खपाने की जहमत नहीं उठाना चाहते. राजनीतिक नेतृत्व के पास अपनी समस्याएं हैं. अब भला बच्चों का स्वास्थ्य, टीकाकरण, माताओं की प्रसूति सेवा से संबंधित समस्या भला वोट बैंक कैसे बन सकती हैं?

बैगा जनजाति वह आदिम जनजाति है, जो ब्रिटिश शासन काल के प्रारंभ से पहाड़ों के ऊपर वनों में अपनी आदिम जीवन पद्धति के साथ निवास करती थी, जिन्हें शासन ने पहाड़ से नीचे लाकर ग्रामों में बसाया. इस प्रक्रिया के साथ ही उनकी समग्र पोषण व स्वास्थ्य ज्ञान परंपरा का क्षय प्रारंभ हो गया. इस प्रकार बैगा, जिसका शाब्दिक अर्थ ही प्रकृति की शक्तियों का उपयोग कर इलाज करने वाला होता है और जो वास्तव में जड़ी–बूटी से स्वास्थ्य संरक्षण का विशारद थे, वही आज परम्परागत ज्ञान से वंचित हो गए हैं.

बैगा आदिम जनजाति प्रकृति की सबसे निकट समुदाय में से एक है. वह बेवर खेती पद्धति के द्वारा अन्न उत्पादन करते रहे हैं, जिसे पर्यावरण के तथाकथित हितचिंतक वन का विनाश मानते हैं और इस पर रोक लगाने की बात करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बैगाओं की नई पीढ़ी में बेवर खेती पद्धति के प्रति नकारात्मक रुझान बनता जा रहा है और वह आधुनिक कृषि से जुड़ी हाइब्रिड जी.एम. आदि की ओर आकर्षित हो रहे हैं. बैगा अपनी बेवर पद्धति की खेती में एक साथ कई बीज बोते थे. इससे कम वर्षा होने पर ज्यादा पानी वाली फसलें तो मर जाती, लेकिन कम पानी वाली फसलें जीवित रह जाती हैं. इस प्रकार हमेशा खाद्य उत्पादन श्रृंखला बनी रहती है. बैगा कोदो, कुटकी, समां उगाते रहे हैं. कोदो, कुटकी खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक विश्वसनीय खाद्य पदार्थ है. उन्हें उत्पादन पश्चात एक बार मिट्टी की कोठी में भंडारित करने के बाद वर्षों तक सुरक्षित किया जा सकता है. ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं, जब 40 से 50 वर्ष पश्चात खाद्य भंडारों के खोलने पर कोदो या कुटकी का संग्रहित भंडार उत्तम खाने योग्य अवस्था में प्राप्त हुआ है. इसके अतिरिक्त बैगा परम्परागत रूप से कई तरह के फल–फूल, कन्द–छाल व पत्तियां, कई तरह की भाजी, पीहरी (मशरूम), ज्वार, मक्का से अपनी खाद्य आवश्यकता की पूर्ति के लिए करते रहे हैं, लेकिन डिन्डोरी, मंडला, कर्वधा और बिलासपुर के मध्य अमरकंटक, रायपुर और जबलपुर इन उत्पादों के बड़े बाजार बन गए हैं. यहीं से बाजार व्यवस्था से उनके शोषण की श्रृंखला का अनचाहा विकास हुआ है. अंधाधुंध दोहन व शोषण से इस संपदा का लगभग विनाश हो गया. उदाहरण के लिए बैगा को वनों में 12 से अधिक किस्म के कन्द मिलते थे. यह कन्द आवश्यकता पड़ने पर जंगल से खोदे जाते और इससे पूरे समूह का पेट भर जाता था. इनमें कनिहाकांदा 10 से 15 किलो तक का होता था. अब उन्हे खोजने पर भी प्राप्त करना कठिन हो रहा है. अत्यधिक दोहन से कई बीज ही खत्म हो गए हैं. इसलिए यदि कोई चाहे भी तो इसके पुनर्उत्पादन प्रक्रिया को चलाया जाना कठिन है. इसलिए आवश्यकता सामुदायिक बीज बैंक बनाने की है, जहां असानी से बैगा को परम्परागत बीज उपलब्ध हो सके. आज आवश्यकता बेवर खेती के फायदे, पारम्परिक बीजों के गुण, उनका स्वास्थ्य पर प्रभाव, सामाजिक–आर्थिक महत्व पर सामाजिक शिक्षण कार्यक्रम चलाकर पारम्परिक, मिश्रित और प्राकृतिक रूप से बेवर कृषि प्रणाली को पुन: उपयोग में लाने की जरूरत है, जिससे बैगा की परम्परागत खाद्य सुरक्षा को निरंतर रखा जा सके.

डिन्डोरी जिले के करंजिया व बजाग विकासखंड के 52 गांव, जहां बैगा जाति सर्वाधिक सघन रूप से निवास करती हैं, उन गांवों को सम्मिलित रूप से बैगा चक कहा जाता है. वहां स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि करंजिया विकासखंड के बैगा चक स्थित बहारपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज भी किसी चिकित्सक की नियुक्ति नहीं है. एक चतुर्थ श्रेणी के स्वास्थ्य कर्मचारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित कर रहे हैं. आधारभूत सुविधा के नाम पर यहां फोन, एम्बुलेंस, जननी एक्सप्रेस सेवा जैसी कोई भी सुविधा नहीं है. समस्याएं तब और भी गंभीर हो जाती हैं, जब प्रशासन द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के लिए जंगल के अन्दर की बैगा महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया जाता है, जहां कोई सुविधा ही नहीं है और जब मामला बिगड़ जाता है, तो उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करंजिया भेज दिया जाता है. वहां भी कोई महिला चिकित्सक न होने के कारण उसे पुन: जिला चिकित्सालय डिन्डोरी रेफर कर दिया जाता है.

बैगा आदिम जनजाति प्रकृति की सबसे निकट समुदाय में से एक है. वह बेवर खेती पद्धति के द्वारा अन्न उत्पादन करते रहे हैं, जिसे पर्यावरण के तथाकथित हितचिंतक वन का विनाश मानते हैं और इस पर रोक लगाने की बात करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बैगाओं की नई पीढ़ी में बेवर खेती पद्धति के प्रति नकारात्मक रुझान बनता जा रहा है और वह आधुनिक कृषि से जुड़ी हाइब्रिड जी.एम. आदि की ओर आकर्षित हो रहे हैं. बैगा अपनी बेवर पद्धति की खेती में एक साथ कई बीज बोते थे.

दो वर्ष पूर्व एक ही माह में ग्राम खारिदिह में रम्मू बैगा की पत्नी और गर्भस्थ शिशु मारे गए. इसके बाद एक दूसरी घटना के दौरान पवन की पत्नी और गर्भस्थ शिशु यानी जच्चा और बच्चा दोनों ही मारे गए. यह सिलसिला निरंतर जारी है. जून 2013 में कुंवर सिंह ने अपने शिशु को खोया, तो वहीं जुलाई में कौशल्या बाई अपने शिशु को जन्म देने के बाद उसका चेहरा भी नहीं देख पाई. यह सब कुछ हुआ संस्थागत प्रसव के लक्ष्य पूर्ति हेतु किए गए गैरनियोजित व अनियमित प्रयासों के परिणामस्वरूप. टीकाकरण की नियमितता व प्रभावशीलता को इस तरह समझा जा सकता है कि चौरादादर स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र सड़क मार्ग से 27 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. वहां बारिश के समय किसी भी तरह पहुंचना कठिन और असंभव है. उप स्वास्थ्य केंद्र में कोई फ्रीज व्यवस्था नहीं है, फिर भी टीकाकरण नियमित हो रहा है. यहां की कोल्ड चौन कैसे चलती है, यह रहस्य का विषय है.

बैगा अपनी परम्परागत जड़ी–बूटी के ज्ञान में ही अपने बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा देखते हैं, लेकिन अब स्थिति यह है कि उनकी परम्परागत पद्धति हाथ से छूट ही गई है और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बहुत ही जर्जर है. ऐसे में बैगा समुदाय के सामने यह सवाल मुंह बाए खड़ा है कि अपने स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए वे कहां जाएं? ■

feedback@chauthiduniya.com

गर्मी के मौसम की बीमारियों से रहें सावधान

चौथी दुनिया ब्यूरो

गर्मी के मौसम में कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. इन बीमारियों का संबंध बढ़ते तापमान के साथ–साथ हमारे खाने पीने की आदतों से भी है. गर्मी शुरू होते ही दूषित पानी एवं खुले में बिक रहे खाद्य पदार्थों से पैदा होने वाली जलजनित बिमारियां सबसे आम होती हैं, साथ ही गर्मियों में नमी बढ़ने के कारण वातावरण में अनेक प्रकार के संक्रमण बड़ी तेजी के साथ फैलने लगते हैं. यह हैं गर्मियों में होने वाली कुछ आम बीमारियां और उनसे बचाव के उपाय.

लू लगना

कई बार गर्मी से अजीब–सी घबराहट होने लगती है, इसे बोलचाल की भाषा में लू लगना भी कहते हैं. हमारे शरीर के साथ दिमाग भी गर्मी की चपेट में आ जाता है. तेज बुखार के साथ उल्टियां और शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो जाना भी इसके लक्षण हैं. गर्मी में पसीना ज्यादा आने से पानी की कमी होने का खतरा रहता है, जिससे लू लगने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है. ऐसे में ज़रूरी है लगातार पानी पीते रहें खासकर अगर धूप में बाहर जा रहे हों. इस बात का भी ख्याल रखें कि खाली पेट न हों. अपने साथ पानी और धूप से बचाव के लिए छाता या सिर ढंकने के लिए स्कार्फ ज़रूर रखें. लू से बचने का एक घरेलू उपाय यह भी है कच्चे आम का पन्ना बनाकर पीया जाये. इसी तरह की बीमारी हीट स्ट्रोक भी है. हीट स्ट्रोक तेज गर्मी की वजह से होता है. इसमें तेज धूप में ज्यादा देर रहने से चक्कर आने लगता है. मन मिचलाना, रक्तचाप एकाएक कम हो जाना और तेज बुखार भी हीट स्ट्रोक के लक्षण है. इससे बचने के लिये तेज धूप में निकलने से पहले सिर को ढंक लें, ढीले कपड़े पहने और ढेर सारा पानी पियें. साथ ही तेज और सीधी धूप में एक जगह ज्यादा देर तक न खड़े हों.

डिहाइड्रेशन

गर्मी के मौसम में होने वाली सबसे आम बीमारी है डिहाइड्रेशन या शरीर में पानी का कम होना. शरीर से जब अत्यधिक मात्रा में तरल पदार्थ कम हो जाते हैं तो उस स्थिति को डिहाइड्रेशन बोलते हैं. गर्मी में शरीर से पानी की कमी हो जाने के कई कारण है, जैसे बहुत पसीना आना, उल्टी एवं दस्त के लक्षण वाले रोग जैसे गैस्ट्रोइंटेराइटिस, फूड प्वाइजिनिंग आदि. इसके अलावा कुछ बीमारियां जैसे लू लगना, टाइफाइड इत्यादि से भी डिहाइड्रेशन हो सकती हैं. इसके प्रमुख लक्षण हैं मुंह सूखना, कमजोरी, चक्कर आना, पीले रंग का पेशाब होना और शरीर का तापमान कम हो जाना. डिहाइड्रेशन अधिक बढ़ जाने पर आंखों का धंस जाना और त्वचा पर झुर्रिया आने जैसे लक्षण भी सामने आते हैं. इससे बचने के लिए केवल समय–समय पर और अच्छी मात्रा में पानी पीते रहने की जरूरत है. डिहाइड्रेशन से निजात पाने के लिए सबसे पहले शरीर में पानी की कमी को दूर करने की आवश्यकता होती है. इसके लिए साफ़ पानी के अलावा आम का पन्ना, पतली लस्सी, नारियल पानी, बेल का शरबत, शिकंजी, छाछ और ओआरएस को थोड़ी–थोड़ी देर में रोगी को देना चाहिए. डिहाइड्रेशन को कभी भी हल्के में न लें. कई बार डिहाइड्रेशन बहुत मामूली होता है, जिससे लोग उसे नजरअंदाज करते हैं, लेकिन बढ़ जाने पर यह घातक बन सकता है.

फूड प्वाइजनिंग

गंदा पानी और बाहर का दूषित या खुला रखा हुआ पानी पीने से पेट में संक्रमण और फूड प्वाइजनिंग होने का खतरा होता है. यह खाने में बैक्टीरिया की वजह से होता है. फूड प्वाइजनिंग से रोगी को डायरिया और उल्टी जैसी तकलीफ होती है. सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल ने अनुमान लगाया है कि एक साल में विश्व स्तर पर 7 करोड़ 60 लाख लोग फूड प्वाइजनिंग के शिकार होते हैं. इस तरह के ज्यादातर मामले गर्मियों में ही होते हैं क्योंकि गर्मियों में खाना जल्दी ख़राब होता है. फूड प्वाइजनिंग के प्रमुख लक्षण हैं बुखार, उल्टी– दस्त होना, चक्कर आना और शरीर में दर्द और कमज़ोरी महसूस होना. कुछ बातों का ध्यान रखकर इस समस्या से बचा जा सकता है. जैसे अगर खाने–पीने में साफ–सफाई का ध्यान रखें, जो भी खाना खाएं वह ताजा हो और पीने का पानी उबला हुआ या फ़िल्टर किया हुआ हो. साथ ही जिन बर्तनों में आप खाना खा या पका रहे हों वो अच्छे से धुले हों और जिस जगह पर आप खाना खा रहे हैं वो साफ–सुथरी हों. साथ ही खाने से पहले हाथ अच्छे से धोयें और बाजार में खुले में बिकने वाली खाने की चीज़ों से इन दिनों परहेज करें. फूड प्वाइजनिंग होने पर पानी में नींबू, नमक और शक्कर मिलाकर पीना फायदेमंद होता है. लेकिन अगर लगातार उल्टी हो रही हो, उल्टी के दौरान खून आए, पेट में तेज दर्द हो, बोलने और दिखाई देने में तकलीफ हो तो फौरन डॉक्टर को दिखाएं.

टायफाइड

टायफाइड गर्मियों में होने एक खतरनाक बीमारी है. इस बीमारी में तेज बुखार आता है, जो कई दिनों तक बना रहता है. यह बुखार कम–ज्यादा होता रहता है, लेकिन कभी सामान्य नहीं होता. गर्मी के मौसम में टायफाइड होने पर लू लगने के कारण बुखार होने का खतरा अधिक रहता है. टायफाइड सल्मोनेला नामक एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है. यह बैक्टीरिया प्रदूषित पानी और खाने की चीज़ों के सेवन से आंतों में जाकर वहां से रक्त में पहुंच जाता है. टायफाइड होने पर शुरू में हल्का बुखार रहता है जो धीरे–धीरे तेज होता जाता है. भूख कम लगना,उल्टियां आना, पेट में दर्द, सिर दर्द, बदन दर्द और सूखी खांसी आना भी इसके लक्षण हैं. रोग की गंभीर स्थिति में बेहोशी भी आ सकती है. इस रोग की जटिलताओं से बचने के लिए लक्षण दिखते ही डॉक्टर के पास जाएं. टायफाइड से बचाव के लिए सबसे ज़रूरी है दूषित पानी व दूषित खाने की चीज़ों से बचाव. खुले और कटे हुए फल–सब्जियों या खाने को न खाएं और जहां तक हो सके ताज़ा खाना ही खाएं. पानी और अन्य तरल पदार्थों का पर्याप्त मात्रा में सेवन करें लेकिन ध्यान रखें पानी साफ़ हो. इसके अलावा साबुन से और बहते पानी में हाथों को कहीं से भी आने पर अच्छी तरह से धोयें. खाने से पहले और शौच के बाद हाथ जरूर धोयें. टायफाइड की बीमारी से बचाव के लिए टीका(वैक्सीन) भी उपलब्ध है जो हर 2 साल बाद दोबारा लगवाना पड़ता है. ■

यमन से भारतीयों की सकुशल वापसी

सेना को सलाम

संकट की सनसनी के बीच भारतीय नागरिकों को सकुशल स्वदेश लाने के कारण पूरे विश्व में भारत की जय-जयकार हो रही है. जय-जयकार हो भी क्यों न. भारत ने संकट की इस घड़ी में सिर्फ अपने देश के नागरिकों की ही नहीं, बल्कि 41 देशों के 960 से भी अधिक नागरिकों की जान बचाकर मानवता की एक नायाब मिशाल जो पेश की है. इस पूरे मिशन के अगुआ थे विदेश राज्य मंत्री जनरल वी के सिंह और उनका साथ दे रहे थे वायुसेना और नौसेना के अधिकारी और जवान. सच मायने में देखा जाए, तो इस अविश्वसनीय सफलता के बाद हमारा यह नारा और भी अधिक बुलंद हो चला है, यस वी कैन...यस वी कैन.

राजीव रंजन

युद्धग्रस्त यमन से भारतीयों को सुरक्षित निकालने का अभियान ऑपरेशन राहत समाप्त हो चुका है. भारतीय वायुसेना और नौसेना के इस संयुक्त अभियान में यमन से 4500 से भी ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया. आज चारों तरफ भारत की जय-जयकार हो रही है. यमन से सही-सलामत वापस लौट चुके लोगों के परिवारों में खुशी की लहर है. यह सब संभव हो सका है विदेश राज्यमंत्री वी के सिंह और सेना की सूझबूझ से, जिन्होंने खुद युद्धग्रस्त यमन में बचाव अभियान की कमान संभाल रखी थी और हवाई या अन्य हमलों की परवाह किए बगैर अपनी जान पर खेलकर सीना ताने युद्ध क्षेत्र में डटे रहे.

मुश्किलें कम न थीं

ऐसा नहीं था कि सबकुछ बहुत आसानी से होता चला गया. वहां कैसे हालात थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका सहित 26 से अधिक देशों ने यमन से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने का भारत से अनुरोध किया था. फायरिंग के बीच अपनों को निकालना बहुत ही मुश्किल था. किसी भी वक्त किसी का भी सीना छलनी हो सकता था. ऐसे हालात में भारतीय सेना के लिए अपना हेडक्वार्टर बनाना जोखिम भरा था. तीन अलग-अलग एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ बातचीत करके अपने हवाईजहाजों को वहां पर ले जाने की चुनौती अलग थी, क्योंकि भारतीय जहाज से पहले वहां कई देशों की जहाजों को टारगेट किया जा चुका था. अदन की खाड़ी से लोगों को निकालने के लिए नौसेना को बोट तक किराए पर लेने पड़े. हर तीन घंटे में एक फ्लाइट भारतीयों को वापस लेकर आ रही थी. एअर बस ए-380 में बैठने के लिए 180 सीटें थीं, लेकिन सीटों से अधिक लोगों को विमान में मैनेज कर लाया गया.

कुछ का काम है कहना

जिन्हें जनरल और उनके सिपहसालारों की जांबाजी पर गर्व नहीं होता, जो लोग जनरल की बातों पर बयानबाजी कर रहे हैं या उनकी बातों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, उन्हें यमन की तस्वीरें ध्यान से देखनी चाहिए. यमन से बच कर भारत लौटे नागरिकों का कहना है कि एक मिनट की सांस लेना भी वहां मुश्किल हो रहा था. वे किसी तरह से मौत के मुंह से बच निकले हैं, क्योंकि वहां 20 मिलियन लोग थे और 60 मिलियन बंदूकें. यमन के अमनदूत जनरल वी के सिंह, सेना के अधिकारियों और जवानों को पूरी दुनिया सलाम कर रही है. फिर क्यों कुछ लोग सच्चाई को देखना नहीं चाहते.

सरहदों की दीवारों पर भारी मानवता

अगर मानवता की सेवा करने की किसी ने ठान ली हो, तो उसे किसी भी देश की सरहद नहीं रोक सकती. पाक सेना द्वारा यमन से 11 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने की घटना कुछ ऐसा ही बयां कर रही है, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने पाकिस्तानी समकक्ष नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया है. नवाज शरीफ ने विशेष विमान से 11 भारतीयों को कराची से नई दिल्ली भेजने की व्यवस्था की थी.

स्थाई एजेंसी की जरूरत

भारत सरकार ने गल्फ वार के वक्त इराक और कुवैत से 1.11 लाख भारतीयों को, इराक से ही साल 2003 में करीब 50 हजार भारतीयों को, साल 2006 में लेबनान युद्ध के दौरान कुल 2280 लोगों को, साल 2011 में लीबिया युद्ध के दौरान 15 हजारों लोगों को, युक्रेन से 1000 छात्रों को और सीरिया से 3000 भारतीयों को बचाया. इसे देखते हुए इस बात की जरूरत महसूस होने लगी है कि एक ऐसी स्थाई एजेंसी का गठन भारत सरकार को करना चाहिए, जो संकट के समय विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापसी के लिए सुनियोजित तरीके से कार्य कर सके.■

feedback@chauthiduniya.com

जनरल की जांबाज़ी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यमन से भारतीयों को निकालने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन राहत की सफलता के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के समन्वय और उस समय जिबूती में मौजूद विदेश राज्य मंत्री जनरल वी के सिंह के योगदान की काफी प्रशंसा की. जनरल की आखिर प्रशंसा हो भी क्यों न. जहां कदम-कदम पर फायरिंग हो रही हो, बम गिर रहे हों, हर कदम पर कोई कातिल खड़ा हो, वहां भारत सरकार के मंत्री ने जो किया, वो विश्व के किसी भी देश के मंत्री के लिए गजब का चैलेंज था. जनरल सिंह तीन दिनों में कई बार जिबूती से सना के बीच आए-गए. कई देशों से बातें कर अभियान की गति बनाए रखी. वे हिंसा से ग्रसित यमन के सना शहर में स्वयं रहकर अलग-अलग एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित कर रहे थे और भारतीय नागरिकों को बाहर निकाल रहे थे. उन्होंने नौसैनिक पोतों तथा वायुसेना एवं एयर इंडिया के विमानों में यात्रियों से मुलाकात भी की. हवाई हमलों के बीच आज अगर भारतीय नागरिक यमन से जिंदा लौट आए या उन्हें सही-सलामत बचा लिया गया, तो इस

सफलता के पीछे सरकार के मंत्री वी के सिंह की सूझबूझ ही है. यमन हिंसा की चपेट में दुनिया के अलग-अलग देशों के नागरिक फंसे हैं. वो यमन से बाहर निकलना चाहते हैं. लेकिन एक-दो मामलों को छोड़ कर भारत के अलावा कोई भी देश अपने नागरिकों को बाहर निकालने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत के रेस्कयू ऑपरेशन का नेतृत्व जनरल वी के सिंह कर रहे थे. इतिहास में पहली बार कोई केंद्रीय मंत्री युद्धक्षेत्र में प्रवेश कर लोगों को बचाने का ऑपरेशन चला रहा था. युद्धग्रस्त यमन में फंसे भारतीयों को निकालने में प्रशासनिक एवं रक्षा अधिकारियों तथा संगठनों के योगदान को भी पीएम ने सैल्यूट किया. सच मायने में देखा जाए, तो विदेश मंत्रालय, नौसेना, वायुसेना, एयर इंडिया, जहाजरानी, रेलवे और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय से नागरिकों के बचाव कार्य में बहुत मदद मिली. ■

सही दिशा में एक क़दम

शफ़ीक आलम

feedback@chauthiduniya.com

ईरान परमाणु समझौता

ईरान और पश्चिमी ताक़तों के बीच रिश्तों में खटास तो इस देश में 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से ही चला आ रहा है, लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम के चलते वर्ष 2002 के बाद कई मौके ऐसे आए, जब लगा कि ईरान पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की तरफ से किसी भी समय फौजी करवाई हो सकती है. अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ईरान पर अघोषित परमाणु कार्यक्रम चलाने का आरोप 1992 से ही लगाता आ रहा है. 2002 में ईरान के एक असंतुष्ट ग्रुप नेशनल कॉन्सिल ऑफ़ रेसिस्टेंट ऑफ़ ईरान के प्रवक्ता अलीरज़ा जफ़रजादे ने भी यह आरोप लगाया था कि देश में दो परमाणु ठिकाने ऐसे हैं, जिसका ज्ञान दुनिया को नहीं है. उसके बाद से ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कई प्रस्ताव पारित हुए. इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (आईएईए) को देश के परमाणु ठिकानों की जांच की ज़िम्मेदारी दी गई. आईएईए ने वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है. उसके बाद से सुरक्षा परिषद ने ईरान पर चार बार सीमित प्रतिबन्ध के प्रस्ताव पारित किए. वर्ष 2009 के प्रस्ताव पर भारत ने भी ईरान के विरोध में मतदान किया था. इसके अतिरिक्त अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने अपनी तरफ से ईरान पर अतिरिक्त प्रतिबन्ध लगा रखे थे.

इस पृष्ठभूमि में ईरान और पी 5 प्लस 1 (अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और जर्मनी) के बीच स्विट्ज़रलैंड के शहर लोज़ान में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हुआ अंतरिम समझौता कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर यह इस साल जून महीने में प्रस्तावित दोनों पक्षों के बीच व्यापक समझौता हो जाता है, तो इससे जहां इस क्षेत्र की भू-राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, वहीं आर्थिक रूप से भी यह समझौता बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा. जहां तक इस समझौते का सवाल है, तो वह जून 2013 में ईरानी वार्ताकार हस्सन रूहानी के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से ही अमेरिका और ईरान में इस मुद्दे पर गोपनीय बातचीत शुरू हो गई थी, जिस पर अभी व्यापक समझौता होना बाकी है.

ईरान हमेशा से अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं करने की बात कहता रहा है. देश के कट्टरपंथी भी सरकार पर इस मसले को लेकर नहीं झुकने के लिए दबाव डालते रहे हैं. हालिया समझौते के विरोध में कट्टरपंथियों ने तेहरान में विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन सरकार ने उसे गैर कानूनी बता कर ख़ारिज कर दिया. बहरहाल, मीडिया में आई ख़बरों के मुताबिक ईरान में इस समझौते के बाद विजय जुलूस निकाले गए और इसे एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा गया, लेकिन दोनों पक्षों के रिश्तों में खटास का सिलसिला इतना पुराना है कि दोनों तरफ के लोग इसको संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं. इस पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि यह समझौता कितने दिनों तक कायम रह सकेगा या यह कि यह समझौता ईरान को परमाणु हथियार संपन्न देश बन जाने में कितने समय तक रोके रख सकता है? इस सवाल का जवाब देते हुए अमेरिकी ऊर्जा मंत्री अर्नेस्ट मोनिज़, जिन्होंने इस समझौते में अहम भूमिका निभाई थी, कहा कि यह समझौता किसी खास अवधि के लिए नहीं है, बल्कि हमेशा के लिए है.

दरअसल, पी 5 प्लस 1 के देशों का उद्देश्य यह था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को ऐसी अवस्था में ले जाया जाए, जहां से उसे परमाणु हथियार बनाने में कम से कम एक साल का समय लगे. समझौते में यूरेनियम संवर्धन में लगे सेंट्रीफ्यूज में दो-तिहाई कटौती की जाने की बात कही गई है, इस्तेमाल में न आने वाले सेंट्रीफ्यूज और देश के सभी परमाणु केन्द्र आईएईए नियमित रूप से निरीक्षण में रहेंगे. साथ ही इस बात पर भी सहमती बन गई है कि ईरान के अरक के परमाणु संयंत्र को दोबारा डिजाइन किया जाएगा. हालांकि अमेरिका ओबामा प्रशासन से जुड़े लोग भी इसको संदेह की नज़र से देख रहे हैं कि कहीं आर्थिक प्रतिबन्ध हटाने की वजह से हुए आर्थिक लाभ को ईरान के कट्टरपंथी क्षेत्र के आतंकी संगठनों को मज़बूत करने में न लगा दें.

तेहरान ने अंतरिम समझौते के कुछ समय बाद ही यह कहना शुरू कर दिया कि जब तक उस पर से सभी प्रतिबन्ध पूरी तरह से उठा नहीं लिए जाते, तब तक वह असल समझौते पर दस्तखत नहीं करेगा, फिर भी तेहरान इस समझौते को लेकर आशान्वित है. उसे उम्मीद है कि इसके बाद देश पर लगे कठिन आर्थिक प्रतिबन्ध समाप्त हो जाएंगे और ईरान की अर्थव्यवस्था विदेशी विनेवेश के लिए खुल जाएगी, जिसकी वजह से आम लोगों की ज़िन्दगी में सुधार आएगा.

भारत और ईरान के सम्बन्ध हमेशा से मधुर रहे हैं, लेकिन ईरान पर आर्थिक प्रतिबन्ध के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार पर एक तरह से विराम लग गया था. भारत चीन के बाद ईरान का सबसे बड़ा तेल आयातक देश था, लेकिन आर्थिक प्रतिबन्ध के बाद और अमेरिका के दबाव में भारत ने तेहरान से आयात किए जाने वाले तेल की मात्रा में काफी कटौती की. भारत के मुताबिक, उसके ऊपर ईरान का 8.8 अरब डॉलर बाकी है, जिसे भारत को लौटाना है. ज़ाहिर है, इस प्रतिबन्ध के उठने के बाद दोनों देशों एक बीच व्यापार फिर से पटरी पर आ जाएगा और भारतीय कंपनियों को ईरान में निवेश का अवसर भी प्राप्त होगा.

अब रही बात इस समझौते से क्षेत्र की भू-राजनीति के प्रभावित होने की, तो वह भी एक जटिल मसला है. सद्दाम हुसैन के शासन के खात्मे के बाद और अरब स्प्रिंग के बाद की स्थिति में मध्य पूर्व की सियासत पर ईरान का प्रभाव बढ़ा है, जिसकी वजह से सऊदी अरब और दूसरे सुन्नी बहुल अरब देश चिंतित हैं. वहीं इजराइल ने भी इस समझौते का कड़े शब्दों में विरोध करते हुए कहा है कि इसकी वजह से इजराइल के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा. इजराइल ने इस समझौते में ईरान द्वारा इजराइल को मान्यता देने की शर्त रखने को भी कहा है, जिसे फ़िलहाल अमेरिका ने यह कह कर ख़ारिज कर दिया कि इजराइल की मान्यता एक अलग मुद्दा है.

हालांकि आधिकारिक तौर पर सऊदी अरब ने इस समझौते का स्वागत किया है, लेकिन वहां से यह चिंता व्यक्त की जा रही है कि प्रतिबन्ध हटने के बाद ईरान क्षेत्र की स्थिरता का फ़ायदा उठा कर इराक, यमन और सीरिया में अपने प्रभाव बढ़ाएगा, जो क्षेत्र में शांति के लिए ठीक नहीं है. ईरान-अमेरिका संबंधों में अगर सुधार होता है, तो इसका प्रभाव दक्षिण एशिया के सामरिक संतुलन पर भी पड़ सकता है और अफ़ग़ानिस्तान में सप्लाई के लिए नाटो को पाकिस्तान पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा. कुल मिला कर देखा जाए, तो इस समझौते से जहां ईरान के लिए विकास के नये दरवाज़े खुल जाएंगे, वहीं इससे सामरिक असंतुलन का भी खतरा पैदा हो जाएगा, लेकिन जब तक समझौता हो नहीं जाता, तब तक इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी.■

feedback@chauthiduniya.com

भिश्ती को टूटे हुए घड़े पर बहुत तरस आया. उसके हृदय में दया और करूणा थी. उसने प्यार से टूटे हुए घड़े से कहा, आज जब हम पानी लेकर वापस आयेंगे तब तुम रास्ते में खुबसूरत फूलों को ध्यान से देखना. चढ़ते सूरज की रोशनी में यह फूल कितने अच्छे लगते हैं और उस दिन टूटे हुए घड़े ने देखा कि सारे रास्ते के किनारे बहुत ही सुन्दर रंगबिरंगे फूल खिले हुए थे. उन लाल नीले पीले फूलों को देख कर उसका दुखी मन कुछ समय के लिये अपना दुख भूल गया. लेकिन मालिक के घर पहुंचते ही वह फिर उदास हो गया. उसे बुरा लगा कि फिर इतना पानी टपक गया था. नम्रतापूर्वक टूटे हुए घड़े ने फिर भिश्ती से माफी मांगी.

साई ज्ञानज्योति स्वरूप हैं

चौथी दुनिया ब्यूरो

ईश्वर अवतार का ध्येय साधुजनों का परित्राण और दुष्टों का संहार करना ही है. लेकिन संतों का कार्य तो सर्वथा भिन्न ही है. सन्तों के लिए साधु और दुष्ट प्राय:एक समान ही है. यथार्थ में उन्हें दुष्कर्म करने वालों की प्रथम चिन्ता होती है और वे उन्हें उचित पथ पर लगा देते है. सन्तों के हृदय में भगवान श्रीहरि विष्णु निवास करते है. वे उनसे पृथक नहीं हैं. साई भी उसीकोटि में हैं, जो कि भक्तों के कल्याण के निमित्त ही अवतीर्ण हुए थे. वे ज्ञानज्योति स्वरुप थे और उनकी दिव्यप्रभा अपूर्व थी. उन्हें समस्त प्राणियों से समान प्रेम था. वे निष्काम तथा नित्यमुक्त थे. उनकी दृष्टि में शत्रु, मित्र, राजा और भिक्षुक सब एक समान थे. भक्तों के लिये उन्होंने अपना दिव्य गुणसमूह पूर्णत: प्रयोग किया और सदैव उनकी सहायता के लिये तत्पर रहे.

नासिक के एक मर्मनिष्ठ, अग्निहोत्री ब्राह्मण थे, जिनका नाम मुले शास्त्री था. उन्होंने 6 शास्त्रों का अध्ययन किया था और ज्योतिष तथा सामुद्रिक शास्त्र में भी पारंगत थे. वे एक बार नागपुर के प्रसिद्ध करोड़पति श्री बापूसाहेब बूटी से भेंट करने के बाद अन्य सज्जनों के साथ बाबा के दर्शन करने मस्जिद में गये. बाबा ने फल बेचने वाले से अनेक प्रकार के फल और अन्य पदार्थ खरीदे और मस्जिद में उपस्थित लोंगों में उनको वितरित कर दिया. बाबा आम को इतनी चतुराई से चारों ओर से दबा देते थे कि चूसते ही सम्पूर्ण रस मुंह में आ जाता तथा गुठली और छिलका तुरन्त फेंक दिया जा सकता था. बाबा ने केले छीलकर भक्तों में बांट दिये और उनके छिलके अपने लिये रखलिये. हस्तरेखा विशारद होने के नाते, मुले शास्त्री ने बाबा के हाथ की परीक्षा करने की प्रार्थना की. लेकिन बाबा ने उनकी प्रार्थना पर कोई ध्यान न देकर उन्हें चार केले दिये इसके बाद सब लोग बाड़े को लौट आये. अब मुले शास्त्री ने स्नान किया और पवित्र वस्त्र धारण कर अग्निहोत्र आदि में जुट गए. बाबा भी अपने नियमानुसार लेंडी को रवाना हो गये. जाते–जाते उन्होंने कहा कि कुछ गेरु लाना, आज भगवा वस्त्र रंगेंगे. बाबा के शब्दों का अभिप्राय किसी की समझ में न आया. कुछ समय के बाद बाबा लौटे. अब मध्याह बेला की आरती की तैयारियां प्रारम्भ हो गई थी. बाबा के आसन ग्रहण करते ही भक्तों ने उनकी

पूजा की. अब आरती प्रारम्भ हो गई. बाबा ने कहा, उस नये ब्राहमण से कुछ दक्षिणा लाओ. बूटी स्वयं दक्षिणा लेने को गये और उन्होंने बाबा का सन्देश मुले शास्त्री को सुनाया. वे सोचने लगे कि मैं तो एक अग्निहोत्री ब्राहमण हूं, फिर मुझे दक्षिणा देना क्या उचित है. माना कि बाबा महान संत है, लेकिन मैं तो उनका शिष्य नहीं हूं. फिर भी उन्होंने वे अपने कृत्य को अधूरा ही छोड़कर तुरन्त बूटी के साथ मस्जिद को गये. वे अपने को शुद्ध और पवित्र तथा मस्जिद को अपवित्र जानकर, कुछ अन्तर से खड़े हो गये और दूर से ही हाथ जोड़कर उन्होंने बाबा के ऊपर पुष्प फेंके. एकाएक उन्होंने देखा कि बाबा के आसन पर उनके कैलाश वासी गुरु घोलप स्वामी विराजमान हैं. अपने गुरु को वहां देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ. कहीं यह स्वप्न तो नहीं है. नही यह स्वप्न नहीं हैं. मैं पूर्ण जागृत हूं. लेकिन जागृत होते हुये भी, मेरे गुरु महाराज यहां कैसे आ पहुंचे. कुछ समय तक उनके

नासिक के एक मर्मनिष्ठ, अग्निहोत्री ब्राह्मण थे, जिनका नाम मुले शास्त्री था. उन्होंने 6 शास्त्रों का अध्ययन किया था और ज्योतिष तथा सामुद्रिक शास्त्र में भी पारंगत थे. वे एक बार नागपुर के प्रसिद्ध करोड़पति श्री बापूसाहेब बूटी से भेंट करने के बाद अन्य सज्जनों के साथ बाबा के दर्शन करने मस्जिद में गये.

मुंह से एक भी शब्द न निकला. उन्होंने अपने को चिकोटी ली और पुनः विचार किया. वे निर्णय न कर सके कि कैलाशवासी गुरु घोलप स्वामी मस्जिद में कैसे आ पहुंचे. फिर सब सन्देह दूर करके वे आगे बढ़े और गुरु के चरणों पर गिर हाथ जोड़ कर स्तुति करने लगे. दूसरे भक्त तो बाबा की आरती गा रहे थे, लेकिन मुले शास्त्री अपने गुरु के नाम की ही गर्जना कर रहे थे. फिर सब जातिपांति का अहंकार तथा पवित्रता और अपवित्रता की कल्पना त्याग कर वे गुरु के श्रीचरणों पर पुनः गिर पड़े. उन्होंने आंखें मूंद ली, परन्तु खड़े होकर जब उन्होंने आंखें खोलीं तो बाबा को दक्षिणा मांगते हुए देखा. बाबा का आनन्दस्वरुप और उनकी अनिर्वचनीय शक्ति देख मुले शास्त्री आत्मविस्मृत हो गये. उनके हर्ष का ठिकाना न रहा. उन्होंने बाबा को पुनः नमस्कार किया और दक्षिणा दी. मुले शास्त्री कहने लगे कि मेरे सब संशय दूर हो गये. आज मुझे अपने गुरु के दर्शन हुए. ■

feedback@chauthiduniya.com

साई के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुःख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वही नहीं है दूर.
10. मुझमें लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य-धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन–201301
ई–मेल feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

टीम इंडिया को बधाई

टीम इंडिया को बधाई! इसलिए नहीं कि सेमीफाइनल में आस्ट्रेलिया से हारने के पूर्व वह लगातार मैच जीती, बल्कि इसलिए कि आस्ट्रेलिया से हारने के कारण देश व विश्व को कई तरह से फायदा पहुंचा. सबसे बड़ा फायदा भारतीय विद्यार्थियों को पहुंचा यदि भारत मैच जीतता तो ठीक परीक्षा के सीजन में विद्यार्थीगण वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल मैच तक टीवी से चिपके रहते. इससे पेपर्स निश्चित रूप से प्रभावित होता. अब कम से कम चिन्तामुक्त होकर पढ़ाई शुरू कर दी हैं. इस मैच के हारने से सबसे अधिक खुश दुनिया व देश के स्वच्छ पर्यावरण के हिमायती हैं. क्योंकि मैच जीतने पर करोड़ों रूपयों के फटाके फूटते, धुआं उठता, कई जहरीलीं गैसें निकलती और पर्यावरण प्रदूषित हो जाता. इससे उनकी चिन्ता बढ़ना स्वभाविक था. लेकिन अब वे निश्चिंत हैं. इसके अलावा मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती फटाकों के चिथड़ों को समेटने में. सटोरियों पर शिकंजा कसने वाली खुफिया एंजेंसियां भी राहत का सांस ली, क्योंकि सबसे ज्यादा सट्टा भारत के फाइनल में पहुंचने पर लगता. तब इस पर अंकुश लगाना टेढ़ी खीर साबित होता. टीम इंडिया ने हारकर तथाकथित भविष्यवक्ता मछली को गलत साबित कर दिया और यह बड़ा संदेश दिया कि अपने कर्म पर विश्वास करो.

–सुरेश वाहने, दुर्ग, छत्तीसगढ़.

कहीं देर ने हो जाए

भुमि–अधिग्रहण बिल को लेकर मोदी सरकार की किरकिरी हो ही रही थी कि उसने अपने एक और मुफ्त दवा देने के वायदे से भी पलट गई. इसके पहले यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान 2012 में केन्द्र सरकार मुफ्त दवा देने का वाद किया था. पिछले साल 348 दवाओं को मुफ्त देने के वादे को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया. हांलांकि बाद में मुफ्त दवाओं को घटाकर इसमें सिर्फ 50 दवाओं को शामिल किया गया, अब यह स्कीम ही गायब हो गई. मोदी सरकार ने मुफ्त दवा देने के वादे को ठंडे बस्ते में डालकर आम जनता को बड़ा झटका दिया है. मोदी सरकार अपने द्वारा किए गए कई वादों से पलट चुकी है और उसने विपक्ष के हाथ में सरकार पर हमला करने का एक और हथियार थमा दिया है. इसी के साथ अब मोदी सरकार से भी लोगों को भरोसा कम हो रहा है. मोदी सरकार ने महंगाई, रोजगार और गरीबी जैसे अपने किसी वादे भी अमल करती नहीं दिख रही है. मोदी जी अपकी सरकार को दस महीने हो गए हैं अब तो जाग जाइए कहीं देर ने हो जाए.

–हेमन्त पांडेय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश.

कोई किसानों की भी तो सुने

भारत कृषि प्रधान देश है और यहां की जीडीपी में किसानों का महत्वपूर्ण योगदान है. अनके राज्यों में बारिश से फसलों को बहुत अधिक नुकसान हुआ है और जिसका बुरा असर देश के किसानों पर पड़ा है. फसलों को बर्बाद देखकर कुछ किसानों की सदमें में मौत हो गई तो कईओं ने आत्म हत्या कर मौत को ही गले लगा लिया. कर्ज के बोझ तले दबे किसानों के ऊपर प्रकृति ने जो कहर बरपाया उससे किसानों की तो उम्मीद ही खत्म हो गई, जो उम्मीद बची हुई थी उसे केन्द्र और राज्यों सरकारों ने तोड़ दिया. किसान आखिर जाए तो जा कहां. राज्य सरकारों की तो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमेशा रोना रोती हैं. लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने तो किसानों से बड़े–बड़े वादे किए थे, लेकिन वे भी उनको मरने के लिए छोड़ चुके हैं. क्योंकि सरकार ने किसानों को कर्ज के बोझ से उतारने की अभी तक कोई नीति नहीं बनाई है. प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि किसानों को तबाह होने से बचा लीजिए.

–समीर ओझा, बक्सर, बिहार.

पीड़ितों के साथ अन्याय है

कवर स्टोरी–यही न्याय है तो अन्याय क्या है (06 अप्रैल–12 अप्रैल 2015) पढ़ा. बेहद प्रभावित किया. संतोष भारतीय से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि 22 मई, 1987 की रात भारतीय मानवता के इतिहास की सबसे काली रातों में से एक है. उस रात को पीएसी ने भीड़ में से लोगों को उठाया और उन्हें गंगनहर के किनारे लाइन में खड़ा किया, गोली मारी और उनकी लाशों को नहर में बहा दिया. हत्या का पीएसी पर कोई झूठा आरोप नहीं है, यह तो उस रात की सच्चाई है. उनमें बचे लोगों ने बताया कि लोगों को किस तरह उस रात मौत के घाट उतार दिया गया. इतने गवाहों और सबूतों के बाद भी हिन्दुस्तान के न्याय को देखिए कि सभी दोषी कोर्ट से निर्दोष साबित हो जाते हैं और पीड़ितों को इतने सालों के इंतजार के बाद भी न्याय नहीं मिला. शायद गाज़ियाबाद के तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वी.एन. राय नहीं होते तो यह घटना देश के सामने भी नहीं आती. अपने आपको मसीहा बताने वाली सरकारों ने भी उनको उनके हाल पर छोड़ दिया. अब जनता भरोसा किस पर करे.

–मंजूर आलम, मेरठ, उत्तर प्रदेश.

जनता की आवाज

मैं चौथी दुनिया समाचार पत्र का नियमित पाठक हूं. जब तोप मुकाबिल हो संपादकीय राजनीतिक तंत्र को जिम्मेदार बनाने की जरूरत है. पढ़कर काफी अच्छा लगा कि चौथी दुनिया हाशिमपुरा हत्याकांड के पीड़ितों की शिद्दत के साथ अभी तक आवाज उठा रहा है. चौथी दुनिया समाचार पत्र ने हाशिमपुरा के पीड़ितों की आवाज उठाने वाला एक मात्र समाचार पत्र है. चौथी दुनिया समाचार पत्र एक साहसिक और असली मायने में कहें तो आज के दौर में जनता की आवाज है. चौथी दुनिया समाचार पत्र हमेशा से जनता से जुड़े मुद्दों को उठाता रहा है.

–राजाराम यादव, दरभंगा

लघु कथा

एक अधूरा घड़ा

बहुत समय पहले की बात है एक भिश्ती था. उसके पास दो घड़े थे. उन घड़ों को उसने एक लम्बे डंडे के दो किनारों से बांधा हुआ था. एक घड़ा था साबुत और सुन्दर लेकिन दूसरे घड़े में दरार थी. भिश्ती हर सुबह नदी तट पर जा कर दोनों घड़ों में पानी भरता और फिर लम्बा सफर तय कर ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर मालिक के घर जाता. जब तक वह वहां पहुंचता टूटे हुए घड़े में से आधा पानी रास्ते में ही बह जाता था. मालिक के घर तक डेढ़ घड़ा पानी ही पहुंचता था. टूटे हुए घड़े को अपनी बेबसी पर आंसू आते. वह जानता था कि जितना काम उसे करना चाहिये वह उससे आधा ही कर पाता है. एक दिन टूटा हुआ घड़ा अपनी नाकामयाबी को और सहन नहीं कर पाया और वह भिश्ती से बोला, मुझे अपने पर शर्म आती है मै अधूरा हूं. मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं. भिश्ती ने उससे पूछा, तुम्हें किस बात की शर्म है. आप इतनी मेहनत से पानी लाते है और मै उसे पूरा नहीं रोक पाता आधा रास्ते में ही गिर जाता है.

भिश्ती को टूटे हुए घड़े पर बहुत तरस आया. उसके हृदय में दया और करूणा थी. उसने प्यार से टूटे हुए घड़े से कहा, आज जब हम पानी लेकर वापस आयेंगे तब तुम रास्ते में खुबसूरत फूलों को ध्यान से देखना. चढ़ते सूरज की रोशनी में यह फूल कितने अच्छे लगते हैं और उस दिन टूटे हुए घड़े ने देखा कि सारे रास्ते के किनारे बहुत ही सुन्दर रंगबिरंगे फूल खिले हुए थे. उन लाल नीले पीले फूलों को देख कर उसका दुखी मन कुछ समय के लिये अपना दुख भूल गया. लेकिन मालिक के घर पहुंचते ही वह फिर उदास हो गया. उसे बुरा लगा कि फिर इतना पानी टपक गया था. नम्रतापूर्वक टूटे हुए घड़े ने फिर भिश्ती से माफी मांगी. तब वह भिश्ती टूटे हुए घड़े से बोला क्या तुमने ध्यान दिया कि रास्ते में वह सुन्दर फूल केवल तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर ही खिले हुए थे. मैं तुम्हारी इस कमजोरी के बारे में जानता था और मैने इसका फायदा उठाया. मैने फूलों के बीज केवल तुम्हारी तरफ ही बोये थे और हर सुबह जब हम इस रास्ते से गुजरते तो तुम इन पौधों को पानी देते थे. पिछले दो सालों से यही फूल मालिक के घर की शोभा बढाते हैं. तुम जैसे भी हो बहुत काम के हो

अगर तुम न होते तो मालिक का घर इन सुन्दर फूलों से सुसज्जित न होता. ईश्वर ने हम सब में कुछ कमियां दी है. हम सब उस टूटे अधूरे घड़े जैसे हैं पर हम चाहें तो हम इन कमजोरियों पर काबू पा सकते हैं. हमें कभी भी अपनी कमियों से घबराना नहीं चाहिये हमें एहसास होना चाहिये कि हममें क्या कमियां हैं और फिर उन कमजोरियों के बावाजूद हम अपने चारों तरफ खूबसूरती फैला सकते हैं खुशियां बांट सकते हैं. अपनी कमी में ही अपनी मजबूती ढूंढ़ सकते हैं.

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर–11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन–201301

कट्टरपंथियों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना ज़रूरी

अनंत विजय

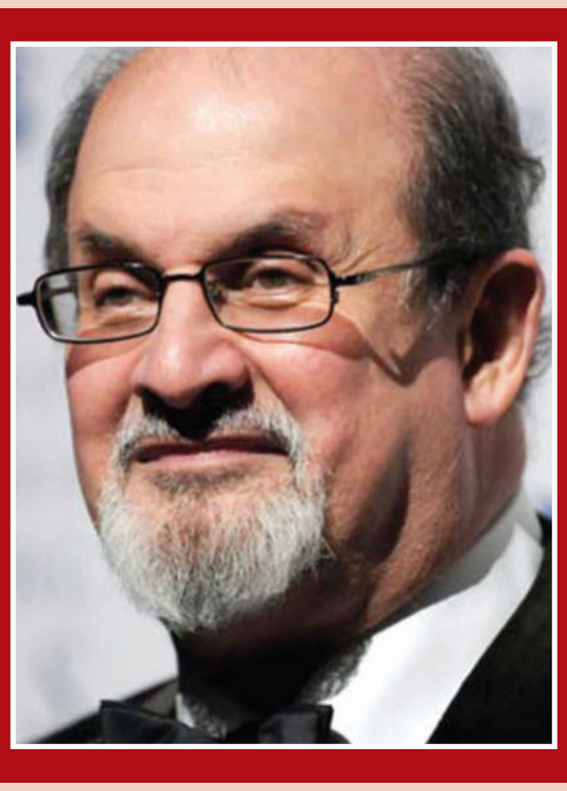

कोलकाता में एक बार फिर से धर्म के नाम पर हिंसा का खेल खेला गया. एक मदरसे के हेडमास्टर पर जानलेवा हमला किया गया. चिंता की बात तो यह है कि पुलिस की मौजूदगी में मदरसा परिसर में मासूम अख्तर नामक इस शख्स पर हमला होता रहा और पश्चिम बंगाल पुलिस खामोशी के साथ असहाय खड़ी रही. मासूम अख्तर का दोष सिर्फ़ इतना है कि उन्होंने बर्धवान धमाके को लेकर एक लेख लिखा था, जिसमें यह संकेत दिया गया था कि अगर किसी मदरसे से आतंकवाद की घटनाएं अंजाम दी जाती हैं या फिर वहां आतंकवादियों को पनाह दी जाती है, तो उसे भंग कर दिया जाना चाहिए. यही बात इस्लामी कट्टरपंथियों के गले नहीं उतरी और इस लेख के छपने के बाद मासूम अख्तर को धमकियां मिलने लगीं. फिर बहाना मिला ईशनिंदा का. अपनी एक कक्षा में मासूम अख्तर ने ऐतिहासिक संदर्भ में पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा को लेकर टिप्पणी की. वह टिप्पणी इस संदर्भ में थी कि बगैर किसी औपचारिक शिक्षा के पैगंबर ने दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाया. लेकिन, कट्टरपंथियों ने कक्षा में दिए गए मासूम के वक्तव्य को इस तरह से पेश कर दिया कि उन्होंने पैगंबर की शिक्षा पर सवाल खड़े किए. यह बात जंगल में आग की तरह फैली और फिर मासूम अख्तर के मदरसे में घुसकर कट्टरपंथियों ने उन पर लाठियों और सरियों से वार किया. अस्पताल में इलाज कराकर घर लौटे मासूम अख्तर को अब भी जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. वह सरकार से गुहार लगा रहे हैं, उन्हें कार्रवाई का भरोसा मिल रहा है, लेकिन स्तंभ लिखे जाने तक हमलावर आज़ाद घूम रहे हैं.

मासूम अख्तर को इस बात का डर है कि उनका हश्र भी बांग्लादेश के उन ब्लागरों जैसा न हो, जिन्हें पिछले दिनों कट्टरपंथियों ने मौत के घाट उतार दिया. इसके पहले भी ईशनिंदा के आरोप में पाकिस्तान के एक सूबे के गवर्नर को गोली मार दी गई थी. सलमान रुश्दी पर भी यही आरोप है और तस्लीमा पर भी. मासूम अख्तर को भी यही धमकी मिल रही है कि तुम सलमान रुश्दी बनना चाहते हो, तो सुधर जाओ, वर्ना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो. क्या यह अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला नहीं है? हमारा संविधान किसी भी नागरिक को अपनी बात कहने का हक़ देता है. इस हक़ की सीमा वहां तक है, जहां किसी को नुक़सान न पहुंचे या उसकी प्रतिष्ठा पर आंच न आए. अभी हाल के अपने फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 66-ए ख़त्म करते हुए भी कहा था कि संविधान में मिली अभिव्यक्ति की आज़ादी से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि आईटी एक्ट की धारा 66-ए से अभिव्यक्ति की आज़ादी बाधित होती है, लिहाजा उसने वह धारा रद्द कर दी. एक तरफ़ जहां सुप्रीम कोर्ट अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा के लिए भारत सरकार के क़ानून रद्द कर रहा है, वहीं दूसरी ओर एक शख्स अपने इस अधिकार की रक्षा के लिए दर-ब-दर भटक रहा है. पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की चुप्पी मासूम अख्तर के लिए जानलेवा साबित हो सकती है. उनकी जान ख़तरे में है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई क़ानून सम्मत काम करने के लिए आगे आना वाला नहीं. हमारे मजबूत होते लोकतंत्र के लिए यह बहुत ही चिंता का विषय है.

अब हम मासूम अख्तर के बहाने अगर इस बात की पड़ताल करें कि क्यों ममता बनर्जी सरकार इस पर सख्ती से पेश नहीं आ रही है, क्यों पश्चिम बंगाल पुलिस त्वरित कार्रवाई कर मासूम की जान की गारंटी नहीं दे पा रही है, क्यों हमलावरों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, क्यों हमलावरों की खुलेआम पैरोकारी करने वाले इमाम की गिरफ्तारी नहीं हो रही है? तो इन सवालों से मुठभेड़ करने पर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इसके पीछे वोट बैंक की राजनीति है. पश्चिम बंगाल की आबादी में से क़रीब 26 फ़ीसद हिस्सा मुसलमानों का है. कई लोकसभा और विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक स्थिति में हैं. इसी चुनावी गणित की वजह से पश्चिम बंगाल में राजनीतिक दल कट्टरपंथियों के ख़िलाफ़ मुंह खोलने की हिमाकत नहीं कर पाते. पश्चिम बंगाल वामपंथियों का गढ़ रहा है. वामपंथी हमेशा से अपने आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी के पैरोकार के तौर पर पेश करते रहे हैं. मकबूल फिदा हुसैन के चित्रों को लेकर जब विवाद उठा था, तो इन वामपंथियों ने आसमान सिर पर उठा लिया था. लेकिन, यही वामपंथी नेता, विचारक एवं लेखक उस वक्त खामोश रहे, जब पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन को वहां से निकाल दिया. वही वामपंथी नेता इस वक्त भी खामोश हैं, जब मासूम अख्तर अपनी जान बचाने के लिए भागे-भागे फिर रहे हैं. उस वक्त आसमान सिर पर उठा लेने वाली ममता बनर्जी जब सूबे की मुख्यमंत्री बनीं, तो वह तस्लीमा के मसले पर खामोश रहीं. तस्लीमा को अब भी पश्चिम बंगाल में क़दम रखने की इजाजत नहीं है, उनकी किताबें कोलकाता पुस्तक मेले में बेचे जाने पर अघोषित रोक है. अगर ग़लती से कोई प्रकाशक तस्लीमा की किताब बेचने लगता है, तो वहां हंगामा होता है या हंगामे की कोशिश होती है. तस्लीमा को पश्चिम बंगाल से बाहर करने को लेकर एक मौलाना खुलेआम गरजते हैं कि हां, उन्होंने बाहर किया तस्मीमा को. लेकिन, न तो वामपंथी नेता और न ममता बनर्जी उनका विरोध करते हैं, कार्रवाई की बात तो बहुत दूर. वामपंथियों के इसी चुनिंदा विरोध की वजह से उनकी साख रसातल में चली गई. राजनीति में उनके घटते समर्थन का असर साहित्य पर भी दिखा और साहित्य में वामपंथियों की गिरोहबंदी कमजोर पड़ती नज़र आने लगी. खैर, यह एक अवांतर प्रसंग है, जिस पर फिर कभी विस्तार से चर्चा होगी.

मासूम अख्तर के बहाने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और वह है, देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी का. क्या किसी भी शख्स को वाजिब सवाल उठाने पर जान से मार देने की धमकी मिलेगी या फिर उसे जान से मार दिया जाएगा? क्या भारत में भी कट्टरपंथियों के हौसले इतने बुलंद हो जाएंगे कि उन्हें क़ानून का खौफ नहीं रहेगा? क्या वोट बैंक की इस राजनीति को लोकतंत्र को कमज़ोर करने की इजाजत दी जा सकती है? इन सवालों के आलोक में देश भर में बहस होनी चाहिए. हमारा मानना है कि इस्लाम को मानने वाले सभी लोग कट्टरपंथी नहीं हो सकते. मासूम अख्तर जैसे विवादित मसलों पर मुसलिम बुद्धिजीवियों को सामने आना होगा, उन्हें सही तस्वीर पेश करनी होगी और अपनी राय से देश को अवगत कराना होगा. इस तरह के मसलों पर मुस्लिम बुद्धिजीवियों का खामोश रहना कट्टरपंथियों को मौन समर्थन देने जैसा है. इससे यह भी संदेश जाता है कि इस्लाम में कट्टरपंथ है, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं.

मासूम अख्तर के बहाने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और वह है, देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी का. क्या किसी भी शख्स को वाजिब सवाल उठाने पर जान से मार देने की धमकी मिलेगी या फिर उसे जान से मार दिया जाएगा? क्या भारत में भी कट्टरपंथियों के हौसले इतने बुलंद हो जाएंगे कि उन्हें क़ानून का खौफ नहीं रहेगा? क्या वोट बैंक की इस राजनीति को लोकतंत्र को कमज़ोर करने की इजाजत दी जा सकती है? इन सवालों के आलोक में देश भर में बहस होनी चाहिए. हमारा मानना है कि इस्लाम को मानने वाले सभी लोग कट्टरपंथी नहीं हो सकते. मासूम अख्तर जैसे विवादित मसलों पर मुसलिम बुद्धिजीवियों को सामने आना होगा, उन्हें सही तस्वीर पेश करनी होगी और अपनी राय से देश को अवगत कराना होगा. इस तरह के मसलों पर मुस्लिम बुद्धिजीवियों का खामोश रहना कट्टरपंथियों को मौन समर्थन देने जैसा है. इससे यह भी संदेश जाता है कि इस्लाम में कट्टरपंथ है, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं. अव्वल तो सभी लोगों को इस तरह के क़दमों और इस तरह की राजनीति का विरोध करना होगा, लेकिन अगर इसी धर्म को मानने वाले लोग अंदर से अपनी बात कहेंगे, तो उसका दूसरा असर होगा. देश के राजनीतिज्ञों को लगेगा कि मुसलमानों के बीच भी अलहदा सोच रखने वाले लोग हैं. इससे उन्हें यह भी संदेश जाएगा कि वोट बंट सकते हैं. इस संकेत के बाद संभव है कि वे कोई कार्रवाई कर सकें या कम से कम इस दिशा में कोई क़दम तो उठा सकें.

जिस तरह से मुस्लिम बुद्धिजीवियों से अपेक्षा की जाती है कि वे कट्टरपंथियों के ख़िलाफ़ बोलें और उठ खड़े हों, उसी तरह से सभी बुद्धिजीवियों को समान रूप से इस तरह की घटनाओं के विरोध में लिखना चाहिए या जिस भी तरीके से हो सके, विरोध जताना चाहिए. हमें यह ख़तरा उठाना ही होगा. दरअसल, हमारे देश के बौद्धिक जगत में वामपंथी विचारधारा के दबदबे ने इस तरह का माहौल बना दिया है कि अगर मुसलमानों के कट्टरपंथ के बारे में लिखोगे, तो आपको संघी करार दिया जाएगा और आपकी धर्मनिरपेक्षता पर सवाल खड़े होने लगेंगे. इसी माहौल की वजह से लेखक एवं विचारक इस तरह के मसलों पर बोलने से कतराते हैं. हिंदी के मशहूर लेखक राजेंद्र यादव तो हमेशा कहते थे कि मुसलमानों के मसले पर हम क्यों बोलें, वे खुद अपने मसलों पर बोलें. दरअसल, हमें इस सोच को बदलने की आवश्यकता है. सच को सच कहना ही होगा, वर्ना मासूम अख्तर जैसे शख्स दर-ब-दर भटकते हुए किसी दिन मार दिए जाएंगे और कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद होंगे तथा राजनेता उनकी कब्र पर वोटों की लहलहाती फसल देखकर खुश होते रहेंगे. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

जीवन का मूल स्वर है दर्द का कारवां

कुमार कृष्णन

आम जीवन का बेबाकी से जिक्र करना और उसकी विसंगतियों की सारी परतें खोल देना विवेक और चिंता की ऊंचाइयों का परिणाम होता है. आज जो साहित्य रचा जा रहा है, वह लेखन की कई शर्तें अपने साथ लेकर चल रहा है. एक तरफ़ जहां ज़िंदगी की गुनगुनाहट है, वहीं दूसरी तरफ़ जवानी को बुढ़ापे में तब्दील होने की जिद्द भी है. इन्हीं सब शर्तों के अनेक रंगों को अपनी ग़ज़लों में पिरोने का साहस डॉ. मालिनी गौतम ने किया है. यूं तो मालिनी गौतम साहित्य की अनेक विधाओं में लिखती हैं, लेकिन हाल में प्रकाशित उनका ग़ज़ल संग्रह-दर्द का कारवां वीरान ज़िंदगी के कब्रिस्तानों पर एक ओर जहां जीवन और मुहब्बत के गीत लिखता है, वहीं दूसरी ओर वर्तमान जीवन की विसंगतियों से लड़ने की ताकत भी देता है.

संग्रह की ग़ज़लों के रंग इंद्रधनुषी हैं, लेकिन सारी ग़ज़लों का मूल स्वर जीवन है और जीवन में घटने वाली घटनाओं का चित्रण है. इससे प्रतीत होता है कि डॉ. मालिनी गौतम ने अपनी ग़ज़लों को जिया ही नहीं है, बल्कि उन्हें भोगा भी है. जीना और भोगना, काई में वह पगडंडी है, जिस पर फिसलने का डर बना रहता है. मालिनी गौतम ने स्वयं को फिसलने नहीं दिया है और जो भी लिखा है, मजबूती के साथ और साफ़-साफ़ लिखा है. जैसे:-

इक पल रोना इक पल गाना, अजब तमाशा जीवन का.
हर दिन एक नया अफ़साना, अजब तमाशा जीवन का.

वासंती कुछ सपने हैं, इन शर्मीली आंखों में,
आशाओं के दीप जले, इन चमकीली आंखों में.

डॉ. मालिनी गौतम अपनी ग़ज़लों के माध्यम से पाठक को नव उत्साह और समय को सकारात्मक ढंग से लेने की सलाह देती हैं, न कि पाठक के कंधों को कमजोर करना चाहती हैं. उनकी ग़ज़लों का यह सकारात्मक रुख सूरज के साथ चलने की जिजीविषा और चांद की रोशनी को अपनी आंखों में भर लेने की छटपटाहट-सा है. जैसे:-

पड़े पैरों में हैं छाले, मगर मैं फिर भी चलता हूं,
कभी सहरा, कभी दरिया से अक्सर गुजरता हूं.

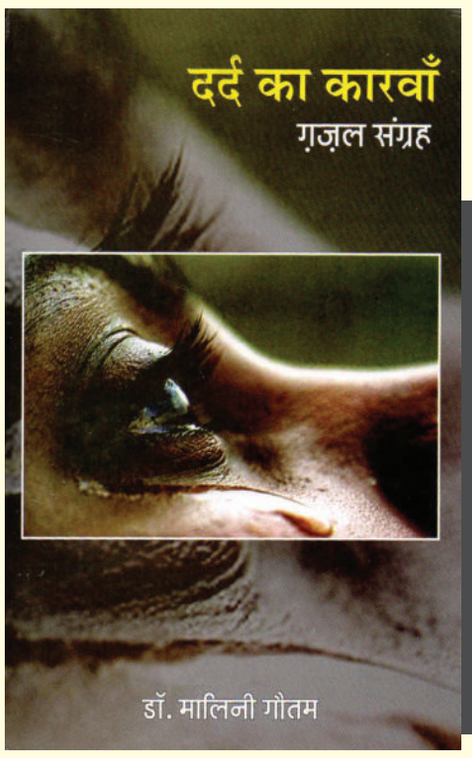

सच में उत्साह आदमी को किरदार की आईनासाजी का हुनर सिखाता है. यह हुनर मालिनी गौतम के लेखन का आत्मबल है. संग्रह की ग़ज़लें पढ़ने के बाद यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है. मालिनी गौतम की ग़ज़लों की दुनिया आम जीवन के आसपास घूमती है, लेकिन यह पूरे तौर पर नहीं कहा जा सकता कि मालिनी गौतम जीवन की दुनिया के बाहर नहीं निकलना चाहती हैं. उनके लेखन का कैनवास काफी बड़ा है. जीवन की हरेक आहट नए-नए दृश्यों को तलाश करती है, जिनमें भोर की पहली किरण के साथ हसीन उजालों की सुगबुगाहट मिलती है. विरह और वियोग का एक छटपटाता हुआ पन्ना भी खुलता है और उस पर बड़े सलीके से मुहब्बत का नाम लिखा जाता है:-

समीक्ष्य कृति
दर्द का कारवां (ग़ज़ल संग्रह)
ग़ज़लकार
डॉ. मालिनी गौतम
प्रकाशक
पहले पहल प्रकाशन, भोपाल, मध्य प्रदेश
मूल्य
150 रुपये

जुल्फों को रुख से हटाकर चल दिए,
चांद धरती पर दिखाकर चल दिए.

साहित्य में फटे हुए दूध को मालिनी गौतम रबड़ी नहीं कहतीं, बल्कि वह साहित्य की तमाम खूबियों और छंदों की रस्में निभाती हैं, जिसके चलते उनकी ग़ज़लें पठनीय और असरदार हो जाती हैं. पूरे विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि दर्द का कारवां की ग़ज़लें पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल होंगी. संग्रह की ग़ज़लें पठनीय और शिल्प के लिहाज से मुकम्मल हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

> फ्री जॉब अलर्ट इस्तेमाल करने में बेहद आसान है. इसे इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही कोई नया जॉब अलर्ट आता है यह आपके मोबाइल फोन पर उसका अलर्ट भेज देगा. इसमें जॉब्स को अलग–अलग कटैगरी में रखा गया है. आपकी योग्यता, लोकेशन और जॉब कटैगरी में बांटा गया है. इस ऐप को यूजर्स ने 5 में से 4.1 रेटिंग दी है.

आ गया गूगल का हिंदी वॉयस सर्च सर्विस

श्याम सुन्दर प्रसाद

अगर आपकी अंग्रेजी कमजोर हैं या आपको अंग्रेजी में कुछ भी सर्च करने में कठिनाई होती है, तो आपके लिए खुशखबरी है. क्योंकि गूगल ने तीस करोड़ हिंदी भाषी लोगों को इंटरनेट से जोड़ने के मकसद से इंडियन लैंग्वेज इंटरनेट अलायन्स (Indian Language Internet Alliance) को शुरू करने का फैसला किया है. गूगल के सहयोगी के रूप में कंटेंट प्रदान करने के लिए हिन्दी के कई नामी समाचार पत्र, समाचार चैनल और सरकारी एजेंसियां शामिल हैं. फिलहाल अंग्रेजी में वॉयस सर्च उपलब्ध करा रही गूगल ने हिन्दी भाषा में भी वॉयस सर्च सर्विस को जोड़ा है. हिन्दी के साथ–साथ दूसरी भाषाओं जैसे तमिल, मराठी और बंगाली गूगल की सूची में हैं. गूगल इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजन आनंदन की माने तो–भारत में करीब 20 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता हैं और हर महीने मोबाइल के माध्यम से करीब 50 लाख नए उपभोक्ता जुड़ रहे हैं. यह रफ्तार अगर यू ही बरकरार रही तो भारत आने वाले एक साल में अमेरिका को गूगल के प्रयोग में पीछे छोड़ देगा, उन्होंने यह भी बताया कि भारत में सिर्फ 19.8 करोड़ लोगो के ही अंग्रेजी में दक्ष होने का अनुमान है. इनमें से ज्यादातर इंटरनेट से जुड़े हुए हैं इसे ध्यान में रखकर इंडियन लैंग्वेज इंटरनेट अलायन्स (ILIA) का गठन किया गया है यह गठबंधन देश में भारतीय भाषाओं के इंटरनेट यूजर के लिए मिलकर कंटेंट तैयार करेगा.

इसके लिए गूगल ने एक आधिकारिक वेबसाइट www.hindiweb.com को भी लांच किया है. अगर इंटरनेट भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगा तो इसके उपभोक्ता में काफी बृद्धि हो सकती है और इससे सरकार की देश को डिजिटल इंडिया के सपनों को साकार करने में थोड़ी मदद भी मिलेगी.

भारत में करीब 20 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता हैं और हर महीने मोबाइल के माध्यम से करीब 50 लाख नए उपभोक्ता जुड़ रहे हैं. यह रफ्तार अगर यू ही बरकरार रही तो भारत आने वाले एक साल में अमेरिका को गूगल के प्रयोग में पीछे छोड़ देगा, उन्होंने यह भी बताया कि भारत में सिर्फ 19.8 करोड़ लोगो के ही अंग्रेजी में दक्ष होने का अनुमान है.

नोटपैड में हिंदी वर्ड को कैसे सेव करें

अपने कम्प्यूटर या लैपटॉप में जैसे ही आप नोटपैड में हिंदी का कोई वाक्य या पैराग्राफ सेव करने की कोशिश करते हैं तो हिन्दी वाक्य के स्थान पर प्रश्न चिन्ह जैसा निशान दिखता है. जिस हिंदी वर्ड को नोटपैड में हम दोबारा पढ़ नहीं पाते हैं. उस समस्या का बहुत छोटा सा हल है, जिसका प्रयोग कर आप हिंदी वाक्य को नोटपैड में सेव कर सकते हैं और फिर दोबारा पढ़ भी सकते हैं.

इसके लिए आप जब भी कोई हिन्दी वाक्य या पैराग्राफ नोटपैड में सेव करते हैं, तो सेव करते समय हमें तीन ऑप्शन दिखता है, जिसमें हम पहले फाइल का नाम हम लिखते हैं और दूसरे में डॉट टी एक्स टी (.txt) होता है जो कि नोटपैड का फाइल एक्सटेंशन होता है और तीसरा Encoding का ऑप्शन होता है जिसमें चार ऑप्शन होते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट रूप से ANSI चयनित रहता है. आप उसको छोड़ किसी दूसरे ऑप्शन जैसे Unicode, unicode big endia या UTF-8 में से किसी एक को चुने और अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर दें. अब आपका लिखा हुआ हिंदी का वाक्य या पैराग्राफ सेव हो जायेगा जिसको आप दोबारा पढ़ सकते हैं.

वयस्क कंटेंट सर्च को ब्लॉक करें

वयस्क कंटेंट को ब्लॉक करने की क्यों जरुरत है यह तो हम सभी जानते हैं. अगर आप चाहते हैं कि सर्च करने पर आपके कम्प्यूटर में वयस्क कंटेंट या उससे रिलेटेड वेबसाइट न ही दिखाई दें और न ही ओपन हो तो उसके लिए आप इस तरीके को अपना सकते हैं. यह बहुत ही आसान है और सबसे बड़ी बात तो यह है की आपको इसके लिए न तो किसी सॉफ्टवेयर की जरुरत है, न ही किसी एक्सटेंशन की और न ही किसी प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट होने की. इसे हटाकर कोई आपके अनुमति के बिना वयस्क कंटेंट नहीं सर्च कर सकता है. इस तरीके को अपनाने के बाद केवल आप इसे खोल और बंद कर सकते हैं. अपने कम्प्यूटर में व्यस्क कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए आप सबसे पहले गूगल सर्च बॉक्स में search setting लिख कर सर्च करें फिर सर्च सेटिंग में जाएं या http://www.google.com/preferences इस लिंक को टाइप करने के बाद आप सीधे सर्च सेंटिंग में जा सकते हैं. फिर वहां पर आप लॉक सेफ सर्च (Lock safe search) ऑप्शन पर क्लिक करें. उसके बाद आप अपने गूगल अकाउंट/जीमेल के यूजर नाम और पासवर्ड का प्रयोग कर लॉग इन करेंगे. उसके बाद एक स्क्रीन आएगा उसमें आप सेफ सर्च बटन पर क्लिक कर दें. उसके बाद आपको कुछ समय लगेगा फिर यह लॉक हो जायेगा. अब आपके कम्प्यूटर में ब्राउजर कोई वयस्क कंटेंट/साईट नहीं सर्च करेगा. यह सिर्फ गूगल में ही नहीं आपके ब्राउज के सारे सर्च इंजन में भी ब्लॉक हो जायेगा. कोई चाहकर भी वयस्क कंटेंट नहीं सर्च कर सकता, क्योंकि इसमें आपके जीमेल अकाउंट से लॉग इन हुआ है. सेफ सर्च को हटाने के लिए भी उसी अकाउंट से दोबारा लॉग इन करना पड़ेगा और सेफ सर्च को अनलॉक करना पड़ेगा, जो सिर्फ

आप कर सकते हैं. आपका सेफ सर्च एक्टिव है की नहीं उसकी जांच करने के लिए आप सर्च करते समय देखें की राइट साइड में सबसे ऊपर चार पांच गुब्बारे दिख रहें या नहीं. अगर आपको यह नहीं दिख रहा है तो समझिए आपका सेफ सर्च एक्टिव नहीं हुआ है. यदि आप सीधा लिंक यूआरएल में डालेंगे तो वो साइट खुल जायेगा. ■

smart7973@gmail.com

सुजुकी की जिक्सर एसएफ़ बाइक

सुजुकी इंडिया ने अपनी महत्वपूर्ण मोटरसाइकिल जिक्सर पूर्ण फेयर्ड एडिशन जिक्सर एसएफ लॉन्च किया है. जिक्सर एसएफ में एरोडायनामिक फुल स्पोर्ट फेयरिंग है. यह फेयरिंग बाइक चालक को अधिकतम प्रोटेक्शन देने, अस्थिरता और खिंचाव में कमी लाने के लिए डिजाइन की गई है. इससे बाइक को बेहतर एरोडायनामिक क्षमता मिलती है. इसका सीधा फायदा ब्रेक लगाने में स्थिरता और अधिक स्पीड होने पर बेहतर नियंत्रण के लिए खिंचाव में कमी के रूप में मिलता है. नई जिक्सर एसएफ के अत्याधुनिक दिखने वाले एल्युमिनियम एक्जॉस्ट एंड कवर से लेकर क्लियर लेंस इंडिकेटर्स तक प्रत्येक फीचर बाइक को स्पोर्टी और प्रीमियम लुक देता है. पहियों पर मौजूद पिनस्ट्राइप इन्हें फुर्तीला और पैना दिखाता है जो सभी मोटरसाइकिल प्रेमियों को अवश्य आकर्षित करेगा. यह 155 सीसी इंजन और 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ है और जिक्सर एसएफ के चमकीले फेयरिंग के नीचे होता है और आसाधारण रनिंग परफॉर्मेंस देता है, जिसके साथ मजबूत एक्सिलरेशन के लिए ब्रांड लो–एंड टॉर्क और डायनामिक मिड–रेंज पॉवर मिलता है. यह बाइक स्पार्कल ब्लैक और पर्ल मिराज वाइट रंगों में उपलब्ध होगी, जिसकी कीमत 83,889 रुपये होगी. ■

एचटीसी का स्मार्टफोन डिज़ायर 826

एचटीसी ने भारत में अपने नए मेगा बजट फोन को लॉन्च किया है. यह ऑक्टा कोर प्रोसेसर से लैस है. साल की शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस 4जी फोन को लॉन्च करने वाली कंपनी ने पिछले दिनों चीन के बाजार मउतारा था. फोन में 13 मेगापिक्सल का रीयर और 4 अल्ट्रापिक्सल का फ्रंट कैमरा लगा है. फोन की मोटाई सिर्फ 8एमएम है, जबकि इसका वजन 183 ग्राम है. इस फोन का डिस्पले 5.5 इंच का है जो 1080 गुणा 1920 पिक्सल का रेजोल्यूशन देता है. यह एंड्रॉयड लॉलीपॉप 5.0.1 पर आधारित है. यह क्वॉड कोर 1.7 गीगाहर्ट्ज कोरटेक्स 53 से लैस है. इसमें 2 जीबी रैम और इसमें इंटरनल मेमोरी 16 जीबी है. इसकी बैटरी 2600 एमएएच की है. इस फोन की कीमत 25,990 रुपये रखी गई है. ■

फोन की मोटाई सिर्फ 8एमएम है, जबकि इसका वजन 183 ग्राम है. इस फोन का डिस्पले 5.5 इंच का है जो 1080 गुणा 1920 पिक्सल का रेजोल्यूशन देता है. यह एंड्रॉयड लॉलीपॉप 5.0.1 पर आधारित है. यह क्वॉड कोर 1.7 गीगाहर्ट्ज कोरटेक्स 53 से लैस है.

माइक्रोसॉफ्ट ने टैबलेट सरफेस 3 लॉन्च किया

माइक्रोसॉफ्ट ने सरफेस टैबलेट का छोटी स्क्रीन वाला सस्ता वर्जन सरफेस 3 लॉन्च किया है. नए डिवाइस की स्क्रीन 10.8 इंच की है. इससे पहले के सरफेस वर्जन की स्क्रीन 12 इंच की थी. माइक्रोसॉफ्ट के सरफेस डिवीजन के हेड पनोस पनय का कहना है कि सरफेस 3 में सरफेस प्रो 3 की वे चीजें हैं जिन्हें लोगों ने पसंद किया है. हमारी कोशिश है कि कम कीमत में प्रीमियम डिजाइन और प्रोडक्विटी वाला डिवाइस दे सकें. नए सरफेस में हाईस्पीड कनेक्शन के साथ वायरलेस कैरियर से कनेक्ट करने की भी सुविधा है. माइक्रोसॉफ्ट इसका प्रचार लैपटॉप का विकल्प बताते हुए कर रहा है. इसकी कीमत लगभग 31 हजार रुपये से शुरू होगी. ■

जॉब ओपनिंग की जानकारी देने वाला एप

नौकरी की तलाश में हैं या फिर अभी कॉलेज पास आउट हुए हैं तो फ्री जॉब अलर्ट ऐप डाउनलोड करें. यह ऐप सरकारी नौकरी से लेकर बैंक में जॉब दिलाने में आपकी मदद करेगा. यह ऐप सरकारी नौकरी, फ्रेशर जॉब, बैंकिंग जॉब, प्राइवेट जॉब, रेलवे, डिफेंस या किसी भी सेक्टर में आए जॉब वैकेंसी से आपको आवगत कराता है. फ्री जॉब अलर्ट इस्तेमाल करने में बेहद आसान है. इसे इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही कोई नया जॉब अलर्ट आता है यह आपके मोबाइल फोन पर उसका अलर्ट भेज देगा. इसमें जॉब्स को अलग–अलग कटैगरी में रखा गया है. आपकी योग्यता, लोकेशन और जॉब कटैगरी में बांटा गया है. इस ऐप को यूजर्स ने 5 में से 4.1 रेटिंग दी है. 3.3 चइ साइज वाले इस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए आपके फोन में 2.2 से ज्यादा का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए. ■

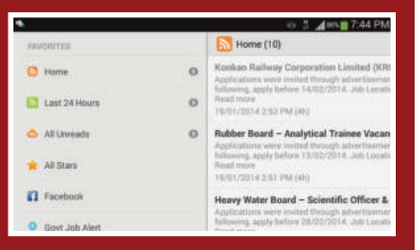

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

विश्व शिखर पर भारतीय खिलाड़ी

नवीन चौहान

ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारतीय बैडमिंटन स्टार सायना नेहवाल ने हाल ही में विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में नंबर एक पर पहुंचकर इतिहास रचा. वह विश्वरैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला और दूसरी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं. उनसे पहले प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन की विश्व रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थे. टेनिस सनसनी सानिया मिर्ज़ा भी विश्व रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंचने की कगार पर पहुंच गई हैं. विश्व की नंबर एक खिलाड़ी बनने के बाद सायना ने कहा है कि रैंकिंग उनके लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है, लेकिन हर खिलाड़ी अपने करियर में दुनिया का नंबर एक खिलाड़ी बनना चाहता है. रैंकिग से आपके प्रदर्शन की कंसिस्टेंसी प्रदर्शित होती है. सायना के लिए साल–2015 बहुत बेहतरीन रहा है. पहले तो वह वह ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचीं. जहां वह कार्लीना मरीन से पार नहीं पा सकीं. इसके बाद दिल्ली में उन्होंने इंडियन ओपन सुपर सीरीज का खिताब जीता, इसी जीत की वजह से वह विश्व रैंकिंग में पहला नंबर तक पहुंचने में सफल हुईं. हालांकि, वह ज्यादा दिनों तक नंबर एक की पोजीशन पर नहीं रह पाईं. विश्व की नंबर एक खिलाड़ी बनने के महज एक सप्ताह बाद ही उन्हें मलेशियन ओपन के सेमी–फाइनल में चीनी खिलाड़ी से मात मिली और उनसे विश्व नंबर एक का खिताब छिन गया. फिलहाल सायना नंबर दो पर हैं, यदि वह ऐसा शानदार प्रदर्शन करती रहीं तो निश्चित तौर पर दोबारा नंबर एक की पोजीशन हासिल करने में कामयाब होंगी. सायना इस बात से खुश हैं कि वह लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं, यह उनके कठिन परिश्रम का नतीजा है. मुझे इस बात का दुःख है कि मैं लंबे समय तक नंबर वन पर नहीं बनी रह सकी, लेकिन मैं नंबर वन पर वापस पहुंचने की पुरजोर कोशिश करूंगी. मैं टॉप रैंक चीनी खिलाड़ियों को हराने में सफल रही हूं, यदि आगे भी यह सिलसिला चलता रहा तो मैं एक बार फिर विश्व की नंबर एक खिलाड़ी बन जाउंगी.

यह बात जग जाहिर है कि भारत में खेल कभी भी लोगों की वरीयता में नहीं रहे. देश के अधिकांश खिलाड़ियों ने संघर्ष करके ही खेलों की दुनिया में अपना अलग मुकाम बनाया और सफलता की ऊंचाइयों को छुआ. इसी तरह चुनौतियों का सामना करते हुए कई भारतीय खिलाड़ी अलग–अलग खेलों में नंबर एक की पोजीशन हासिल की आइये ऐसे ही कुछ खिलाड़ियों पर नज़र डालते हैं.

navinonline2003@gmail.com

महेंद्र सिंह धोनी

दुनिया भर में कैप्टन कूल और सर्वश्रेष्ठ फिनिशर के रूप में जाने–जाने वाले भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एक दिवसीय रैंकिंग में पहले पायदान पर रहे हैं. धोनी ने साल 2006 में वन–डे रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल की थी. एक दिवसीय फॉर्मेट के बेहद उम्दा खिलाड़ी हैं. उन्हें साल 2008 और 2009 में आईसीसी का वन–डे प्लेयर ऑफ द इयर घोषित किया गया था. 2010 में वह एक बार फिर वन–डे रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचे थे.■

जीतू राय

10 मीटर एयर रायफल स्पर्धा के विश्व के नंबर एक खिलाड़ी जीतू राय को अभिनव बिंद्रा का उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है. साल 2014 में जीतू राय ने धमाकेदार प्रदर्शन किया और विश्व कप में स्वर्ण पदक हासिल किया. इसके बाद म्यूनिख में हुई स्पर्धा में उन्होंने दो रजत पदक पर निशाना लगाया. उन्होंने 2014 में एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में देश को स्वर्ण पदक दिलवाये. अपनी सफलताओं के बारे में उनका कहना है कि हर खिलाड़ी को अपनी रैंकिंग मेंटेन करने या सुधार के लिए लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करना होता है और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है. मैं भी ऐसी कोशिश कर रहा हूं. ■

राहुल द्रविड़

क्रिकेट के मिस्टर परफेक्शनिस्ट के रूप में जाने जाने वाले भारतीय पूर्व भारतीय बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने टेस्ट रैंकिग में पहला स्थान हासिल किया था. वह 35 टेस्ट और 226 दिनों तक आईसीसी रैंकिंग में नंबर एक की पोजीशन पर रहे. द्रविड़ पहली बार साल 1998 में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी बने थे. उन्हें हटाकर सचिन तेंदुलकर रैंकिंग में पहले पायदान पर काबिज हुए थे. इसके छह साल बाद 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में दोहरा शतक लगाकर एक बार फिर नंबर एक रैंकिंग हासिल की थी. इसके बाद वह छह महीने तक दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी बने रहे. साल 2010 में वह एक बार फिर नंबर एक पर पहुंचे लेकिन इस बार जैक कैलिस ने उन्हें ज्यादा दिनों तक यहां नहीं रहने दिया.■

हिना सिद्धू

साल 2014 में भारत को निशानेबाजी का एक नया सितारा मिला. या कहें हिना सिद्धू को खेल जगत में एक नई पहचान मिली. उन्होंने विश्व रैंकिग में पहला स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया. उनके इस मुकाम तक पहुंचने के कारण उनके प्रदर्शन में निरंतरता थी. साल 2008 से लेकर अब तक दुनिया भर में कई खिताब जीते हैं. 2008 में हंगरी ओपन से लेकर 2014 की एशियाई चैंपियनशिप तक वह कई बार स्वर्ण पदक पर निशाना लगाने में सफल रहीं. इसके साथ ही उन्होंने साल 2014 में अमेरिका में आयोजित आईएसएसएफ शुटिंग चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया. हालांकि वह ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों और इंचियोन एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक नहीं जीत सकीं. उन्हें इन स्पर्धाओं में क्रमशः रजत और कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा.■

विश्वनाथन आनंद

शतरंज में भारत का पिछले दो दशक से प्रतिनिधित्व कर रहे विश्वनाथन आनंद भारत में शतरंज का पर्याय हैं. आनंद पांच बार विश्व चैंपियन का खिताब जीत चुके हैं और कई बार विश्वचैंपियनशिप के फाइनल में भी पहुंचे हैं. अपने करियर में वह कई बार नंबर एक के पायदान पर पहुंचे. कुल मिलाकर वह पूरे करियर में तकरीबन छह महीने तक विश्व के नंबर एक खिलाड़ी रहे हैं. वह पहली बार साल 2007 के अप्रैल महीने में जारी रैंकिंग में विश्व के नंबर एक शतरंज खिलाड़ी बने, अक्टूबर तक वह इस जगह पर बने रहे. इसके बाद व्लादिमिर कार्मनिक ने उन्हें पहले पायदान से हटाया. इसके बाद अप्रैल 2008 में उन्होंने फिर से नंबर एक रैंकिंग हासिल की और जुलाई तक पहली पोजीशन पर बने रहे और अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ 2803 रेटिंग अंक हासिल किये. इसके बाद बुलगारिया के वेसेलिन टोपोलोव ने आनंद को नंबर एक के स्थान से हटा दिया.■

सचिन तेंदुलकर

करियर में 200 टेस्ट खेलकर, टेस्ट रैंकिंग में 18 पायदान पर रहते हुए क्रिकेट को अलविदा कहने वाले क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल बल्लेबाज हैं. सचिन आईसीसी रैंकिंग में सबसे पहले 1994 में पहले स्थान पर काबिज हुए थे. वह तीन महीने तक नंबर एक पर रहे. उन्हें हटाकर ब्रायन लारा ने नंबर एक की गद्दी हासिल की थी. सन 1998 में सचिन सिडनी में 155 रन की पारी खेलने के बाद एक बार फिर टेस्ट के नंबर एक बल्लेबाज बन गए. साल 2000 में वह एक बार फिर आईसीसी रैंकिंग में पहले पायदान तक पहुंचे. साल 2002 में भी वह कुछ दिनों तक विश्व के नंबर एक खिलाड़ी रहे लेकिन इस बार एडम गिलक्रिस्ट ने उन्हें पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल कर लिया.सचिन अपने 24 साल लंबे टेस्ट करियर में 1157 दिनों तक आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर एक पर रहे. इसके अलावा सचिव एकदिवसीय रैंकिग में भी नंबर एक पर रहे. ■

रोंजन सिंह सोढ़ी

डबल ट्रैप शूटिंग के उस्ताद माने जाने वाले रोंजन सिंह सोढ़ी फिलहाल विश्व के नंबर एक ट्रैप शूटर हैं. विश्वकप जैसी अन्य स्पर्धाओं में सफल रहने के बावजूद सोढ़ी कभी भी ओलंपिक स्पर्धाओं में अपना जादू नहीं दिखा सके. वह पछले एक दशक से इस स्पर्धा के बेहतरीन खिलाड़ी हैं लेकिन ओलंपिक जैसी बड़ी स्पर्धा में वह हर बार चूक जाते हैं. सोढ़ी ने शूटिंग विश्व कप में साल 2010 और 2011 में डबल ट्रैप का स्वर्ण पदक हासिल किया और 2012 में बहुत थोड़े से अंतर से स्वर्ण पदक जीतने से रह गए. उन्हें देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, वह ग्वांग्जू एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जीते थे. ओलंपिक में सोढ़ी दीपिका कुमारी की तरह दबाव में आकर बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर सके और उन्हें छठवें स्थान से संतोष करना पड़ा. 2016 में रियो ओलंपिक में उनसे करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की आशा की जा रही है.■

लिएंडर पेस

टेनिस का ग्रैंडस्लैम खिताब जीतने वाले विश्व के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी लिएंडर पेस दो दशक से टेनिस में भारत की कमान संभाले हुए हैं. अपने करियर की शुरूआत में पेस टेनिस की जूनियर एकल रैंकिंग में नंबर एक पर पहुंचे थे. इसके बाद वह एकल स्पर्धाओं में लगातार भारत का प्रतिनिधित्व करते रहे और 100 श्रेष्ठ खिलाड़ियों में शामिल हुए, लेकिन इसके बाद उन्होंने युगल स्पर्धाओं में हमवतन महेश भूपति के साथ खेलना शुरू किया और सफलता की नई इबारत लिखनी शुरू की. वह जुलाई 1999 से फरवरी 2000 तक टेनिस की युगल रैंकिंग में नंबर एक पर रहे. पेस करियर में कई पार्टनर्स के साथ कोर्ट में उतरे. लेकिन भूपति के साथ खेलते हुए उन्होंने जो ऊंचाइंया छुईं, वहां तक दोबारा नहीं पहुंच सके. हाल ही में पेस ने अपने करियर का 15 वां ग्रैंड स्लैम खिताब मार्टीना हिंगिस के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिक्स डबल्स के रूप में जीता है.■

महेश भूपति

भारत के सर्वकालिक बेहतरीन टेनिस खिलाड़ियों में शुमार महेश भूपति ग्रैड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय हैं. भूपति ने अपने करियर में कुल 12 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते, लेकिन भूपति अपने करियर में केवल दो सप्ताह तक विश्व के नंबर एक खिलाड़ी बन सके. 1999 का साल पेस–भूपति की जोड़ी का सबसे यादगार साल था. टेनिस सर्किट में इंडियन एक्सप्रेस के नाम से मशहूर इन दोनों खिलाड़ियों की जोड़ी के दबदबे के बावजूद भूपति केवल दो सप्ताह तक विश्व के नंबर एक युगल खिलाड़ी बन सके, हालांकि वह पेस की तुलना में लंबे समय तक चोटी के दस खिलाड़ियों में शामिल रहे. कुल मिलाकर वह पूरे करियर में तकरीबन तीन साल तक दुनिया के टॉप टेन खिलाड़ियों में शामिल रहे. वह कई बार नंबर दो की पोजीशन तक पहुंचे लेकिन टॉप पोजिशन पर पहुंचने से चूक गए.■

दीपिका कुमारी

2012 के लंदन ओलंपिक में झारखंड की तीरंदाज दीपिका कुमारी भारत के लिए मेडल जीत सकने वाले खिलाड़ियों में से एक थीं. हालांकि वहां उन्हें पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा. फिलहाल वह विश्व रैंकिंग में 14 वें पायदान पर हैं. 2010 में दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों सहित अन्य स्पर्धाओं में बेहतरीन प्रदर्शन किया था और व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक हासिल किया था. इसके बाद ग्वांगजू एशियाई खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा का कांस्य पदक अपने नाम किया. इसके बाद इस्तांबुल में साल 2011 में और टोकियो में 2012 में आयोजित विश्वकप में रजत पदक हासिल किया. मई 2012 में अमेरिका के अटलांटा में तीरंदाजी की एकल रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने के बाद जून में जारी हुई रैंकिंग में दीपिका ने पहला स्थान हासिल किया था. वह विश्व नंबर एक में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय महिला तीरंदाज हैं, उनसे पहले डोला बनर्जी नंबर एक पर पहुंचीं थीं.■

प्रकाश पादुकोण

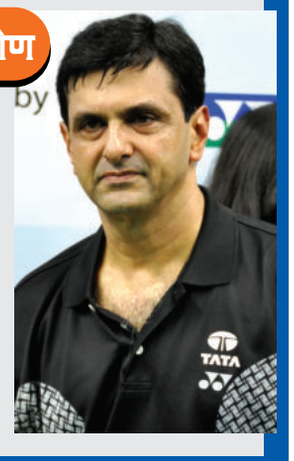

भारतीय बैडमिंटन को विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने वाले प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन की विश्व रैंकिग में नंबर एक पर पहुंचने वाले पहले भारतीय थे. बैडमिंटन का यह दिग्गज खिलाड़ी यदि नहीं होता तो शायद हमारे देश को पुलेला गोपीचंद और सायना नेहवाले जैसे खिलाड़ी आज देखने को नहीं मिलते. उनकी उपलब्धियों की वजह से ही इन खिलाड़ियों ने बैडमिंटन को करियर के रूप में अपनाया. वह ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं, उन्होंने साल 1980 में यह खिताब हासिल किया था. पादुकोण 1980 से 1983 के दरम्यान कई बार नंबर एक की पोजीशन पर रहे. उन्होंने 1981 में विश्वकप और 1978 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया था. पादुकोण का इन स्पर्धाओं का जीतना और इसके बाद नंबर वन बनना भारतीय बैडमिंटन जगत के लिए मील का पत्थर साबित हुआ.■

अगर अभिनेता मेरे फिल्म में होने की वजह से उसमें काम नहीं करना चाहते, तो मैं क्या कर सकती हूं? मैं इस विषय में कुछ नहीं कर सकती. जिंदगी में हर चीज के पीछे एक वजह से होती है. हां, मैं एक पॉर्न स्टार थी, लेकिन मैं अपने बीते समय को काटकर नहीं फेंक सकती.

हां, मैं एक पॉर्न स्टार थी सनी लियोनी

सनी बॉलीवुड की खान तिकड़ी यानी शाहरुख, सलमान और आमिर खान के साथ काम करना चाहती हैं. लेकिन सुनने में आया है कि खान तिकड़ी अभी सनी लियोन से दूरी बना कर रखना चाहती है. बॉलीवुड में सनी की डेब्यू फिल्म पूजा भट्ट की फिल्म जिस्म-2 थी. इस फिल्म के लिए सनी को रियलिटी शो बिग बॉस के घर जाकर ऑफर दिया था. इसके बाद सनी जैकपॉट और रागिनी एमएमएस-2 जैसी फिल्मों में नजर आईं.

बॉलीवुड में कदम रखने से पहले सनी लियोन एक पॉर्न स्टार थीं. आज भी इंटरनेट पर उनकी पॉर्न फिल्मों का ढेर लगा है. एक पहली लीला के प्रमोशन के दौरान उन्होंने यह बात स्वीकार की कि यह उनका पास्ट है, उन्हें इससे तकलीफ है. क्योंकि इसी वजह से बॉलीवुड के कई बड़े कलाकार उनके साथ स्क्रीन शेयर करने में हचक रहे हैं. कई अभिनेताओं ने उनके साथ काम करने से साफ इंकार कर दिया. लेकिन सनी को इस बात का अफसोस नहीं है वह केवल अपनी छवि बदलने में लगी हुई हैं. उन्हें लगता है कि फिल्म ***एक पहेली लीला*** उनके लिए इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगी.

सनी बॉलीवुड की खान तिकड़ी यानी शाहरुख, सलमान और आमिर के साथ काम करना चाहती हैं. लेकिन सुनने में आया है कि खान तिकड़ी अभी सनी लियोन से दूरी बना कर रखना चाहती है. बॉलीवुड में सनी की डेब्यू फिल्म पूजा भट्ट की फिल्म जिस्म-2 थी. इस फिल्म के लिए सनी को रियलिटी शो बिगबॉस के घर जाकर ऑफर दिया था. इसके बाद सनी जैकपॉट और रागिनी एमएमएस-2 जैसी फिल्मों में नजर आईं. सनी लैला तेरी ले लेगी, पिंक लिप्स और बेबी डॉल मैं सोने दी जैसे आइटम नंबर और टेलीविजन शो एमटीवी स्पिलट्स विला की वजह से एक जाना पहचाना चेहरा बन गईं. इन दिनों सनी अपनी फिल्म एक पहेली लीला को लेकर सुर्खियों में हैं. वह इस फिल्म में बोल्ड अंदाज में नजर आई हैं. फिल्म के प्रमोशन के दौरान सनी ने बताया कि मैं सलमान, शाहरुख और आमिर खान के साथ काम करना चाहती हूं. वे बहुत बड़े सितारे हैं. मैं शाहरुख से मिली हूं, वह बहुत भले आदमी हैं.

आमिर भी मेरी फेहरिस्त में हैं, अगर मुझे सलमान के साथ काम करने का एक मौका मिलता है, तो मैं ऐसा करना चाहूंगी. एक पहेली लीला के निर्देशक बॉबी खान लगातार इस बारे में बात करते आ रहे हैं कि कैसे कुछ नामी अभिनेताओं ने इस फिल्म में सनी के साथ काम करने से इंकार कर दिया था. 33 वर्षीय सनी के लिए यह यकीनन तकलीफदेह बात है, लेकिन वह कहती हैं, मैं इसे उस तरह नहीं देखती. अगर अभिनेता मेरे फिल्म में होने की वजह से उसमें काम नहीं करना चाहते, तो मैं क्या कर सकती हूं? मैं इस विषय में कुछ नहीं कर सकती. जिंदगी में हर चीज के पीछे एक वजह से होती है. हां, मैं एक पॉर्न स्टार थी, लेकिन मैं अपने बीते समय को काटकर नहीं फेंक सकती और ना मैं ऐसा करना ही चाहती हूं.■

दबंग-3 के लिए करना होगा इंतजार

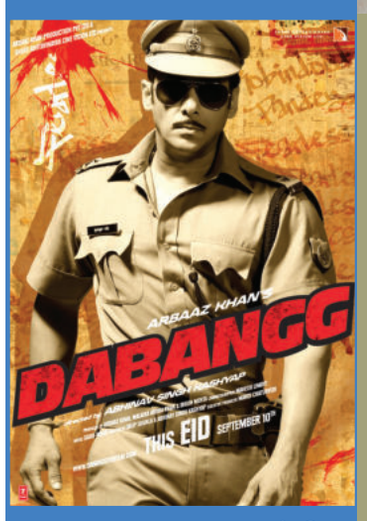

बॉलीवुड के दबंग सलमान खान अपने प्रशंसकों के लिए दबंग-3 लेकर आ रहे हैं. लेकिन फैंस को उनकी इस फिल्म के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा. इस फिल्म को बनाने को लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं. निर्देशक और अभिनेता

अरबाज खान का कहना है कि फिल्म को पूरी तरह से तैयार होने में तकरीबन दो साल लगेंगे. अरबाज ने 2010 में आई फिल्म दबंग के निर्माता थे. इसके बाद आई दबंग-2 के निर्माता और निर्देशक दोनों बन गए. फिल्म के बारे में पूछने पर अरबाज ने बताया कि फिलहाल सलमान अपनी फिल्मों के पेंडिंग असाइनमेंट में व्यस्त हैं. उन्होंने यह भी कहा कि दबंग-3 को लेकर पहले सलमान से चर्चा करनी होगी, इसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा. सलमान पहले ही अपने पुरानी फिल्मों बजरंगी भाई जान और प्रेम रतन धन पायो की शूटिंग में व्यस्त हैं. इसलिए उनके फैन्स को थोड़ा लंबा इंतजार करना होगा.■

शेरलॉक होम्स की तरह ब्योमकेश बख्शी

निर्देशक दिबाकर बनर्जी ने फिल्म ब्योमकेश बख्शी के रिलीज होने के कुछ ही दिनों बाद ही इसके सीक्वल की घोषणा कर दी. दिबाकर शेरलॉक होम्स की जासूसी की कहानियों पर आधारित फिल्मों की तर्ज पर ब्योमकेश बक्शी की कहानियों पर आधारित कई सीक्वल बनाने जा रहे हैं. हाल ही में रिलीज हुई इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत ने ब्योमकेश बख्शी की भूमिका निभाई है. उनके काम की बहुत तारीफ हो रही है. फिल्म की शुरूआती सफलता से उत्साहित दिबाकर ने कहा कि उनके पास अपनी इस फिल्म के सीक्वल की कहानी पहले से ही दिमाग में है. मैं डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी-2 बनाने के लिए बेहद उत्साहित हूं क्योंकि इस फिल्म में यह जासूसी का पहला मामला है. मैंने पहले ही सोच रखा था कि अगर मेरी यह फिल्म सफल होती है तो मैं एक और फिल्म बनाऊंगा और उसमें ब्योमकेश के नए साहसिक कामों को दर्शकों तक पहुंचाऊंगा. मुझे एक नहीं ब्योमकेश बख्शी पर कई फिल्में बनानी हैं. मुझसे कई लोग यह बोल चुके हैं कि मैं इस फिल्म का सीक्वल कब बना रहा हूं. दर्शकों से मिली तारीफ से मैं बहुत खुश हूं. यह फिल्म दर्शकों को एक अलग दुनिया में ले गई और यही हम ऐसा ही चाहते थे. देश में ब्योमकेश बख्शी को हर कोई जानता है और यह फिल्म उन लोगों को ज्यादा पसंद आ रही है जो ब्योमकेश बख्शी के फैन हैं. दिबाकर ने किरदारों को फिल्म में काफी अच्छे से गढ़ा है. डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी के जरिए बंगाली लेखक की कहानियों के किरदार ब्योमकेश बख्शी को जीवंत करने की यह एक सफल कोशिश है. सुशांत के काम के साथ-साथ उनका लुक भी दर्शकों को बहुत पसंद आया है. फिल्म में सुशांत को एक बिल्कुल नए अवतार में दिखाया गया है. फिल्म 1940 की पृष्ठभूमि पर आधारित है और उनके बंगाली किरदार को काफी बारीकी से फिल्माया गया है. सुशांत ने फिल्म के प्रमोशन के दौरान भी धोती कुर्ता ही पहना था.■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

मुशायरा जश्न-ए-बहार

गंगा-जमुनी तहज़ीब का अलमबरदार

मोनिशा भटनागर
feedback@chauthiduniya.com

निगाहों के तक़ाज़े चैन से मरने नहीं देते,
यहां मंजर ही ऐसे हैं कि दिल भरने नहीं देते.
क़लम मैं तो उठा के जाने कबका रख चुका होता,
मगर तुम हो कि क़िस्सा मुख्तसर करने नहीं देते.

प्रो. वसीम बरेलवी का ये शेर 17वें जश्न-ए-बहार मुशायरे की कहानी पूरी तरह बयां कर देता है. हर बार की तरह इस साल भी दिल्ली के मथुरा रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में 17वें जश्न-ए-बहार मुशायरे की महफ़िल जमी. भारत के प्रसिद्ध मुशायरे में शिरकत करने दुनियाभर के नामचीन शायर नजर आए और अपनी बेहतरीन नज्मों से समा बांध दिया. इस मुशायरे की शुरूआत 17 साल पहले कामना प्रसाद ने जश्न-ए-बहार ट्रस्ट की स्थापना करके की थी. मक़सद यह था कि गंगा जमुनी तहज़ीब और उर्दू की परंपरा चलती रहे और उर्दू के उस्तादों और उर्दू के क़द्रदानों के बीच रिश्ता भी बरक़रार रहे. उर्दू शायरी के चाहने वालों को इस सालाना जश्न का बेसब्री से इंतज़ार रहता है. साल दर साल आयोजित होने वाले मुशायरे की मक़बूलियत बढ़ती गई और इसकी देश में आयोजित होने वाले एक अंतरराष्ट्रीय मुशायरे के रूप में पहचान बनती गई.

इस बार कार्यक्रम में हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान, सउदी अरब, चीन, अमेरिका और कनाडा के भी मशहूर शायरों ने शिरक़त कर महफिल में चार चांद लगा दिए. उर्दू के चाहने वालों ने इन शायरों की शायरी का ख़ूब लुत्फ़ उठाया. जश्न-ए-बहार महफिल को संबोधित करते हुए कामना प्रसाद ने कहा कि भारत में मुशायरे को हमेशा से ही धर्मनिरपेक्ष दृष्टि से देखा जाता रहा है जिसकी पहचान उर्दू और हिंदुस्तानी चरित्र को समेटे हुए है. उन्होंने कहा कि मुशायरा हर किस्म की तफ़रीक़ और तक़्सीम की मुख़ालफ़त करता है. इसमें शरीक होने वालों का मज़हब सिर्फ़ एक होता है और वह है मज़हबे दिल.

पाकिस्तान से आए शायरों इस्लामाबाद की किश्वर नाहीद, लाहौर के अमजद इस्लाम अमजद और कराची की अम्बरीन हासिब ने अपनी शायरी से समां बांध दिया. वहीं भारत के वसीम बरेलवी, खुशबीर सिंह साद, पॉपुलर मेरठी,अलीना इसरत रिज़वी, आलोक श्रीवास्तव, कलीम समर, मंसूर उस्मानी जैसे शायरों ने अपनी शायरी से वहां मौजूद दर्शकों को सराबोर कर दिया. सउदी अरब से आये उमर सलीम अल-एद्रुस ने जहां हिंदुस्तान की शान में क़सीदे पढ़े, वही कनाडा के अशफ़ाक़ हुसैन और अमेरिका के डॉ अब्दुल्लाह अब्दुल्लाह ने अपनी रूमानी शायरी से वहां मौजूद लोगों की वाह-वाही लूटी. इस बार मुशायरे को और दिलचस्प बनाया चीन से आए 75 वर्षीय शायर झांग शिग्जुआन ने अपने उर्दू प्रेम से मुशायरे में मौजूद हर शख़्स का दिल जीत लिया. यहा तक कि झांग ने अपना तख़ल्लुस (पेन नेम) इंतिख़ाब आलम रखा है, जो उनके चीनी नाम का उर्दू अनुवाद है.

समारोह में बतौर मुख्य अतिथि आये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरूद्दीन खान ने कहा, उर्दू को मुल्क के साथ जोड़े, मज़हब के साथ नहीं. उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुई और हिंदुस्तान की ज़बान है. इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर भी उपस्थित थे. उन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता(सदारत) की.

गंगा-जमुनी तहज़ीब की मिसाल बन चुके जश्न-ए-बहार मुशायरे में तालियों की गड़गड़ाहट और वाह-वाही के बीच शायरी के गुलदस्ते में शोख़ी, रूमानियत के साथ-साथ इंसानियत और बंटवारे का ज़ख्म भी पैबस्त था. यहां मौजूद दर्शकों को देश-विदेश के शायरों ने अपनी शायरी से अदबी रियासत से रू-ब-रू करवाया. इस महफ़िल में शायरी पूरी दुनिया की संस्कृतियों को एक सूत्र में पिरोती दिखी.

मुशायरे में आये सभी शायरों ने कामना प्रसाद जी और उनकी इस अनूठी संस्था जश्न-ए-बहार को उर्दू शायरी के ऐसे मुशायरे को आयोजित करने के लिए शुक्रिया और बधाई दी. खुले आसमां के नीचे दिल्ली वालों ने देश-विदेश के नामचीन शायरों की नज़्मों-गज़लों का जमकर लुत्फ़ उठाया.■

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

20 अप्रैल–26 अप्रैल 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

विरासत की जंग

राजद कार्यसमिति की बैठक में पप्पू यादव ने जैसे ही महाविलय के ख़िलाफ बोलना शुरू किया लालू प्रसाद हत्थे से उखड़ गए. लालू प्रसाद ने साफ कहा कि महाविलय हो चुका है और अब इसके लिए केवल औपचारिकताओं को पूरा करने का काम बाकी रह गया है, इसलिए किसी को भी इसके ख़िलाफ बोलने की जरूरत नहीं है. अगर किसी को यह पसंद नहीं है तो उसके लिए दरवाजा खुला है. लालू प्रसाद ने पप्पू यादव की ओर मुख़ातिब होते हुए कहा कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, इसे मैं अच्छी तरह जानता हूं लेकिन हर कोई यह अच्छी तरह समझ ले कि बाप का उत्तराधिकारी बेटा ही होता है.

सरोज सिंह

चुनावी साल में अगर किसी पार्टी में विरासत की जंग छिड़ी हो तो इस पार्टी के मुखिया की पीड़ा का सहज एहसास किया जा सकता है. यह ऐसी पीड़ा है जिसे दबा कर रखने में ही भलाई समझी जाती है लेकिन कभी-कभी यह पीड़ा इतनी असहनीय हो जाती है कि चाह कर भी छिपाने में दिक्कत होती है. जी हां, हम बात कर रहे हैं इन दिनों लालू प्रसाद की पार्टी राजद में चल रही विरासत की जंग की. सभी जानते हैं कि पिछले दो दशकों से बिहार और देश की राजनीति में लालू प्रसाद एक ऐसे किरदार हैं, जिन्हें चाहकर भी कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है. लालू के जितने आलोचक रहे हैं, उतने ही चाहने वाले भी. लालू प्रसाद जिस सोशल इंजीनियरिंग के दायरे में अपनी राजनीति करते आ रहे हैं, उसमें सेंध लगाने की तमाम कोशिशें अब तक नाकाम रही हैं. यहां तक कि अपने सबसे कठिन दिनों में भी लालू प्रसाद ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग के चक्रव्यूह को टूटने नहीं दिया और यही उनकी राजनीतिक सफलता का राज भी है. इस दौरान छोटी-मोटी पार्टी विरोधी हलचलों को लालू प्रसाद ने अपने ही स्टाइल में निपटा दिया.

पिछले लोकसभा चुनाव के बाद लालू प्रसाद की राजनीतिक बादशाहत को पहली बार एक गंभीर चुनौती मिली और वो चुनौती दी है मधेपुरा के राजद सांसद पप्पू यादव ने. किसी जमाने में एक बाहुबली के तौर पर पप्पू यादव की पहचान बनी थी और कोशी और मिथिला के इलाके में मंडल आंदोलन के दौरान पप्पू यादव एक खास समुदाय के रॉबिनहुड के रूप में उभर कर सामने आए थे. मंडल आंदोलन के ठंडे पड़ने के बाद पप्पू यादव की राजनीतिक चमक भी हल्की पड़ी और बाद के दिनों में अजीत सरकार हत्याकांड में उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ा. इस हत्याकांड में बरी होने के बाद पप्पू यादव ने अपनी छवि बदली और एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने अपनी दूसरी पारी शुरू की. संगठन के माहिर पप्पू यादव ने जल्द ही न केवल कोशी बल्कि बिहार के दूसरे जिलों में भी अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ा दी. जनता का समर्थन भी पप्पू को मिलने लगा और लोकसभा चुनाव के समय ऐसे राजनीतिक हालात बने कि न चाहते हुए भी पप्पू यादव को लालू प्रसाद ने राजद के टिकट पर मधेपुरा से चुनाव लड़ने के लिए उतार दिया. पप्पू यादव न केवल खुद चुनाव जीते बल्कि बगल की संसदीय सीट सुपौल से उनकी पत्नी रंजीता रंजन कांग्रेस के टिकट पर जीत कर दिल्ली पहुंच गईं. पति-पत्नी दोनों की जीत ने कोशी और मिथिलांचल के इलाके में पप्पू यादव के राजनीतिक ग्राफ को काफी ऊपर पहुंचा दिया और इसी चढ़े हुए ग्राफ ने पप्पू यादव के दिल में यह ख्वाब भी पैदा कर दिया कि आने वाले दिनों में या कहें तो लालू प्रसाद के बाद उनकी विरासत के असली वारिस वह हो सकते हैं. लालू प्रसाद और उनकी पार्टी राजद का वारिस होने का सपना पप्पू यादव को बैचेन करने लगा और इस मंजिल को हासिल करने के लिए वह लगातार बिहार का दौरा करने लगे. कोई ऐसा दिन नहीं बीत रहा है जब पप्पू यादव सूबे के किसी न किसी जिले में कोई राजनीतिक जलसा न कर रहे हों. पप्पू यादव के जादू का असर यह हुआ कि राजद विधायक दल में सेंध लग गई और पार्टी के कुछ विधायक खुलकर तो कुछ परदे के पीछे पप्पू के साथ आ गए. पप्पू यादव के इन कामों से लालू प्रसाद की पीड़ा लगातार बढ़ती गई. लेकिन उन्होंने कभी भी इसे सार्वजनिक नहीं किया. मीडिया ने भी जब इस पहलू को उनके सामने कुरदने की कोशिश की तो उसे भी लालू प्रसाद ने हल्के में लेकर उड़ा दिया और कभी भी अपने स्तर से इसे गंभीर मामला नहीं बनने दिया. लेकिन लालू प्रसाद को यह एहसास हमेशा रहा कि पप्पू यादव के बयानों और क्रियाकलापों से पार्टी के अंदर सही संदेश नहीं जा रहा है. खासकर मांझी प्रकरण में लालू प्रसाद और पप्पू यादव दो छोर पर नज़र आए. जीतनराम मांझी को नेता मानने की अपील पप्पू यादव बार-बार कह रहे हैं. जीतन राम मांझी के लिए लालू प्रसाद के दिल में भी सॉफ्ट कॉर्नर है पर राजद की राजनीति में उनकी भूमिका क्या होगी, इसकी पटकथा लालू प्रसाद खुद लिखना चाहते हैं. लालू प्रसाद जैसे शख्स के लिए यह संभव ही नहीं कि वह किसी दूसरे की लिखी पटकथा को पढ़ें. अगर ऐसा हुआ तो फिर लालू यादव का मतलब ही क्या रह जाता है? इसलिए लालू प्रसाद ने बार-बार पप्पू यादव को यह संदेश दिया कि डिब्बा बनकर रहो इंजन बनने की कोशिश मत करो. अगर पसंद नहीं है तो फिर दूसरी ट्रेन का हिस्सा बन जाओ. इधर महाविलय को लेकर लालू यादव और पप्पू यादव के बीच मतभेद इतने बढ़ गए कि राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक का माहौल ही तनावपूर्ण हो गया. पहले तो पप्पू यादव महाविलय के पक्ष में नहीं हैं और उनका कहना है कि अगर यह बहुत जरूरी है तो राजद और उसके कार्यकर्ताओं के हितों की कीमत पर न हो. कार्यसमिति की बैठक में भी पप्पू यादव ने जैसे ही महाविलय के ख़िलाफ़ बोलना शुरू किया लालू प्रसाद हत्थे से उखड़ गए. लालू प्रसाद ने साफ कहा कि महाविलय हो चुका है और अब इसके लिए केवल औपचारिकताओं को पूरा करने का काम बाकी रह गया है, इसलिए किसी को भी इसके ख़िलाफ़ बोलने की जरूरत नहीं है. अगर किसी को यह पसंद नहीं है तो उसके लिए दरवाजा खुला है. लालू प्रसाद ने पप्पू यादव की ओर मुख़ातिब होते हुए कहा कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, इसे मैं अच्छी तरह जानता हूं. लेकिन हर कोई यह अच्छी तरह समझ ले कि बाप का उत्तराधिकारी बेटा ही होता है. इतना कहकर लालू प्रसाद ने पप्पू यादव को बिठा दिया. कार्यसमिति के बाद पप्पू यादव वहां से तो निकल गए लेकिन कटिहार पहुंचकर उन्होंने अपने दिल की भड़ास जमकर निकाली. उन्होंने कहा कि मैं पिछले दो दिनों से सो नहीं पाया हूं. समझ में नहीं आ रहा है इस मुल्क में राजतंत्र है या प्रजातंत्र? राजतंत्र में तो सुनता आया हूं कि पिता की विरासत पुत्र को सौंपी जाती है लेकिन प्रजातंत्र में भी ऐसी परंपरा है, इसका ज्ञान मुझे नहीं है. पप्पू यादव कहते हैं कि किसी की संपत्ति का वारिश उसका पुत्र हो सकता है लेकिन राजनीतिक वारिश तो वही हो सकता है जो इसके लायक है और जिसे जनता चुनती है या चुनेगी. दरअसल पप्पू यादव कार्यसमिति में लालू प्रसाद द्वारा दिए गए उस बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा उत्तराधिकारी मेरा बेटा ही होगा क्योंकि पिता का वारिश तो बेटा ही होता है. कटिहार में लालू प्रसाद के बयानों का करारा जवाब देकर पप्पू यादव ने साफ कर दिया कि वह मानने वाले नहीं है. वह कहते हैं कि लालू प्रसाद हमारे नेता हैं लेकिन उनका वारिश कौन होगा इसे लालू प्रसाद नहीं बल्कि बिहार की जनता तय करेगी. जानकर बताते हैं कि पप्पू यादव दूर की राजनीति कर रहे हैं. पप्पू यादव को पता है कि महाविलय के बाद नई पार्टी में उनका राजनीतिक कद अपने आप कम हो जाएगा. इसलिए वह शुरू से ही इसके पक्ष में नहीं हैं. पप्पू शुरू से ही जीतनराम मांझी का पक्ष ले रहे हैं क्योंकि कोशी और मिथिला के इलाके में महादलितों की बहुत बड़ी आबादी है. पप्पू चाहते हैं कि महाविलय के बाद राजद पर वह अपना दावा ठोंककर लालटेन को जलाए रखें. पप्पू खेमे के नेताओं का कहना है कि लालू प्रसाद के राजनीतिक पतन के बाद यादवों की राजनीति पप्पू यादव के आसपास घूमे, इसके लिए अभी से ही बिसात बिछाई जा रही है. यादव समुदाय स्वाभाविक तौर पर पप्पू यादव को नेता मान लें इसके लिए सब जतन अभी से हो रहे हैं. इस खेमे का मानना है कि लालू प्रसाद के पुत्रों में इतनी राजनीतिक क्षमता नहीं है कि वे पप्पू यादव का मुकाबला कर सकें. इसलिए पप्पू यादव इसे एक बेहतर अवसर मानते हुए लालू प्रसाद की विरासत पर अभी से ही अपना मजबूत दावा ठोंक रहे हैं. जानकार बताते हैं कि पप्पू यादव देवेंद्र यादव और रंजन यादव जैसे नेताओं के भी लगातार संपर्क में हैं. इंतजार महाविलय का हो रहा है और जिस दिन यह हुआ उसी दिन से विरासत की जंग अपनी अंतिम अध्याय में प्रवेश कर जाएगी.■

पप्पू यादव न केवल खुद चुनाव जीते बल्कि बगल की संसदीय सीट सुपौल से उनकी पत्नी रंजीता रंजन कांग्रेस के टिकट पर जीत कर दिल्ली पहुंच गईं. पति-पत्नी दोनों की जीत ने कोशी और मिथिलांचल के इलाके में पप्पू यादव के राजनीतिक ग्राफ को काफी ऊपर पहुंचा दिया और इसी चढ़े हुए ग्राफ ने पप्पू यादव के दिल में यह ख्वाब भी पैदा कर दिया कि आने वाले दिनों में या कहें तो लालू प्रसाद के बाद उनकी विरासत के असली वारिस वह हो सकते हैं. लालू प्रसाद और उनकी पार्टी राजद का वारिस होने का सपना पप्पू यादव को बैचेन करने लगा और इस मंजिल को हासिल करने के लिए वह लगातार बिहार का दौरा करने लगे.

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

वास्तु विहार की नई टाऊनशिप

पूर्वी भारत की भवन निर्माण कंपनी वास्तु विहार हर बार अपने घरों में कुछ नई-नई तकनीकों को जोड़ती रहती है. कंपनी लेकर आई है एक और अंतरराष्ट्रीय तकनीक. इस तकनीक से बने घर फौलादी सुरक्षा लिये होंगे जो किसी भी प्रकृतिक झंझावतों का मुकाबला आसानी से कर सकेंगे. वेल्डेड वायर गर्डर तकनीक से बनी ये टाऊनशिप अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी. इस तकनीक से बनने की वजह से घर की नींव को अतिरिक्त मजबूती मिलेगी. जिसकी बदौलत भविष्य में इसके ऊपर कई मंजिला इमारतों का निर्माण करना संभव हो सकेगा. इस अत्याधुनिक टाऊनशिप के सभी घर हीट इंसुलेटेड तकनीक से बनाये जाने की वजह से ऊर्जा की बचत करेंगे. ऊर्जा संरक्षित ये घर सौर ऊर्जा का भरपूर उपयोग कर बिजली की खपत को 25 प्रतिशत तक कम करेंगे. इससे बिजली की बचत होगी. पर्यावरण संरक्षित होगा और आपकी जेब पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ को भी कम करेगी. इन घरों को मेंटनेंस फ्री भी बनाया जायेगा. यानी घर की बाहरी दीवारों को एक रफ-टफ लुक दिया जायेगा. जिसकी बदौलत इन घरों का रख-रखाव आसान होगा. बाहरी दीवारों को हर साल न तो रिपेयरिंग की जरुरत पड़ेगी और न ही पेंट की. वास्तु विहार की ये नई तकनीक एक बार फिर भवन निर्माण के क्षेत्र में नई क्रांति की नींव रखेगा. **– निक्की सिंह**

मुस्लिम मतों की भूमिका निर्णायक

जनता दल राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय संयोजक अशफाक रहमान का मानना है कि बिहार विधानसभा के 2015 के चुनाव में मुस्लिम मतों की निर्णायक भूमिका होगी इसलिए जनता दल राष्ट्रवादी धोखा देकर मुस्लिम मत हासिल करनेवाले दलों का नकाब उतारने के लिए पूरे राज्य में अपने कार्यकर्ताओं के जरिये जन जागरण अभियान चला रही है. मतदाताओं से अपने हितैषी दल को वोट देने की अपील कर रही है. पार्टी सबको साथ लेकर चलने एवं अपने नीति एवं कार्यकमों की जानकारी आम जनता के बीच पहुंचा रही है. रहमान ने आम जनता से एक बार फिर दोहराया कि जनता दल राष्ट्रवादी बिहार को बदहाली की ओर ले जाने वाले दलों से जरूर जनता को निजात दिलायेगी. साथ ही रहमान ने बताया कि बिहार में सब कोई अपने धुन में लगा हुआ हैं इसलिए एक बार फिर अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि आनेवाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहें. **– भारती**

बह रही विकास की गंगा

गोगरी अनुमंडल क्षेत्र के सौढ़ उत्तरी पंचायत स्थित सतीश नगर गांव के भगवानपुर टोला में विधान पार्षद सोनेलाल मेहता के द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना मद से बनी सड़क का उद्घाटन किया गया. उन्होंने कहा कि उक्त सड़क खोखा मंडल के घर से आनंदी मंडल के घर तक पांच लाख एक हजार 6 सौ की राशि से मुख्यमंत्री विकास योजना से बनी है. जो उनके कोटे की है. उन्होंने कहा कि लोगों की कठिनाई को देखते हुए इस सड़क को बनाया गया है. उन्होंने कहा कि सुशासन की सरकार में बह रही है विकास की गंगा. जिला परिषद उपाध्यक्ष सुनील कुमार ने कहा कि क्षेत्र की समस्या को लेकर उनके द्वारा जिला प्रशासन से लेकर सूबे के मुखिया तक ध्यान दिया जायेगा. इस मौके पर जदयू प्रखंड अध्यक्ष नंदलाल मंडल, जदयू नेता शंभू झा, राजद नेता प्रकाश दास, मुखिया पृथ्वी चन्द्र सिंह, नागेश्वर पटेल, कैलाश शर्मा, अमीत कुमार, प्रभू नारायण पंडित, सुभाष सिंह, सुशील सिंह सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे.■ **– गीता कुमार**

गया

आईआईएम को नहीं मिली भूमि

सुनील सौरभ

देश के प्रसिद्ध प्रबंधन शिक्षण संस्थान आईआईएम के लिए मगध विश्वविद्यालय परिसर में राज्य सरकार द्वारा चिन्हित 119 एकड़ भूमि देने से सिंडिकेट ने इंकार कर दिया. इस मामले पर अब राज्य सरकार व मगध विश्वविद्यालय के बीच एक तरह से टकराव की स्थिति बन गयी है. सिंडिकेट में जहां भूमि देने की बात की जा रही है, इसके लिए आईआईएम एक को हजार करोड़ रुपये की भरपाई करनी पड़ेगी. देश के चर्चित शिक्षण संस्थान में शुमार भारतीय प्रबंधन संस्थान (आई आई एम) के लिए तत्कालीन जीतन राम मांझी की सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी. बिहार मे जब आईआईएम खोले जाने की बात हुई तो इसके मेंटर आईआईएम इंदौर ने पटना के आसपास ही जगह देने की मांग राज्य सरकार से की. इस संस्थान के लिए सौ एकड़ से अधिक भूमि पटना के आसपास मिलने के परेशानी को देखते हुए इसे गया में खोलने का राज्य सरकार ने आईआईएम को सलाह दी. इसके लिए राज्य सरकार ने बोधगया स्थित मगध विश्वविद्यालय परिसर में भूमि देने का प्रस्ताव आईआईएम इंदौर को दिया. कहा गया कि गया की पूरे देश से रेलवे, वायु सेवा व सड़क मार्ग की अच्छी कनेक्टीवीटी है. इन सब बातों को देखते हुए ही आई आई एम इंदौर ने अपनी शाखा गया में स्थापित करने का निर्णय लिया. दिसंबर 2014 के अंतिम सप्ताह में आईआईएम के लिए भूमि चिन्हित करने के लिए एक टीम मगध विश्वविद्यालय आयी. इस टीम में केन्द्रीय मानव संसाधन विभाग के तकनीकी शिक्षा के निदेशक अमरजीत सिन्हा, आईआईएम इंदौर के प्रो. सिद्धार्थ, ऋषिकेश सिंह कृष्णन , राज्य सरकार के मानव संसाधन विभाग के निदेशक आर के महाजन समेत अन्य कई पदाधिकारी शामिल थे. इस टीम ने मगध विश्वविद्यालय के परिसर के पूरब व पश्चिम हिस्से में खाली पड़ी भूमि को आई आई एम के लिए चिन्हित किया था. तब मगध विश्वविद्यालय कर्मियों ने इसका विरोध किया था. लेकिन राज्य सरकार व कुलाधिपति के दबाव में विरोध दब गया था. इस भूमि के बदले आई आई एम ने 900 करोड़ रुपये मगध विश्वविद्यालय को देने का निर्णय लिया था. लेकिन अब मामला उलट गया है.

देश के चर्चित शिक्षण संस्थान में शुमार भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) के लिए तत्कालीन जीतन राम मांझी की सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी. बिहार मे जब आई आई एम खोले जाने की बात हुई तो इसके मेंटर आई आई एम इंदौर ने पटना के आसपास ही जगह देने की मांग राज्य सरकार से की. लेकिन इस संस्थान के लिए सौ एकड़ से अधिक भूमि पटना के आसपास मिलने के परेशानी को देखते हुए इसे गया में खोलने का राज्य सरकार ने आई आई एम को सलाह दी. इसके लिए राज्य सरकार ने बोधगया स्थित मगध विश्वविद्यालय परिसर में भूमि देने का प्रस्ताव आईआईएम इंदौर को दिया.

29 मार्च 2015 को मगध विश्वविद्यालय सिंडिकेट की बैठक में राज्य सरकार के नक्शे को खारिज कर दिया गया. हालांकि इसके लिए राज्यपाल सह कुलाधिपति के नामित सदस्य व राज्य सरकार के नामित सदस्यों ने आई आई एम के लिए चिन्हित भूमि के आवटन के लिए जबर्दस्त दबाव बनाया. लेकिन इन सदस्यों की एक नहीं चली. सिंडिकेट सदस्य दो धड़े में बंट गये. इस मामले के लेकर सिंडिकेट की बैठक स्थागित कर दी गयी. पुन: बैठक शुरू हुई तो मगध विश्वविद्यालय परिसर के दक्षिणी हिस्से की भूमि को आई आई एम के लिए देने का निर्णय लिया गया. इस हिस्से मे मविवि के अनेक विभागों के कई बहुमंजिली इमारतें, स्टेडियम स्वीमिंग पुल, छात्रावास कर्मचारी आवास आदि है. इसके तोड़े जाने से जो क्षति होगी इसकी भरपाई आई आई एम को करना पडेग़ा. इसमें आई आई एम को कई हजार करोड़ की भरपाई करनी पड़ेगी. जबकि पूर्व में चिन्हित भूमि खाली थी. लेकिन 'प्राइम लोकेशन में इस भूमि के होने के कारण मविवि इसे देने से इंकार कर रहा है. एक तरह से आई आई एम के लिए भूमि आवंटन का मामला लटक गया है. वहीं दूसरी ओर आई आई एम इंदौर इस वर्ष जुलाई माह से गया में नामांकन कर पढ़ाई आरंभ करने का निर्णय ले चुका है. हालांकि इस मामले में पटना हाई कोर्ट भी एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार तथा मविवि से पूछा था कि आखिर आई आई एम के लिए भूमि देने के लिए क्या परेशानी हो रही है. आई आई एम के गया लाने के लिए संघर्ष करने वाले बुद्धिजीवियों को आशंका है कि मविवि कर्मियों के ऐसे रवैये से आई आई एम कहीं दूसरी जगह नही चला जाए. अब सवाल है कि आई आई एम इंदौर अपने अनुसार चिन्हित भूमि के बदले दूसरी भूमि को लेने के सवाल पर क्या रुख अपनाती है? यदि सिंडिकेट द्वारा चिन्हित भूमि को लेने के लिए तैयार भी हुई तो क्या हजारो करोड़ की भरपाई मविवि को कर पाती है या नहीं. इन सवालों के बीच गया में आई आई एम की स्थापना का मामला एक तरह से अधर में लटक गया है.■

feedback@chauthiduniya.com

अन्य ख़बरें

विद्युतीकरण का श्रीगणेश

सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर प्रखंड के मधौलसानी पंचायत में विद्युत सुविधा बहाल करने को लेकर प्रयास शुरू कर दिया गया है. पंचायत के रायपुर गांव में योजना के तहत विधायक पति सह वरीय जदयू नेता राजेश चौधरी ने कार्य का शुभारंभ कराया. इस अवसर पर जदयू नेता ने कहा कि क्षेत्र के लोगों को सरकारी सुविधा का लाभ दिलाना प्राथमिकता है. मौके पर अभियंता मुकुंद कुमार, विनय कुमार, गुरूशरण सिंह, रवींद्र सिंह, बलवीर सिंह, योगी सिंह फौजी, राम प्रताप राय, नवीन झा, भागो राय व संजीत बैठा समेत अन्य थे. **– विभा**

निकली शोभा यात्रा

सीतामढ़ी शहर के महावीर स्थान स्थित दक्षिणमुखी सिद्धपीठ हनुमान मंदिर में दो दिवसीय हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन किया गया. अवसर पर शहर में भव्य निशान शोभा यात्रा निकाली गयी. कार्यक्रम में कन्हैया सर्राफ, सौरभ कुमार, नगर परिषद सभापति सुवंश राय, कौशल किशोर शर्मा, पंडित तेजपाल शर्मा, लालबाबू शर्मा, लक्ष्मीकांत शर्मा, अजय विद्रोही, पवन कुमार शर्मा, राजेश कुमार सुंदरका, दीपक शर्मा, दीपक मस्करा, शिव कुमार प्रसाद, राजेश सिंह, प्रो नरेश कुमार राज, गणेश सिकारिया, पंकज गोयनका, अजय सोनी, नीरज कुमार गोयनका, नरेंद्र शर्मा समेत अन्य थे. **– ब्रजेश**

धोखाधड़ी के खिलाफ खोला मोर्चा

सीतामढ़ी जिले के स्वास्थ्य महकमे में चल रही धोखाधड़ी के खिलाफ लोजपा नेता सबीह अहमद ने मोर्चा खोल दिया है. शहर के जांच घरों में चल रहे फर्जी रिपोर्ट के खेल को आम जनता के जीवन के साथ खतरनाक मजाक बताते हुए लोजपा नेता ने आंदोलनात्मक तेवर अख्तियार कर लिया है. पिछले दिनो सीतामढ़ी व्यवहार न्यायालय में तीन चिकित्सको के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के बाद मामले का खुलासा किया. बताया गया है डॉ. मनोज से इलाज के दौरान अपनी 7 माह की पुत्री अनम का पोपुलर जांच घर से सीटी स्कैन एवं आरएमइजी स्कैन सेंटर से इजी स्कैन जांच करा कर रिपोर्ट के साथ डॉ मनोज से संपर्क किया. रिपोर्ट के आधार पर डॉ ने बच्ची को अविलंब पटना रेफर कर दिया. पटना के चिकित्सक डॉ प्रदीप ने जब अपने स्तर से जांच कर इलाज की तब सीतामढ़ी की रिपोर्ट को फर्जी पाया. परेशान हाल लोजपा नेता ने डा नरेंद्र कुमार, डॉ एके सिंह व डॉ रवींद्र बिहारी त्रिवेदी के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है. साथ ही डीएम व सीएस को आवेदन देकर दोषी जांच घर संचालको के विरुद्ध कार्रवाई का आग्रह किया है. कहा है कि अगर दोषी चिकित्सकों पर कार्रवाई नहीं हुई तो जन आंदोलन किया जायेगा. **– विकास**

महावीर जयन्ती मनी

मोतिहारी के स्थानीय डाक बंगला परिसर में भगवान महावीर की जयन्ती धूम-धाम से मनायी गयी और इनके आर्दशों पर विस्तार से चर्चा की गयी. कार्यक्रम की अध्यक्षता चम्पारण संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष राय सुन्दर देव शर्मा ने की जबकि संचालन संघर्ष मोर्चा के प्रधान महासचिव अमरेन्द्र सिंह ने किया. मंच का संचालन कर रहे श्री सिंह ने कहा कि भगवान महावीर का जन्म 2500 वर्ष पहले वैशाली के गणतंत्र राज्य कुण्डलपुर में हुआ था जो कि आज वैशाली जिले में उपस्थित है. भगवान महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था एवं महावीर कई उपाधियां प्रसिद्ध है. इनकी मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में हो गयी थी. मौके पर डॉ उमेश, विपिन श्रीवास्तव, अतफाक हैदर, मनोज श्रीवास्तव, साबिर अली, मुकेश पटेल, राजू साह सहित अन्य लोग उपस्थित थे.

ग्रामीणों ने रोकी ट्रेन

मोतिहारी के घोड़ासहन स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों की ठहराव की मांग को ले टाईगर फोर्स के बैनर तले ग्रामीणों ने धरना दिया और कई ट्रेनों का परिचालन बाधित किया. व्यवसायी संघ के अध्यक्ष संजय जायसवाल व प्रभुनारायण प्रसाद ने बताया कि एक्सप्रेस ट्रेनों की ठहराव यहां नहीं होने से भारी परेशानी होती है. उनके अनुसार, पूर्व में इस स्टेशन पर सभी ट्रेनें रुकती थीं और रेलवे को अच्छा राजस्व भी आता रहा है.एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव के लिए विभिन्न संगठनों एवं राजनैतिक पार्टियों के यहां पूर्व में कई बार धरना प्रदर्शन भी किया गया किन्तु कोई कार्रवाई नही होने से जनता का आक्रोश बढ़ गया है.

मानस महायज्ञ आयोजित

मोतिहारी के महावीर मंदिर परिसर में दस दिवसीय 44 वां श्री राम चरित मानस महायज्ञ का आयोजन किया गया. मौके पर चित्रकुट से पधारी साध्वी पुष्पा रामायणी ने कहा कि आज के दौर में शांति के लिए मनुष्य भटक रहे हैं. शांति प्राप्ति स्थल सत्संग होता है. गुरु के शरण से परमात्मा की प्राप्ति होती है. वर्तमान समय में घर-घर में दु:ख है. भगवान के भक्तों को भी कष्ट होता है लेकिन भगवान की शक्ति प्राप्त होने से कष्ट लौट जाता है. साध्वी ने प्रवचन कथा श्रवण में उपस्थित सैकड़ों लोगों से कहा कि राम चरित मानस से उनके प्रकार का दिशा लेना संभव है. यह कथा सम्पूर्ण मानव जाति को जीने की कला सिखाती है. कथा वाचन में साध्वी ने कहा कि शंकर जी के समझाने की अवहेलना कर जब सती पत्नी सीता का स्वरूप बनाकर राम के ईश्वरत्व की परीक्षा ली और जब असफल हो गईं तब शंकर ने भी उनको त्याग दिया. प्रायश्चित के दौरान अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया. उनका अगला जन्म पार्वती के रूप में हुआ पुनर्विवाह शंकर से होने के बाद उन्होंने राम कथा सुनी. मंच संचालन प्रो. राम निरंजन पांडेय ने किया तथा साध्वी का विस्तार से परिचय भी कराया. **– इंतेज़ारूल हक़**

सड़क की समस्या से दिलाई निजात

सदर प्रखंड के गुलाबनगर में जदयू विधायक पूनम देवी यादव ने आठ लाख बीस हजार चार सौ की राशि से बननेवाली सड़क का शिलान्यास किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हम अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सड़क की समस्यायों से निजात दिला दिया है. विधायक ने कहा कि रहीमपुर दक्षिणी के जंगली टोला करारी से रामलखन यादव के घर तक सड़क मरम्मत एवं पीसीसी सड़क का भी शिलान्यास किया गया है. इस अवसर पर जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष विनय कुमार वरुण, कृष्ण कुमार सिंह, नवीन कुमार, धूरण सिंह, कारेलाल सिंह आदि मौजूद थे. इससे पूर्व शनिवार को सदर विधायक सह सभापति महिला एवं बाल विकास समिति बिहार के पूनम देवी यादव ने अपने विधान सभा क्षेत्र के भदास उत्तरी पंचायत के बड़हारा, राजाजान, बभना, झमटा, भदास एवं भदास दक्षिणी पंचायत के त्रिभुवन टोला, सौरायडीह, भदास आदि गांवों का सघन दौरा किया. इस मौके पर पूर्व मुखिया वीरेन्द्र सदा, वकील शर्मा, चन्देश्वरी शर्मा, बिरजू रजक, नवल यादव, विनय कुमार, सरपंच प्रतिनिधि मो. रिजवान अहमद, महेश चौरसिया, गोपाल यादव, अर्जुन साह, राजा पटेल, डा0 जर्नादन, श्रवण ठाकुर, चंदन झा, ई. क्यूमइद्दीन आदि उपस्थित थे.

प्रतिभा मोहताज नहीं होती

खगड़िया के जेएनकेटी इन्टर विद्यालय के शैक्षाणिक सत्र 2015-16 का सत्रारंभ हुआ. इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी डॉ. ब्रजकिशोर सिंह ने कहा प्रतिभा अपने द्वार खोलने में समर्थ होती है. उज्जवल भविष्य के लिए वह स्वयं कार्य करती है. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सुरेश साह ने अपने संबोधन में कहा कि प्राचार्य डा आमोद कुमार का चिंतन बच्चों के स्वप्नों के अनुरूप है. जिला माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सीताराम चौधरी ने कहा कि जेएनकेटी इंटर विद्यालय देश के सभी माध्यमिक विद्यालयों के लिए एक मॉडल पेश करता है. इस अवसर पर शिक्षक नवीन कुमार ने विद्यालय के अनुशासन की चर्चा किया. प्राचार्य डा0 आमोद कुमार ने अतिथियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की और सभी छात्र-छात्राओं के जीवन के स्वप्निल द्वार को खोलने का संकल्प वक्त किया. इस अवसर पर शिक्षक विभाकर कुमार, आशीष कुमार, ज्ञानेश नंदन, अभिनंदन कुमार, अजय कुमार, प्रकाश कुमार, सुनील, सोनी, सुगंधा कुमारी, अर्चना, अंजु आदि उपस्थित थे.■ **– मनेन्द्र कुमार**

वर्षों से प्यासा है पुपरी का जल मीनार

सरकार प्रायोजित योजनाओं के तहत सीतामढ़ी जिले के अलग- अलग स्थानों पर करोडों की लागत से विकास कार्य कराये जा रहे हैं. लेकिन कमीशनखोरी व भ्रष्टाचार का आलम यह है कि कई योजनाएं दशकों बाद भी अधर में लटका है. अब आम लोगों का स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भरोसा उठने लगा है. जिले के सुरसंड विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पुपरी अनुमंडल मुख्यालय में मौजूद जल मीनार अगर समय रहते पूरा नहीं कराया गया तो संभव है कि आगामी विधानसभा चुनाव में इसे चुनावी मुददा बनाया जा सकता है....

गोविंद कुमार

एक ओर सूबे की सरकार आम लोगों को मूलभूत सुविधा मुहैया कराने को लेकर संकल्पित होने की बात करती है तो दूसरी ओर सरकार का प्रशासनिक तंत्र लापरवाह कार्यशैली का उदाहरण पेश करने से बाज नही आ रहा है. उदाहरण के तौर पर सीतामढ़ी जिले के पुपरी अनुमंडल मुख्यालय को देखा जा सकता है, जहां कहने को तो दो जल मीनार लोगों को नजर आता. लेकिन एक भी अब तक लोगों को पेयजल मुहैया कराने की स्थिति में नहीं है. मजे की बात यह है कि एक का करीब साढ़े चार दशक तो दूसरे का निर्माण शुरू हुए करीब डेढ़ दशक होने वाला है. बताया जाता है कि साढ़े चार दशक पूर्व निर्मित जल मीनार अप्रैल 2009 तक नगरवासियों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराता रहा है. तब के बाद से मामूली खराबी की वजह से बेकार बना है. पुपरी नगर के नागेश्वर स्थान के समीप ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत वर्ष 1970 में जल मीनार का निर्माण के बाद लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होना शुरू हुआ था. मई 2009 में इसका पम्प चेम्बर और जुलाई में बोरिंग धस गया. नतीजतन पानी की समस्या उत्पन्न हो गयी. इसी बीच एसएच-52 का निर्माण के समय रोड के अंदर पाईप लाईन क्षतिग्रस्त हो गई. जिसका मरम्मत नहीं कराया गया. जलापूर्ति ठप होने के बाद पुन: नया बोरिंग कराया गया. साथ ही जल मीनार का मरम्मत भी कराया गया. करीब ढ़ाई साल के मशक्कत के बाद 26 जनवरी 2012 को तत्कालीन सांसद डॉ अर्जुन राय द्वारा पुन: जलापूर्ति शुरू कराया गया. लेकिन कार्य योजना में व्याप्त कमीशनखोरी व भ्रष्टाचार का आलम रहा कि जलापूर्ति आंशिक रूप से ही शुरू हो सका. साल 2008 में इस जलापूर्ति के माध्यम से करीब 77 हजार रूपये का राजस्व सरकारी खाता में विभागीय स्तर पर कराया गया. बताया जाता है कि पुपरी में तकरीबन 5 सौ गृह जल संयोजन है. जिसे शुद्ध पेयजल की कमी का सामना करने की विवशता बनी है.

अखिलेश कुमार पाठक | अतुल कुमार | चंदन कुमार ठाकुर | डॉ. कुमकुम सिंहा | गुलाब ठाकुर | सूरज कुमार | विश्वनाथ प्रसाद

चर्चा है कि दूसरा जल मीनार जनकपू रोड शहरी योजना के तहत साल 1992-93 में करीब 67 लाख की लागत से बनाया गया. लेकिन इसमें भी कार्य योजना की ला-परवाही का खामियाजा साथ नहीं छोडा. आलम हुआ कि एक बूंद पानी दिये बिना ही बोरिंग फेल हो गया. दूसरी बार बोरिंग कराया गया, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात होकर रह गया. नतीजतन अब तक पुपरी नगर पंचायत के लोगों को पेयजल की समस्या का निदान के लिए भगवान भरोसा पर रहने की विवशता बनी है. युवा जदयू प्रखंड अध्यक्ष सुरज कुमार ने जलापूर्ति को बाधित होने के लिए स्थानीय प्रशासनिक तंत्र को पूर्णत: जिम्मेदार बताया है. लेकिन समस्या निदान को लेकर परेशान हाल लोगों ने अबकी बार जलापूर्ति योजना की विफलता को चुनावी मुददा बनाने का मन बना लिया है. संभव है कि चुनावी मौसम में यह मामला संभावित प्रत्याशियों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा. स्थानीय अखिलेश कुमार पाठक, चंदन कुमार ठाकुर, गुलाब ठाकुर, सूरज कुमार, विश्वनाथ प्रसाद, डॉ कुमकुम सिन्हा व अतुल कुमार समेत अन्य ने समस्या को गंभीर बताते हुए आवाज बुलंद करने की बात कही है.

कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनावी चक्रव्यूह की रूप-रेखा अब तैयार होने लगी है. जाति-पार्टी की राजनीति के बीच स्थानीय समस्या को भी तरजीह दिया जाने लगा है. ऐसे में पूर्व के प्रतिनिधि जहां जनता की अदालत में अपनी सफाई का मौका तलाश करेंगे, वहीं नये संभावित प्रत्याशियों को अपनी भावना साफ लहजे में जनता के बीच रखनी होगी. जन समस्याओं का निदान कहां तक हो पायेगा, यह तो वक्त बतायेगा. लेकिन समस्या को चुनावी मुददा बनाने का प्रयास की सराहना शुरू हो गयी है.■

feedback@chauthiduniya.com

सच साबित हुई चौथी दुनिया में छपी खबर

सिविल सर्जन समेत कई अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

इंतेज़ारुल हक़

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया में प्रकाशित खबर *स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों का घोटाला* सच साबित हुई और जांच के बाद सभी मामले सामने आ गये. पूर्वी चम्पारण के जिलाधिकारी जीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा उपविकास आयुक्त अनिल चौधरी के नेतृत्व में गठित जांच टीम ने सदर अस्पताल की कुव्यवस्था व व्याप्त भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की गहनता से जांच की जिसमें अनेक चौंकाने वाले तथ्य सामने आये.यहां किस तरह से जीवन रक्षक दवा की खरीददारी में मनमानी की गयी है और विभागीय आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए सरकार को चूना लगाया गया है, इसका खूबसूरत नमूना देखने को मिला है. तीन करोड़ 64 लाख रुपये की दवा खरीद कर स्टोर में इंट्री दिखाया गई है जबकि स्टोर में इतनी दवा नहीं है और 4 करोड़ 50 लाख की निकासी कर ली गयी है. जांच टीम द्वारा रिर्पोट सौंपे जाने के बाद इस मामले ने सिविल सर्जन डॉ मीरा वर्मा, अस्पताल के एक चिकित्सक, प्रधान सहायक, स्टोरकीपर व अन्य दो कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई जिलाधिकारी ने शुरू कर दी है. गोदाम को भी सील कर दिया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

विभागीय आदेश के अनुसार, एक लाख से अधिक की राशि का दवा खरीदने के लिए टेंडर की प्रक्रिया होनी चाहिए किन्तु ऐसा नहीं हुआ है और खुले आम विभागीय आदेशों की धज्जियां उड़ायी गयी है. यहां बताते चलें कि चौथी दुनिया अखबार में 2 फरवरी के अंक में स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था व करोड़ों रुपये का घोटाला होने की बाबत एक खबर प्रकाशित हुई थी.प्रकाशित खबर में सदर अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार,दवा खरीद में हुई मनमानी,विभागीय अधिकारियों द्वारा की जा रही मनमानी से संबधित विस्तार से खबर प्रकाशित हुई थी. जिलाधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उपविकास आयुक्त को जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. खबर में पूर्वी चम्पारण जिले में संचालित केसरिया व मधुबन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की वास्तिविक स्थिति को विस्तार से रेखांकित किया गया था. इसमें केवल केसरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 92लाख 30 हजार सात सौ 89 रुपये का घोटाला होने व इसकी सूचना वहां के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा सिविल सर्जन डॉ. मीरा वर्मा को कार्यालय के पत्रांक616 दिनांक 9.12.014 के तहत देने की जिक्र किया गया था. जिस राशि का घोटाला हुआ है वह एनआरएचएम योजना की है. स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रतिनियुक्त कर्मचारी संजय कुमार पांडेय के नाम से उक्त राशि का चेक काटा गया था. बैंक स्टेटमेन्ट के आधार पर वर्ष 2009 से 20011 तक हुए खर्च का जब ब्योरा तैयार किया गया था तब उक्त राशि के घोटाला का मामला सामने आया. श्री पाण्डेय द्वारा वर्ष 2006 से मई 20012 तक एनआरएचएम के विभिन्न कार्यक्रमों में राशि खर्च की गयी है जिसमें अधिकांश की निकासी नगद होने की बात बतायी गयी है और इसकी अभिश्रव व भुगतान पंजी कार्यालय को नही सौंपी गयी है.मई 2012 में जब श्री पाण्डेय द्वारा लेखापाल रवि रंजन एवं लिपिक मुरारी कुमार गुंजन को प्रभार दिया गया था तभी यह मामला सामने आया था किन्तु इस संचिका को सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा आरोपी को बचाने की नियत से किसी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया.इसके बाद प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने अपने कार्यालय के पत्रांक 228 दिनांक 10.4.14 के द्वारा ही इस मामले से सिविल सर्जन को अवगत कराते हुए विभागीय कार्रवाई करने व प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया किन्तु इसपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. दूसरी तरफ मधुबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की लचर व्यवस्था व चिकित्सकों की

फोटो-स्टोर में रखी दवा, प्रकाशित खबर

मनमानी से संबधित खबर प्रकाशित की गयी थी.यहां मरीज दवा के लिए कैसे भटकते रहे और मजबूर हो निजी दुकानों से खरीदते रहे तथा एक्सपायर दवा शौचालय में फेंक दी गईं. इसकी शिकायत सिविल सर्जन से की गयी और इस मामले को मंत्री रमई राम की अध्यक्षता में हुई जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक में उठाया गया.सिविल सर्जन की खिंचाई भी हुई और इस मामले की गहनता से जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. बावजूद इसके कोई ठोस कार्रवाई नही की गयी थी. इधर खबर पर जिलाधिकारी श्री श्रीवास्तव द्वारा जांच कराये जाने व मामले की पकड़ में आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कम्प मचा हुआ है और मामले को मैनेज करने की चर्चा जोरों पर हो रही है.चर्चा यह भी है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी काफी पहुंच रखते हैं और पैसे के बल पर सब कुछ मैनेज करना जानते हैं.जैसा की पूर्व में हुआ है.यहां पूर्व में तैनात सिविल सर्जन डॉ. सरोज सिंह,डॉ. बिल्टू पासवान समेत कई चिकित्सा पदाधिकारियों पर इस तरह का आरोप लग चुका है और जांच के बाद इनसे संबधित संचिकाओं को कहां दबा दिया गया इसकी खबर किसी को नहीं है. बताते चलें कि डॉ. सरोज पर 90 लाख रूपये व डॉ बिल्टू पर 20 लाख रुपये की दवा खरीददारी के मामले में अनियमितता का आरोप है.डॉ. सरोज पर मुकदमा भी दर्ज किया गया था.अब डा0 मीरा वर्मा पर कार्रवाई होती है या इस मामले को भी दबा दिया जायेगा,यह तो आने वाला समय बतायेगा.■

एक नज़र

दंगल आयोजित

गोगरी अनमंडल क्षेत्र के महदीपुर गांव में चैती दुर्गा पूजा समिति द्वारा चार दिवसीय अखिल भारतीय दंगल प्रतियोगिता के तीसरे दिन खगड़िया के पहलवान ने उत्तर प्रदेश को हरा दिया. उल्लेखनीय है कि चार दिवसीय दंगल प्रतियोगिता में जहां माड़र के पहलवान सिराज ने बनारस के पहलवान को हराया. वहीं मानसी रोहियार बंगलिया के राजदेव यादव ने मौनू पहलवान आगरा को पटकनी दी. वहीं चैती दुर्गा महदीपुर अखाड़ा के पुराने पहलवान लालजी बनारस व सुजीत पहलवान मध्यप्रदेश के बीच बराबरी का मुकाबला रहा. जबकि अखाड़ा संचालन युवा पहलवान नगीना सिंह, जवाहर सिंह ने बताया कि इस आयोजन से क्षेत्र के युवाओं को इस कुश्ती खेल के प्रति आकर्षित किया जा रहा है. इस अवसर पर मेला सचिव राजेन्द्र सिंह, अध्यक्ष परमानंद सिंह, कोषाध्यक्ष चन्द्रदेव प्रसाद सिंह, सुरेन्द्र बाबू, कन्या मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक दीपक कुमार एवं युवा समाजसेवी संजय सिंह अनिल उपस्थित थे.

महदीपुर में हुआ जागरण

गोगरी अनुमंडल क्षेत्र के पसराहा थाना अन्तर्गत महदीपुर मेला में आयोजित चैती दुर्गापुजा में जागरण एवं नाटक प्रस्तुत किया गया. जिसमें निमिया के डाढ़ मईया डाले ली झुलनवा, धोवत-धोवत तोहरे मंदिरवा, नाटक राखी बने अंगारे की प्रस्तुति हुई. जिसका उद्घाटन लोजपा नेत्री प्रो. सुहेली मेहता ने करते हुए कहा कि जागरण एवं नाटक के माध्यम से कलाकारों द्वारा किसी भी सामाजिक कुरीति पर आसानी से प्रहार किया जा सकता है. समाज में होने वाली बुराई को बड़ी सरलता से दिखाया जाता है. किस तरह समाज में महिलाओं को घर का बोझ माना जाता है. जिसके कारण उन्हें आगे की पढ़ाई से वंचित होना पड़ता है. इस कार्यक्रम के सभी कलाकारों ने बखूबी अपना किरदार निभाया. इस मौके पर निदेशक सत्येन्द्र सिह, मेला सचिव राजेन्द्र प्रसाद सिंह, अध्यक्ष परमानंद सिंह सहित हजारों दर्शक उपस्थित थे.

योजनाओं का हुआ उद्घाटन

गोगरी अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में दो करोड़ राशि योजनाओं का उद्घाटन महदीपुर के बरजरंगबली मंदिर के पास से पूर्व नगर विकास मंत्री राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी ने किया. इस अवसर पर परबत्ता प्रखंड के पूर्व उ उपप्रमुख नागेश्वर मेहता ने कार्यस्थल पर मौजूद थे. संवेदकों के द्वारा एक ही जगह पर गोगरी अनुमंडल के पसराहा, दीनाचकला, वासदेवपुर, कुलहरिया,गोगरी, करना, राटन, बंदेहरा, सोण्डिया, महदीपुर, कोलबारा, उत्तरी सौढ़, भरतखंड, पिपरा लतीफ पंचायत के कुल 29 योजन-ाओं का अनावरण किया गया. इस मौके पर सम्राट चौधरी ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा तत्तर रहेंगे. इस मौके पर रविश चन्द्र सिंह, अखिलेश कुमार सिंह,राजीव कुमार, रामचन्द्र सिंह, मो. जब्बार, पूर्व प्रभारी मुखिया क्षत्री शर्मा, राजेश कुमार, चतुरी पंडित, प्रदीप कुमार ठाकुर उपस्थित थे.

महायज्ञ की तैयारी जोरों पर

गोगरी अनुमंडल क्षेत्र के पसराहा थाना अन्तर्गत चकहर कमरी स्थित बस स्टैंड के प्रांगण में बजरंगबली प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जायेगा. यह कार्यक्रम 27 से 29 अप्रैल तक चलेगा. यह कार्यक्रम श्रीश्री 108 रामध्वनी महायज्ञ की तैयारी जोरों से चल रही है. जिसमें दूर दराज के रामध्वनी मंडली नेपाल, सहरसा, मधेपुरा,खगड़िया, बेगूसराय आदि से भाग ले रहे हैं.यज्ञ समिति के सदस्य विपिन यादव, कोषाध्यक्ष ब्रहमदेव साह, पूर्व सरपंच निवास सिंह, रूपेश सिह, सचिव महेन्द्र शर्मा, मनोज पासवान, नितीश कुमार सिंह, टुनटुन पोद्दार, ललन पंडित, पारो चौधरी, मुकेश तांती कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुये हैं.

कीर की गजल पर श्रोता हुए दिवाना

गोगरी अनुमंडल के परबत्ता प्रखंड के नयागांव शिरोमणि टोला के प्रांगण में तीन दिवसीय चैती महोत्सव का आयोजन किया गया. बहिष्कृत हितकारी संगठन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में रेडियो सिंगर फणीभूषण के द्वारा तुम तो ठहरे परदेशी साथ क्या निभाओगे एवं गुलाम अली द्वारा गाये गये गजल हम तेरे शहर में आये है, मुसाफिर की तरह गायकी पर श्रोता मंच मुग्ध हो गये. इस मौके पर बहिष्कृत हितकारी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार ने गजल सम्राट फणीभूषण को शाल देकर सम्मानित किया. मौके पर जोरावरपुर पंचायत की मुखिया श्रीमति विमला देवी, सरपंच लक्ष्मी देवी के द्वारा कार्यक्रम का इद्घाटन किया गया. दुर्गा मंदिर संघ के अध्यक्ष कपिलदेव कुंवर , मुखिया प्रतिनिधि शंकर कुमार, धीरज कुमार, मिथिलेश राय, राजेश चौधरी, पुष्पम देवी सहित सैकड़ों दर्शक उपस्थित थे.

सब स्टेशन का कार्य प्रारंभ

गोगरी अनुमंडल के परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामानंद सिंह के द्वारा करना विद्युत सब स्टेशन का कार्य प्रारंभ का इद्घाटन किया गया. बिहार विद्युत स्टेशन के आंतरिक संसाधन के तहत 2009 के दिसम्बर माह में विधायक के द्वारा शिलान्यास किया गया था. लेकिन कुछ कानूनी अड़चन के कारण कार्य का शुभारंभ नहीं किया जा सका. इस मौके पर जयजयराम चौधरी, मिथिलेश कुमार, मंटु भगत उर्फ मनोज भगत,पारो चौधरी, मुकेश कुमार सिंह सहित दर्जनों जदयू कार्यकर्ता उपस्थित थे. **– गीता कुमार**

जिला अधिवेशन आयोजित

सीतामढ़ी जिले के उच्च विद्यालय बरियारपुर के सभागार में भारत मुक्ति मोर्चा का जिला अधिवेशन आयोजित किया गया. भरत चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम का संचालन पूर्व प्राचार्य राम एकबाल राय ने की. मौके पर बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर के प्रपौत्र मा. राज रत्न अंबेडकर ने कहा कि केंद्र की वर्तमान सरकार इवीएम द्वारा चुनी गयी घोटाला की सरकार है. कार्यक्रम में वामसेफ के राष्ट्रीय प्रचारक डीआर ओहैल, राष्ट्रीय महासचिव डॉ एस अकमल, चंद्रेश यादव, दिनेश यादव, कर्मवीर पासवान, ब्रहमदेव पासवान, प्रमुख रिंकु कुमारी, सत्येंद्र भंडारी, पुनीत बैठा, विन्देश्वर पासवान, राम जुलुम सिंह कुशवाहा, परमेश्वर सिंह, मुखिया जागेश्वर महतो, राम कैलाश ठाकुर, इंदल पासवान, हरिश्चंद्र पासवान, सुनीता भारती, हरदेव बैठा, मीरा देवी, प्रियंका कुमारी, सुरेंद्र महतो व उमेश महतो समेत अन्य थे.

कांग्रेस ने फूंका मंत्री का पुतला

अखिल भारतीय कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के विरुद्ध मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा किये गये टिप्पणी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोष व्यक्त किया. जिलाध्यक्ष विमल शुक्ला के नेतृत्व मे कार्यकर्ताओं ने सीतामढ़ी शहर के मेहसौल चौक पर जाम कर नारेबाजी की. साथ ही मंत्री का पुतला दहन किया. कार्यक्रम में शिवहर जिलाध्यक्ष मो. असद, संजय कुमार, सत्येंद्र कुमार तिवारी, सीताराम झा, परवेज आलम अंसारी, पुष्पांजलि कुमारी, शिव शंकर शर्मा, सीमा गुप्ता, मणि भूषण कुमार, नन्हे अंसारी, डॉ. भुवनेश्वरी मिश्र, अंजारुलहक तौहिद, नागेश्वर तिवारी, सुरेश रजक, रितेश मोहन, डॉ मोबिनुल हक, रणधीर कुमार सिंह, नंदकिशोर साह व वीरेंद्र कुशवाहा समेत अन्य थे.■ **– विकास**

प्यार हुआ, इकरार हुआ !

राधिका

feedback@chauthiduniya.com

प्यार तो हर कोई करता है लेकिन खगड़िया के पूर्व विधायक रणवीर यादव की प्रेम कहानी दूसरी प्रेम कहानियों से जुदा है या यूं कहें कि जुदा होने के साथ–साथ बहुत दिलचस्प भी है. रणवीर ने दो शादियां की हैं. उनकी पहली पत्नी का नाम पूनम है और दूसरी पत्नी का नाम कृष्णा. कृष्णा रिश्ते में रणवीर की पत्नी होने के साथ–साथ उनकी साली भी हैं.

रणवीर अपनी पहली शादी के बारे में बताते हैं कि मेरी पहली शादी कुछ हद तक घरवालों के दबाव में आकर हुई थी. रणवीर आगे कहते हैं कि जब मैं महज 25 साल का था तभी से मेरे लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे. लेकिन मेरे लिए चिंता का विषय ये था कि तब मुझपर कई केस मुकदमें दर्ज थे. मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो मेरे बारे में सबकुछ जानकर भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो. इसी क्रम में एक दिन पूनम का रिश्ता मेरे लिए आया, और पूमन के घर से हमारे अच्छे रिश्ते थे इसलिए हम लोगों ने उनके रिश्ते को तरजीह दी. उसके बाद बात हुई पूनम को देखने की. रणवीर आगे कहते हैं कि मैंने पूनम को स्कूल से आन–जाने के दौरान में देखने का फैसला किया. लेकिन ऐसा हो न सका और हमारी मुलाकात पूनम के मामा के घर पर हुई. इस मुलाकात में मैंने पूनम से एक सवाल पूछा कि क्या आप मेरे बारे में सब कुछ जानती हैं, तो उनका जवाब आया कि हां मैं सब कुछ जानती हूं और फिर भी आपसे शादी करने को तैयार हूं. पूनम के इस जवाब ने कहीं ना कहीं मेरे मन को छू लिया. फिर मेरे घरवालों ने ये फैसला लिया कि अब मैं पूमन के मामाजी के घर से शादी कर के हीं जाउंगा. फिर उसी दिन हमारी शादी हो गई. मेरी बारात पूनम जी के मामाजी के घर से निकल कर मेरे ससुर के घर गई थी. इस तरह मेरी पहली शादी पूनम से हो गई.

लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है. रणवीर ने जब अपनी और पूनम की शादी में पूनम की छोटी बहन कृष्णा को देखा तो उनको ऐसा लगा कि काश उन्हें पूनम की जगह कृष्णा से मिलवाया गया होता, तो अच्छा होता. लेकिन मेरी शादी तो पूनम से हो गई थी इसलिए मैंने अपने अंदर आए इस प्यार के सैलाब को दबा दिया और इस बात को वहीं खत्म कर दिया.

रणवीर आगे बताते हैं कि कृष्णा को खेल में बहुत रुचि थी. वो नेशनल चैंपियन भी रह चुकी हैं. मैं भी खेल में रुचि रखता था. इस वजह से मेरा उनकी तरफ आकर्षण और बढ़ गया. पूनम से शादी के करीब 9 महीने बाद मुझ पर गोली चलाई गई थी. अपने बचाव में मैंने और मेरे साथियों ने भी गोली चलाई थी. इसी गोलीबारी में विरोधी दल के कुछ लोग मारे गए थे. इसकी सजा के तौर पर हमें जेल भेज दिया गया था. इसी दौरान जेल से ही मैंने चुनाव जीता था. इसी दौरान कृष्णा, जो रांची में रहती थीं, मुझसे और पूनम से मिलने आईं थीं. इस वक्त तक मेरी और कृष्णा से मेरे उनसे प्रेम के बारे में कोई बात नहीं हुई थी.

साल 1992 में कृष्णा के पैर में चोट लगी थी, तब उन्हें डॉक्टर से मैंने हीं दिखाया था. डॉक्टर को दिखाने के बाद जब वो वापस रांची जाने लगीं तो मैं ही उन्हें रेलवे स्टेशन छोड़ने गया था. रणवीर बताते हैं कि जैसे ही ट्रेन चल पड़ी वैसे ही अचानक मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे. ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे मेरे प्राणों को कोई अलग कर रहा हो. कृष्णा ने मुझे रोते हुए देख लिया. इस प्रकरण के बाद जब मेरी कृष्णा से बात हुई तब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं रात भर सो नहीं पाई. सोचती रही कि आप रो क्यूं रहे थे. इतना कहते–कहते कृष्णा की भी आंखें भर आईं और रोते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा लगता है कि मुझे आपसे प्यार हो गया है. इसके बाद हमारी फोन पर बात शुरू हो गई.

लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. मुझे हाई कोर्ट ने 20 साल की सजा सुना दी. मुझे 20 साल की जेल हो गई. इसके बाद कृष्णा रांची से पटना मुझसे मिलने आई थीं. उस मुलाकात के बाद मेरा प्यार कृष्णा के लिए और गहरा हो गया. मुझे लगा कि कृष्णा ने सिर्फ सुख में ही नहीं दुख में भी मेरा साथ दिया है. पर ऐसी बातें ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकतीं. धीरे– धीरे लोगों को ये बात पता चलने लगी कि मेरे और कृष्णा के बीच कुछ तो चल रहा है. इस बात का पता चलने के बाद कृष्णा के घर वालों ने उन पर शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया. कृष्णा ने तय कर लिया था कि वो मुझसे हीं शादी करेंगी. इसी बीच मैं जेल से छूट गया और मैंने और कृष्णा ने गुपचुप शादी कर ली.

हमने शादी तो कर ली थी, और अब बारी थी पूनम को मनाने की. 1992 में पूनम ने एमपी का चुनाव लड़ा था और इसी दौरान उन पर हमला हुआ था जिसमें उनके हाथ में काफी चोट लगी थी. पूनम की सारी देख रेख मैंने और कृष्णा ने ही की थी. इस बात से पूनम इतनी प्रभावित हुईं कि जब मैंने और कृष्णा ने उन्हें हमारी शादी के बारे में बताया तो उन्होंने इस बात को हंसते–हंसते स्वीकार कर लिया. आज हम लोग हंसी–खुशी चैन से अपनी जिंदगी जी रहे हैं.■

ठेकेदार बन करोड़ों रुपये हजम कर गये गुरु जी

जय मंगल पांडेय

बक्सर जिले मे विद्यालयों के भवन निर्माण के ठेकेदार बने गुरुजी सरकार के करोड़ों रुपये हजम कर बैठ गये. आठ वर्षों मे न भवन बना और न विभाग को रुपये वापस किये. हद तो यह है कई गुरुजी रिटायर भी हो गये और शिक्षा विभाग के अधिकारी गहरी निद्रा में सोये रहे. मातहत अधिकारियों की काली करतूत तथा भ्रष्टाचार से लाचार जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पूरी तरह बेकार बताते हुए प्रधान सचिव तक शिकायत भेज दी है.

बक्सर जिले मे शिक्षा विभाग के अधिकारियों की काली करतूत, मनमानी तथा भ्रष्टाचार के किस्से अनंत है. आला अधिकारियों के आदेश को दरकिनार कर शिक्षा विभाग के अधिकारी अपनी ही मनमर्जी चलाते हैं. परिणाम स्वरूप यहां की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त तथा विभाग की योजनाएं लूट–खसोट की शिकार हो गयी हैं. एक तो राज्य सरकार ने शिक्षकों को भवन निर्माण का ठेकेदार बना कर शिक्षा व्यवस्था को पंगू कर दिया. विभाग की मैनेज संस्कृति से ठेकेदार बनकर गुरुजी विधालय भवन निर्माण का रुपये ही हजम कर गये. वर्ष 2006–07 से 2012–13 में विद्यालय भवन, किचेन शेड तथा शौचालय बनाने के नाम पर शिक्षा विभाग द्वारा करोड़ों रुपये प्रारंभिक विद्यालय के प्रभारियों को दे दिया गया. ऐसे लगभग 90 स्कूल हैं. लेकिन आठ–नौ वर्षो मे भी इन विद्यालयों का भवन निर्माण नहीं कराया गया. करोड़ों रुपये हजम कर गुरुजी कई तरह की बहानेबाजी कर मामले को टालते रहे. कहीं पर ग्रामीणो का विरोध तथा कहीं शिक्षा समितियों व प्रभारियों के आपसी विवाद के भरोसे निर्माण पर ग्रहण लगने का तर्क दिया गया. लेकिन विभाग के अधिकारियों ने इसमें दिलचस्पी नहीं ली. लिहाजा गुरुजी बहानेबाजी कर सरकारी रुपये दबा कर बैठे रहे. लेकिन विभाग के अधिकारियों ने न आज तक इसकी खोज–खबर भी नहीं ली. हद तो यह है कि रुपये हजम कर कई गुरुजी रिटायर भी हो गये. सरकारी रुपये से गुरूजी का भले ही काया कल्प हो गया और दूसरी ओर नौनिहाल आसमान या पेड़ों के नीचे पढ़ते रहे. विभागीय कामकाज में अक्षम अधिकारियों से लाचार जिलाधिकारी रमण कुमार कहते है कि जिले मे शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी बेकार हैं. किसी भी अधिकारी मे अधिकारी लायक गुण नहीं हैं. उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि रुपये हजम करने वाले शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज करायी जाएगी और सेवा मुक्त भी किया जाएगा. इन अधिकारियों के विरुद्ध मानव संसाधन विभाग के प्रधान सचिव के पास शिकायत भेजने वाले डीएम की संवेदन शीलता से सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि बक्सर में शिक्षा व्यवस्था कितनी बदतर हो गयी है. भवन के अभाव में लगभग सौ से अधिक विद्यालय एक ही भवन में दो शिफ्टों में चलते हैं. ऐसे विद्यालयो में पठन–पाठन के बदले रोज हंगामा तथा विवाद होता रहता है. शिक्षा विभाग की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई. एक सच्चाई यह भी है कि विभाग के अधिकारियों की मेहरबानी से बड़े पैमाने पर फर्जी शिक्षक बहाल हो गये और आज तक उनके प्रमाणपत्रों की जांच नहीं हुई जानकार बताते है कि वर्ष 2003 से लेकर 2014 तक नियुक्त किये गये नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र फाइलों में धूल चाट रहे हैं. आज तक संबंधित संस्थानो से इसका सत्यापन नहीं कराया गया. शिक्षा विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही का ही परिणाम है कि बक्सर जिले में फर्जीवाड़े का खेल बंद नहीं हुआ. जब कभी मामला उच्च स्तर तक पहुंचा, तो विभाग से सारा रिकॉर्ड ही गायब कर दिया गया. वेतनमान पर भी फर्जी नियुक्त का मामला पूर्व मे उजागर हो चुका है. तात्पर्य यह कि मैनेज संस्कृति के बल पर शिक्षा विभाग मे कोई भी कार्य असंभव नही है.■

feedback@chauthiduniya.com

Mob. : 9386745004, 9204791696
www.iiher.org,
Email : anilsulabh6@gmail.com

INDIAN INSTITUTE OF HEALTH EDUCATION & RESEARCH
Health Institute Rd, Beur (Near Central Jail), Patna -2.
(Recongnised by Govt. of Bihar, RCI, Govt. of India, IAP & ISPO)
AFFILIATED TO MAGADH UNIVERSITY, BODHGAYA

POST GRADUATE COURSES :

Name of Courses		Eligibility	Duration
MPT	Master of Physiotherapy	BPT	2yrs.
MOT	Master of Occupational Therapy	BOT	2yrs.
DEGREE COURSES			
BPT	Bachelor of Physiotherapy	I.Sc (Bio)	4yrs.+6 Months of Internship
BOT	Bachelor of Occupational Therapy	I.Sc (Bio)	4yrs.+6 Months of Internship
BPO	Bachelor of Prosthetic & Orthotic	I.Sc	4yrs.+6 Months of Internship
BASLP	Bachelor of Audiology & Speech Language Pathology	I.Sc	3yrs.+1 year of Internship
BMLT	Bachelor of Medical Laboratory Technology	I.Sc	3yr.+6 Months of Internship
BMRIT	Bachelor of Radio Imaging Technology	I.Sc	3yrs.+6 Months of Internship
B.Ophth.	Bachelor of Ophthalmology	I.Sc	4yr.+6 Months of Internship
B.Ed.	(Special Education)	Graduate	1yr.
1 YEAR ABRIDGED DEGREE FOR DPT / DOT			
DIPLOMA COURSES :			
DPT	Diploma In Physiotherapy	I.Sc (Bio)	3yrs.+6 Month of Internship
D-X-Ray	Diploma In X-Ray Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DMLT	Diploma In Medical Laboratory Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DECG	Diploma In E.C.G.	I.Sc (Bio)	2yr.
DOTA	Diploma In O.T. Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DHM	Diploma In Hospital Management	Graduate	1yr.
CMD	Certificate in Medical Derssing	Matirc with Science & English	1yr.

ADMISSION OPEN

Form & Prospectus -
Can be obtained from the office against a payment of Rs. 500/-. only by cash. Send a DD of Rs. 550/- only in the favour of Indian Institute of Health Education & Research, Patna, for postal delivery.

डा. अनिल सुलभ
निदेशक प्रमुख

"टी.आई." ब्राण्ड शटरपत्ती
क्वालिटी में सर्वोत्तम

मजबूती हमारी सुरक्षा आपकी.....

AL अलीगढ़ लॉक्स TM प्रा.लि.

पीरमुहानी,जगत जननी माता मन्दिर के नजदीक, पटना–3
फोन : 0612-3293208, 6500301, Email : aligarhlocks@gmail.com
अपने क्षेत्र बिहार का प्रथम एवं एकमात्र TM प्रतिष्ठान नक्कालों से सावधान
कृपया हमारे इस नाम से मिलते–जुलते प्रतिष्ठान को देख भ्रमित न हों।

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

20 अप्रैल–26 अप्रैल 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड

सरकार कर्मचारियों को डिमोट करेगी

आरक्षण पर सियासत

सूफी यायावर

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले तरक्की में आरक्षण का मसला खड़ा हो गया है. राजनीति के विशेषज्ञों का मानना है कि यह मसला सोच-समझ कर खड़ा किया गया है. वोटों का ध्रुवीकरण करने और भाजपा को धक्का देने की रणनीति कहीं न कहीं साझा समझ पर तैयार की गई लगती है. एक तरफ सपा ने झंडा उठा रखा है, तो दूसरी तरफ बसपा ने अचानक परिदृश्य में कूद कर झंडा उठा लिया है. तरक्की में आरक्षण के मसले पर भाजपा दर्शकदीर्घा में खड़ी दिख रही है. लेकिन राजग से जुड़े रामविलास पासवान इस मसले में दलितों के साथ खड़े होने का प्रहसन जरूर खेल रहे हैं. वे इस बात की वकालत कर रहे हैं कि दलितों को तरक्की में भी आरक्षण का फायदा मिले. उनका कहना है कि इसे लागू कराने के लिए मोदी सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में ही मसौदा रखा गया था. यह मसौदा स्टैंडिंग कमेटी में चला गया है. पासवान ने उम्मीद जताई है कि दलितों को तरक्की में भी आरक्षण के लिए केंद्र से भी जल्दी ही मंजूरी मिल जाएगी. इस मसले में तो समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से ही अपनी स्पष्ट लाइन निर्धारित कर रखी है. सपा की स्पष्ट राय रही है कि आरक्षण का फायदा उठा कर नौकरी पाने के बाद तरक्की में भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए. बल्कि तरक्की केवल योग्यता के आधार पर मिलनी चाहिए. तरक्की में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू हो गई तो प्रशासन तंत्र में अराजकता का सृजन हो जाएगा. सपा की इस नीति का उसे फायदा यह मिला कि सवर्ण और पिछड़ी जाति के लोग इस मुद्दे पर सपा की तरफ हो गए. इसमें पिछड़े समुदाय से यह मांग भी उठी कि तरक्की में दलितों को आरक्षण का फायदा मिले तो पिछड़ों को भी वह सुविधा मिले.

उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीमकोर्ट को बताया है कि प्रदेश में 2007 के कानून के मुताबिक तरक्की में आरक्षण पाए कर्मचारियों की लिस्ट तैयार की जा रही है. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के हिसाब से ही सरकार ने नीतिगत फैसला लिया है. ऐसे कर्मचारी जिनकी तरक्की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बाकी है, उन्हें तरक्की दी जाएगी और जिनकी तरक्की का मसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दायरे से बाहर है, उन्हें पूर्व के पदों पर वापस कर दिया जाएगा. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2007 में मायावती सरकार ने तरक्की में आरक्षण के प्रावधान का कानून पारित कर दिया था. इस कानून को कोर्ट में चुनौती दी गई थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तरक्की में आरक्षण की व्यवस्था को खारिज कर दिया था. मायावती सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था. सुप्रीमकोर्ट ने कहा था कि तरक्की में आरक्षण सुप्रीमकोर्ट के इंदिरा साहनी मामले में दिए गए बृहद बेंच के फैसले के हिसाब से ही होगा. इसके बाद सिंचाई विभाग के दो इंजीनियरों ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल कर कहा था कि कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक सरकार कुछ नहीं कर रही है. यहां तक कि उसने कोई लिस्ट भी जारी नहीं की है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

वोट की सियासत में भारतीय लोकतंत्र में योग्यता और स्तरीयता की बातें बेमानी हो गई हैं. राज चलाने वाले राजनीतिकारों को तो इसकी कोई चिंता ही नहीं कि देश कैसे चले और दुनिया में देश की योग्यता का मानक कैसे स्थापित हो. सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ढक्कन करने के लिए 2012 में यूपीए सरकार 117वां संविधान संशोधन का प्रस्ताव ले आई, इसके साथ संविधान का अनुच्छेद 16 (4) (ए) जोड़ने का प्रस्ताव किया गया. कहा गया कि अनुच्छेद 335 राज्य सरकारों को ऐसा कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगा, जिसमें वह दलितों को तरक्की में आरक्षण और परिणामी-ज्येष्ठता का लाभ देना चाहती हो. चूंकि यूपी सरकार ने 1995 में यह नियम लागू किया था, इसलिए संशोधन विधेयक को 17 जून, 1995 से लागू करने का प्रावधान किया गया. राज्यसभा से विधेयक पास हो गया लेकिन वह लोकसभा में अटका हुआ है. तरक्की में आरक्षण लाने या उसे हटाने के सियासी नफा-नुकसान के बरक्स सरकारी कर्मचारियों में साफ-साफ विभाजन हो गया, जिसका असर भी विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा.

तरक्की में आरक्षण के मसले को सियासी तवे पर रख कर भुनने-भुनाने में समाजवादी पार्टी का रुख शुरू से ही साफ रहा है. हाईबरनेशन में जा चुकी बसपा को भी सुरंग से बाहर निकलने का मौका मिल गया है. भाजपा का उहापोह जारी है. कांग्रेस अपनी चालाकी से बाज नहीं आ रही. हर बात पर प्रतिक्रियाएं देने में आगे रहने वाले भाजपा प्रवक्ताओं की भीड़ इस मसले पर चुप्पी साधे है. आरक्षण मसले से प्रदेश के 22 लाख कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपना नफा-नुकसान तौलने और उसका आकलन करने में लगी हैं. पिछले विधानसभा चुनाव

के दौरान भी तरक्की में आरक्षण का मुद्दा गरमाया था. सपा ने इसे खत्म करने का वादा किया था. 2012 में इस कानून पर आए संविधान संशोधन के विरोध में संसद में सपा अकेली थी. अब विधानसभा चुनाव फिर से सिर पर है तो दो साल पहले यह मसला फिर उभर कर सियासी पटल पर आ गया है. परिणामी ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति पाए लोगों को पूर्व के पदों पर वापस करने का निर्णय जितना अमल में आता जाएगा, सियासत उतनी ही गरमाती जाएगी. इस मसले पर सपा का रुख और उसके वोट बैंक का समर्थन दोनों ही स्पष्ट है. बसपा इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश में है. बसपा सुप्रीमो मायावती इसे हवा देने के लिए अचानक मैदान में सक्रियता से कूद पड़ी हैं. राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कहना शुरू किया कि सपा सरकार का फैसला दलित विरोधी है. लेकिन कांग्रेस और भाजपा का धर्मसंकट कुछ अधिक ही बढ़ गया है. जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने के लिए कांग्रेस सरकार ही संशोधन विधेयक लेकर आई थी. लेकिन आज सरकार से अलग हो चुकी कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे से कन्नी काट रही है. लोकसभा में दलित वोट जोड़ने में सफल रही भाजपा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी इसे अपने साथ रखना चाहती है. भाजपा का धर्मसंकट यह है कि अगर वह फैसले का विरोध करती है तो सवर्ण-पिछड़ा वोट बिदकेगा और समर्थन करती है तो उस पर दलित विरोधी होने का ठप्पा लग सकता है. ऐसे में पार्टी की चुप्पी ही उसकी बेहतर रणनीति है.

तरक्की में आरक्षण का फायदा पाए प्रदेश के राज्य कर्मचारियों में इस वक्त फिर से पुराने पद पर जाने का खौफ समाया हुआ है. परिणामी ज्येष्ठता के आधार पर 15 साल में हुई तरक्कियां रद्द हुईं तो लगभग दो लाख कर्मचारियों को पुराने पदों पर लौटना पड़ेगा. दिलचस्प तो यह भी है कि इसमें से हजारों कर्मचारी रिटायर भी हो चुके हैं. सरकार ने उन कर्मचारियों को वित्तीय नुकसान न हो इसके लिए उनकी आर्थिक सुविधाओं को बहाल रखने का फैसला किया है. लेकिन इस व्यवस्था के लागू होने पर विभागों के प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव और उससे होने वाले भूचाल की आशंकाओं को नकारा नहीं जा सकता है.

उल्लेखनीय है कि कार्मिक विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आधार बनाकर कहा है कि 15 नवंबर 1997 के बाद पदोन्नति में आरक्षण का लाभ और परिणामी ज्येष्ठता प्राप्त कर जिन कर्मचारियों ने तरक्की पाई है, उन्हें पूर्व के पदों पर वापस भेज दिया जाए. यह पदावनति उस पद के स्तर तक होगा जहां तक उनके समकक्ष कर्मचारी जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, आज भी काम कर रहे हैं. सपा सरकार ने अपने चुनावी एजेंडे में प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने की बात कही थी. चूंकि परिणामी ज्येष्ठता के आधार पर प्रमोशन 2012 तक हुआ था इसलिए सभी विभागों में इन 15 सालों में प्रमोशन पाने वाले कर्मचारी प्रभावित होंगे. कर्मचारी संगठनों के मुताबिक शिक्षा विभाग में ही ऐसे 30 हजार कर्मचारी हैं. सिंचाई विभाग में महज 30 इंजीनियरों के पदावनत होने की बात आ रही है, लेकिन वह केवल ए श्रेणी के पदों को लेकर है. यह आदेश सभी श्रेणी के पदों पर लागू होना है इसलिए संख्या और बढ़ेगी. नई सीनियरिटी लिस्ट बनने के बाद जो सीनियर बने थे वह समकक्ष या जूनियर हो जाएंगे. कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इसका असर आपसी सामंजस्य और काम पर पड़ेगा. आरक्षण का मसला राजनीतिक दलों के अलावा कर्मचारी नेताओं के लिए भी प्रतिष्ठा का मसला बन गया है.

प्रदेश के सारे सरकारी विभाग फिलहाल राजनीतिक भिड़ंत का अखाड़ा बन गए हैं. कामकाज के बजाय आरक्षण समर्थन और विरोध में बैठकें, सभाएं, प्रदर्शन और ज्ञापनबाजियां ही हो रही हैं. समर्थक और विरोधी, दो खेमों में बंटे सरकारी कर्मचारी अपनी-अपनी रणनीति बनाने में ही व्यस्त हैं. तरक्की में आरक्षण का विरोध कर रही सर्वजन हिताय संरक्षण समिति सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करो नाम से विशाल संकल्प सभा आयोजित कर रही है तो आरक्षण समर्थक कर्मचारियों ने भी काली पट्टी लगा कर काम करने के अलावा सम्मेलन करने और सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने की रणनीति बनाई है. तरक्की में आरक्षण का विरोध करने वाले संगठनों ने यह भी मांग शुरू की है कि तरक्की में अगर दलितों को आरक्षण की सुविधा मिले तो पिछड़ों को क्यों नहीं मिले. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुपालन में पदावनत से रिक्त होने वाले पदों पर पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों को नियुक्त किए जाने की मांग भी साथ-साथ उठने लगी है. कुल मिला कर प्रदेश का माहौल वैसा ही अराजक बन रहा है, जैसा राजनीतिक दल चाहते हैं.

आरक्षण मुहिम में पासवान भी जुटे

राजग सरकार में केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तरक्की में आरक्षण लागू करने की मांग कर रहे हैं. मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लोजपा की दलित महापंचायत में पासवान ने कहा कि सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के चलते प्रमोशन में आरक्षण खत्म हुआ था. पासवान ने मोदी को दलितों-पिछड़ों का सच्चा हितैषी बताते हुए कहा कि यूपीए सरकार में संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर के स्मारक को भी जगह नहीं मिली थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार को केंद्र सरकार ने बाबा साहब के स्मारक के लिए राजी कर लिया. दलित महापंचायत में निजी क्षेत्र में आरक्षण, प्रोन्नति में आरक्षण के लिए संसद से बिल पास कराकर कानून बनाने की मांग जैसे पांच प्रस्ताव पारित किए गए.

सुप्रीमकोर्ट ने क्या कहा था

19 अक्टूबर 2006 को एम नागराज केस में संविधान पीठ के फैसले को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केवल तीन आधार पर ही तरक्की में आरक्षण दिया जा सकता है. सरकारी सेवा में अगर दलित कम हों, अधिकारियों को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा हो और जिससे काम-काज पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़े. लिहाजा, जो प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया उसके तहत जो भी प्रमोशन हुए वह भी अवैध हो गए. इसलिए उसे वापस करने का फैसला लिया गया. प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अम्बिका चौधरी ने कहा कि इस निर्णय से कर्मचारियों को कोई आर्थिक नुकसान नहीं होने दिया जाएगा.

ऐसे खुला मामला

पिछले दिनों होमगार्ड विभाग और पुलिस विभाग में कुछ अधिकारी पदावनत किए गए थे. यह आरक्षण के आधार पर मिले प्रमोशन को रद्द करने की कवायद के तहत ही किया गया था. इसे विभागीय आदेश बताकर दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सुगबुगाहटों और गुफ्तगू ने मामला खोल दिया. सरकार ने व्यापक विरोध और आंदोलन उठने की आशंका को देखते हुए ही सभी विभागों के लिए एक सामान्य आदेश नहीं जारी किया था. जबकि लगभग सभी विभागों में अंदर ही अंदर पदावनति और तरक्की दोनों की सूची तैयार कराई जा चुकी थी.

हड़ताल पर चले जाएंगे 16 लाख कर्मचारी

आरक्षण विरोधियों की ओर से सर्वजन हिताय संरक्षण समिति के अध्यक्ष शैलेन्द्र दुबे ने चेतावनी दी है कि लोकसभा में लंबित संविधान संशोधन बिल अगर पारित करने की कोशिश की गई तो प्रदेश के 16 लाख कर्मचारी बिना किसी नोटिस के हड़ताल पर चले जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की कोशिश की गई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे. समिति ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की है. भाजपा इस मुद्दे पर अब तक चुप है. लेकिन एक तरफ केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान तो दूसरी तरफ मोहनलालगंज के भाजपा सांसद कौशल किशोर प्रमोशन में आरक्षण के समर्थन में खुलेआम उतरे हुए हैं. आरक्षण समर्थकों ने कहा है कि 10 दिनों में आरक्षित सीटों पर निर्वाचित विधायकों-सांसदों ने अपना रुख साफ नहीं किया तो उनके ही इलाके में विरोध-सम्मेलन शुरू हो जाएंगे. आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के अवधेश वर्मा का दावा है कि वे कई जनप्रतिनिधियों के संपर्क में हैं.

सपा साध रही अंबेडकर को

तरक्की में आरक्षण के मसले पर समाजवादी पार्टी के स्टैंड से दलितों की नाराजगी को देखते हुए सपा ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को साधना शुरू कर दिया. सपा के अपने विचार-महा-पुरुष डॉ. राम मनोहर लोहिया की जयंती पर सरकार ने धन खर्च नहीं किए, लेकिन प्रदेशभर में अंबेडकर जयंती मनाने के लिए सरकारी खजाना खोल दिया गया 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाने के लिए सरकार ने प्रत्येक जिले को 35-35 हजार रुपये दिए. इसके लिए 75 जिलों को कुल 26,25,000 रुपये दिए गए थे. ■

feedback@chauthiduniya.com

उत्तर प्रदेश की खबरें इंटरनेट पर पढ़ने के लिए www.up.chauthiduniya.com लॉगऑन करें.

आतंकियों की पनाहगाह बना लखनऊ

दीनबंधु कबीर

बाहर के वित्तीय स्त्रोंतो पर सख्ती हो जाने के कारण देश में ऑपरेट कर रहे आतंकी संगठन स्थानीय अपराधियों के साथ मिल कर बड़ी लूटों को अंजाम दे रहे हैं. तेलंगाना मुठभेड़ में मारे गए सिमी के आतंकियों के लखनऊ एटीएम लूटकांड में शामिल होने का मामला उजागर होने के बाद आतंकी संगठनों की इस रणनीति का खुलासा हुआ है. लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशस्वी यादव ने इसकी आधिकारिक पुष्टि करते हुए कहा कि तेलंगाना में सिमी के जिन दो आतंकवादियों को चार फरवरी को नलगोंडा मुठभेड़ में मारा गया था, वे लखनऊ एटीएम लूट में शामिल थे. तेलंगाना पुलिस की ओर से जारी प्रेस नोट में भी उन दोनों आतंकियों के लखनऊ एटीएम लूटकांड से जुड़े होने का शक जताया गया है. यूपी पुलिस की एक टीम घटनाक्रम को विस्तार से जानने के लिए तेलंगाना गई है. मुठभेड़ में मारे गए मोहम्मद एजाजुद्दीन और मोहम्मद असलम सिमी के उन सात आतंकवादियों में शामिल थे, जो पिछले साल 13 अक्टूबर को मध्यप्रदेश की खंडवा जेल से फरार हो गए थे. इन्हीं आतंकियों ने बिजनौर विस्फोट और पश्चिम बंगाल में विस्फोटों समेत कई अन्य वारदातों को अंजाम दिया था. एजाजुद्दीन मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर का रहने वाला था और असलम खंडवा का निवासी थी, लेकिन इन लोगों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बाद में लखनऊ को अपना अड्डा बना रखा था.

लखनऊ की वह अत्यंत सनसनीखेज घटना थी, जब इन आतंकियों ने बैंक का धन लेकर आए तीन लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी और 51 लाख रुपये लूट कर मोटरसाइकिल से भाग गए थे. दोपहर में जिस समय आतंकी मोटर साइकिल से आए थे, उस समय लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर के नजदीक हसनगंज क्षेत्र में बाबूगंज स्थित एचडीएफसी बैंक के एटीएम में रुपये डाले जा रहे थे. तेलंगाना मुठभेड़ में मारे गए दोनों आतंकियों ने मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों में बैंक डकैती, एटीएम लूट व हत्याओं को अंजाम दिया था. तेलंगाना पुलिस के इस खुलासे के बाद खुफिया एजेंसियों के साथ-साथ लखनऊ की स्थानीय पुलिस और स्थानीय खुफिया इकाई की बोलती बंद है, क्योंकि एटीएम लूटकांड के बाद जिस तरह के तर्क दिए जा रहे थे और जिस दिशा में छानबीन की जा रही थी, वह सब बेबुनियाद साबित हुए हैं. अब तो यह सवाल खड़ा हो गया है कि खंडवा जेल से भागने के बाद इतने शातिर आतंकियों ने बिजनौर और फिर लखनऊ को अड्डा बना रखा था और खुफिया इकाई निश्िंचत बैठी हुई थी. इस खुलासे के बाद न केवल लखनऊ पुलिस, बल्कि राजधानी लखनऊ में नीली बत्ती वाले वे तमाम अधिकारी, जो एंटी टेररिस्ट स्क्वैड, स्पेशल टास्क फोर्स, सर्विलांस सेल, एलआईयू, क्राइम ब्रांच जैसे महकमों की कुर्सियां तोड़ते हैं, कठघरे में खड़े हैं. लेकिन इन नौकरशाहों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता.

आतंकियों के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद जो खुलासा हुआ है उसने खुफिया एजेंसियों को एक बार फिर अपने काम-काज के तौर तरीकों पर सोचने पर मजबूर कर दिया है. अब एजेंसियां उन अपराधी गिरोहों पर निगरानी रखने का टास्क तैयार कर रही हैं जो आतंकी संगठनों से जुड़ कर उनके लिए फंड जुटाने या उनकी भाषा में माल-ए-गनीमत' जुटाने के लिए काम कर रहे हैं. खुफिया एजेंसियों ने अपराधों को अब इस एंगल से भी देखना शुरू किया है. तेलंगाना पुलिस का कहना है कि लखनऊ एटीएम लूट के पहले फरवरी 2014 में तेलंगाना में हुए बैंक लूट कांड में भी ये आतंकी शामिल थे. पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में हुए विस्फोट के बाद वहां जांच के लिए पहुंची एनआईए की टीम ने उस समय भी यह संदेह जाहिर किया था कि मध्यप्रदेश के खंडवा जेल से फरार हुए आतंकियों ने तेलंगाना के करीमनगर में फरवरी 2014 में स्टेट बैंक में डकैती डाली थी. इसी डकैती में लूटी गई रकम का इस्तेमाल बिजनौर और बर्दवान में बम बनाने के लिए किया जा रहा था. दोनों ही जगह बम बनाते समय विस्फोट हुआ था.

सिमी और इंडियन मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों को इधर हुई सख्ती के कारण पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से फंड मिलने में मुश्किलें हो रही हैं. इस वजह से आतंकियों ने स्थानीय अपराधी गिरोहों से सम्पर्क बना कर बड़ी लूटों को अंजाम देने की रणनीति तैयार की है. अब तो यह भी खुलासा हुआ है कि पटना धमाके के लिए भी माल-ए-गनीमत' से ही पैसा दिया गया था. पटना ब्लास्ट के मामले में रांची से पकड़े गए आतंकियों ने पूछताछ में बताया था कि पटना में नरेंद्र मोदी की रैली में धमाका करने के लिए पांच लाख रुपये मिले थे. यह पैसा उन्हें भोपाल में मन्नापुरम गोल्ड फाइनैंस कंपनी में हुई ढाई करोड़ की लूट की रकम से मिला था. आतंकियों को यह पैसा खंडवा जेल से फरार आतंकी अबू फैसल ने दिया था. अबू फैसल खुद भी इस लूट में शामिल था. अबू फैसल और बिजनौर से फरार आतंकियों ने मध्यप्रदेश में अंजाम दी गई बैंक लूट की वारदातों से काफी पैसा इकट्ठा कर लिया था. इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी असदुल्लाह अख्तर उर्फ हड्डी ने पूछताछ में खुलासा किया है कि इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापकों में से एक मिर्जा बेग ने माल-ए-गनीमत' की शुरुआत दुबई से की थी.

तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक अनुराग शर्मा ने उत्तर प्रदेश पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं. जानकारी के मुताबिक़ मारे गए दोनों आतंकियों ने वर्ष 2009 में खंडवा के भाजपा नेता प्रमोद तिवारी पर फायरिंग की थी. उसी साल फरवरी महीने में असलम, महबूब, अमजद और अबू फैसल ने खंडवा के एक व्यापारी से 60 हजार रुपये लूटे थे. सितम्बर 2009 में अबू फैसल, अमजद, जाकिर, महबूब और असलम ने देवास के नर्मदा ग्रामीण बैंक से सवा लाख रुपये लूटे और फिर इन्हीं आतंकियों ने अगले ही महीने उसी देवास में बैंक ऑफ इंडिया से साढ़े नौ लाख रुपये लूट लिए. अक्टूबर 2009 में सतना के जेलर संजय पांडेय की हत्या और नवम्बर 2009 में खंडवा में सिपाही सीताराम यादव की हत्या में भी इसी आतंकी गिरोह का हाथ था. सितम्बर 2010 में अबू फैसल, एजाज, इकरार, मुजीब, जाकिर और असलम ने मिल कर मध्यप्रदेश के भोपाल टॉकीज स्थित मन्नापुरम गोल्ड फाइनैंस लिमिटेड की शाखा से 10 किलो सोना लूटा था. इसके अलावा इटारसी में केनरा बैंक, रतलाम में पंजाब नेशनल बैंक और इंदौर में स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया में हुई डकैतियों में भी यही गिरोह शामिल था. तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक का कहना है कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर और चेन्नई रेलवे स्टेशन पर बंगलौर-गुवाहाटी एक्सप्रेस में इन्हीं आतंकियों द्वारा विस्फोट किए जाने के सुराग मिले हैं. पुणे में जुलाई 2014 में गणपति मंदिर के नजदीक विस्फोट में भी इसी गिरोह का हाथ रहा है.

बहरहाल, लखनऊ पुलिस की टीम इस मसले का विस्तार से पता लगाने के लिए तेलंगाना पहुंच चुकी है. एएसपी क्राइम दिनेश कुमार सिंह व एटीएम लूटकांड की तफ्तीश कर रहे एसओ हसनगंज धीरज सिंह की टीम को नलगोंडा (तेलंगाना) भेजा गया है. एएसपी दिनेश सिंह ने भी कहा है कि मारे गए दोनों आतंकियों के फोटो और एटीएम लूट व हत्याकांड में शामिल बदमाशों के सीसीटीवी फुटेज में हुलिया मिल रहा है. दोनों आतंकियों का लखनऊ कनेक्शन निकालने के लिए चार साल पहले गोलागंज इलाके से उनकी गिरफ्तारी की खबरों पर पुराने रिकार्ड खंगाले जा रहे हैं. तेलंगाना में ढेर दोनों आतंकियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने, उनके मोबाइल का कॉल डिटेल व लोकेशन खंगालने व तेलंगाना की जांच एजेंसियों से उनके बारे में जानकारी करके नतीजा निकालने के आदेश दिए गए हैं. इस बात की भी छानबीन की जा रही है कि फरवरी में दोनों आतंकी कहां थे और किन-किन लोगों से बातें की थीं.

अफसर कम, पॉलिटिशियन ज्यादा हैं डीजीपी

अब देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस का असली चरित्र. तेलंगाना पुलिस की पुष्टि के बाद इस बारे में लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशस्वी यादव ने जैसे ही खबर जारी की, पुलिस के आला अधिकारी ही उन पर उंगलियां उठाने लगे. इसमें सरकार के कृपापात्र डीजीपी एके जैन कूद कर सबसे आगे हो लिए. तुष्टिकरण की सियासत उनकी वर्दी पर कुछ ज्यादा ही हावी दिखी. डीजीपी जैन ने तेलंगाना पुलिस की सूचना को बिल्कुल ही आधारहीन ठहरा दिया. उनके इस बयान पर एक आला पुलिस अधिकारी ने ही कहा कि जब डीजीपी को असलियत पता थी, तो वे उसे छुपाए क्यों बैठे हैं? जैन ने कहा कि उन्होंने मध्यप्रदेश के डीजीपी, आईजी और खंडवा के एसएसपी से बात की. किसी की भी बात से यह साबित नहीं हो रहा कि उन्हीं आतंकियों ने लखनऊ में लूटपाट की थी. जैन ने तेलंगाना के डीजीपी से बात करने की कोशिश नहीं की, जहां मुठभेड़ की घटना हुई और मारे गए आतंकियों के लखनऊ एटीएम लूटकांड से जुड़े होने की बात कही गई. ऐसा बयान जारी कर उत्तर प्रदेश के डीजीपी एके जैन को तेलंगाना पुलिस के महानिदेशक के साथ-साथ अपने मातहत काम करने वाले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी झूठा ठहराने में कोई संकोच नहीं हुआ. ■

feedback@chauthiduniya.com

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशस्वी यादव

आतंकियों की तरफदारी में संस्थाएं

तेलंगाना मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों के लखनऊ एटीएम लूटकांड में शामिल होने की खबर बताते ही डीजीपी के अलावा कई अन्य संस्थाएं भी लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पर हमला वार हो गईं. आतंकी गतिविधियों में लगे होने के आरोप में जेल में बंद कथित आतंकियों को रिहा कराने के लिए संघर्ष करने वाली संस्था रिहाई मंच ने तो यहां तक कह दिया कि सरकार एटीएम लूटकांड को आतंकवाद से जोड़कर पूरे सूबे में दहशत का माहौल बना रही है. मंच ने कहा कि एसएसपी यशस्वी यादव और एएसपी दिनेश यादव का ओहदे पर बने रहना अमन-चैन के लिए खतरा है. यह बयान इतना गंभीर है कि जैसे एसएसपी और एएसपी ही संदिग्ध हों और आतंकियों से अधिक उन्हीं से खतरा हो. रिहाई मंच तेलंगाना मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों को निर्दोष लड़के बता रहा है. इसी तर्ज पर समाजसेवी नूतन ठाकुर ने भी बयान जारी कर दिया और लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को हटाए जाने की मांग कर दी. उन्होंने तो सीधे-सीधे कह दिया कि एसएसपी यशस्वी यादव ने तेलंगाना में कथित आतंकियों के मारे जाने की घटना को एटीएम लूटकांड से जोड़ कर फर्जी तरीके से मामले को खोलने की कोशिश की है.

पुलिस की गलतबयानी

दो सिक्योरिटी गार्ड और एक कस्टोडियन की हत्या कर लाखों रुपये से भरा एटीएम कैश बॉक्स लूट लिए जाने के मामले में पुलिस का उस समय का तर्क कुछ और ही था. तेलंगाना अध्याय खुलने के बाद उन पुराने तर्कों को भी जानना जरूरी है. पुलिस को तब पता चला था कि बदमाशों ने दोनों हाथों से गोलियां चलाई थीं. यह सुराग मिलने के बाद स्पेशल टास्क फोर्स और लखनऊ पुलिस ने शातिर बदमाश ललितेश्वर द्विवेदी को सर्विलांस पर ले रखा था. पुलिस ने तब कहा था कि ललितेश्वर लूट के दौरान गोली मारने को शुभ मानता है. ललितेश्वर के अलावा ओसामा, रिजवान व छह अन्य गैंग के बारे में भी पुलिस पड़ताल कर रही थी. ललितेश्वर का रिकार्ड है कि वह वारदात के दौरान अपने शिकार को जिंदा नहीं छोड़ता. पिछले करीब एक साल का खाका बताता है कि कई खूंखार अपराधी जेल से बाहर आए, जिनमें हाल में जमानत पर छूटा ललितेश्वर, सोनू कंजड़, कानपुर का बदमाश रत्नेश उर्फ बउवा, कानपुर का ही संदीप, अलीगंज का हर्षित भल्ला जैसे अपराधी शामिल हैं. हर्षित भल्ला, रत्नेश व संदीप को भी पुलिस ने काफी शातिर बताया था और कहा था कि ये भी अपने टारगेट को जिंदा नहीं छोड़ते. पुलिस राजन, ओसामा, रिजवान और पप्पू यादव गैंग को भी खंगाल रही थी. एटीएम लूट कांड के बाद क्रिश्चियन कॉलेज परिसर में कैश बॉक्स बरामद होने के बाद पुलिस ने पेट्रोल पंप मालिक हत्याकांड से भी मामलों को जोड़ कर देखने की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला. बरामद बॉक्स को अहम कड़ी बताया गया था, पर परिणाम कुछ भी नहीं निकला. जबकि मामले की जांच में पुलिस की सर्विलांस शाखा और क्राइम ब्रांच समेत 16 टीमें जुटी थीं. ■

गोरखपुर को एम्स की सौगात जल्द

शत्रुंजय सिंह रैकवार

गोरखपुर खाद कारखाने की 25 वर्ष पाइपलाइन फटने के बाद कारखाना बन्द करने की घोषणा कर दी गई थी. वर्ष 2002 में जब कारखाने को हमेशा के लिए बन्द करने का निर्णय लिया गया था तब कारखाने के कर्मचारियों के साथ-साथ गोरखपुर शहर के लोगों की भी आंखें भर आईं थीं. 1 अप्रैल 2015 को सुबह-सुबह जब लोगों ने अखबारों में खाद कारखाना फिर से चलाने की खबर पढ़ी तो पुराने कर्मचारियों और गोरखपुर के लोगों की आंखें फिर से छलछला आईं. लेकिन इस बार उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे. सबकी जुबान पर एक ही चर्चा थी, गोरखपुर का खोया हुआ गौरव पुनः वापस मिल गया. गोरखपुर को उसका गौरव वापस दिलाने का श्रेय गोरखपुर के भाजपा सांसद महंत आदित्यनाथ को जाता है .

उल्लेखनीय है कि ढाई दशक पहले फर्टिलाइजर कारखाने की चिमनियां जब धुआं उगलती थीं तब पूर्वांचल के खेतों में स्वस्तिक खाद असर दिखाती थी और शहर में इसके कर्मचारियों की चहल-पहल रहती थी. शहर की पहली मारुति कार, पहली टीवी और फ्रिज इसी कारखाना परिसर में आया था. गोलघर, रेती चौक एवं उर्दू बाजार के दुकानदार फर्टिलाइजर वालों को विशेष छूट देते थे. महंगे से महंगा सामान किस्त पर लेने में फर्टिलाइजर वालों को कभी कोई मुश्किल पेश नहीं आती थी. कारखाने की बसें शहर में समृद्धि का प्रतीक बनकर घूमती थीं और बहुतेरे युवक फर्टिलाइजर कारखाने में नौकरी करने का सपना देखा करते थे. कारखाने के प्रशासनिक अधिकारी हरिद्वार सिंह बताते हैं कि उन दिनों कॉलोनी में 24 घंटे बिजली-पानी और दूसरी सुविधाएं मिलती थीं.

कारखाना बंद होने के ढाई दशक बाद अब लगता है कि गर्दिश के दिन जाने वाले हैं. यूपी के कई अन्य विकसित जिलों की तरह गोरखपुर भी तरक्की की नई इबारत लिखेगा. यह पूर्वांचल का पिछड़ापन कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. गोरखपुर में दो बड़े संस्थानों की स्थापना से यह उम्मीद जगी है. पहला संस्थान है खाद कारखाना और दूसरा एम्स. खाद कारखाना फिर से चलाने के लिए मोदी कैबिनेट ने 31 मार्च को हरी झंडी दिखा कर बाधा दूर कर दी. गोरखपुर में एम्स की घोषणा भी जल्द ही हाने वाली है. एम्स के लिए विभिन्न स्तरों से किए गए प्रयास और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों व समाजिक संगठनों द्वारा चलाए गए अब तक के सबसे सशक्त एवं लम्बे जनजागरण अभियान (प्रधानमंत्री को 139139 पोस्टकार्ड लिखने और मुख्यमंत्री के लिए सैकड़ों मीटर लम्बा हस्ताक्षरित बैनर तैयार करना इसमें शामिल है) का फल मिलने वाला है. गोरखपुर में 200 एकड़ जमीन तलाशने की कवायद अंतिम रूप लेने वाली है. मसौदा तैयार है, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इसे भी शीघ्र हरी झंडी दिखा सकते हैं.

फर्टिलाइजर कारखाने के साथ पाइप लाइन से रसोई गैस की उपलब्धता का रास्ता भी खुलेगा. गोरखपुर और बरौनी का खाद कारखाना फिर से चलाने के सार्थक प्रयास हो रहे हैं. दोनों खाद कारखानों की स्थापना पर छह-छह हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसके अलावा हल्दिया से गोरखपुर होते हुए जगदीशपुर तक गैस पाइप लाइन बिछाने पर एकमुश्त 10 हजार करोड़ रुपये की मंजूरी हुई है. खाद कारखाना फिर से चालू कराने के लिए लम्बे समय से प्रयासरत भाजपा सांसद महंत आदित्यनाथ कहते हैं कि आजादी के बाद ऐसा पहली बार होगा जब उत्तर भारत के औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कोई सरकार 22 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगी. पिछले तीन साल में गोरखपुर और आसपास के जिलों में विकास को गति मिली है. गोरखपुर में तकनीकी विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का बाल चिकित्सा संस्थान, सिद्धार्थनगर में विश्वविद्यालय, बस्ती में मेडिकल कालेज और इंजीनियरिंग कालेज, चारों ओर फोर लेन की सड़कों का जाल बिछाए जाने की योजनाएं, गोरखपुर के हवाई अड्डे का विस्तार, कुशीनगर में मैत्रेय और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण से इस पिछड़े क्षेत्र की सूरत ठीक हो रही है. रेल लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण के बाद गोरखपुर को जल्दी ही राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनों की सुविधा भी मिलने वाली है. खुद को गोरखपुरिया बताने से हिचकने वाले कल गर्व से कह सकेंगे, हां, हम गोरखपुरिया हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

समाजवादी पार्टी में अंतर्कलह

संतोष देव गिरि

सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव अपनी ही पार्टी, सरकार के मंत्रियों और विधायकों की समय-समय पर क्लास लेते रहते हैं. मुलायम को समाजवादी पार्टी के गठन से लेकर अपने राजनीतिक जीवन में शायद अब तक की सबसे बड़ी पीड़ा वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर हुई. जिसकी टीस उन्हें समय-समय पर चुभती रहती है. उत्तर प्रदेश में उनकी ही समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है और मुख्यमंत्री भी उनके बेटे अखिलेश यादव हैं. इसके बावजूद पहली बार सपा की लोकसभा सीट चार पर सिमट गई. राजनीति के जानकार इसे मोदी लहर के साथ-साथ पार्टी में चल रही गुटबाजी और वर्चस्व की लड़ाई को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. हालांकि खुद मुलायम भी सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार कर चुके हैं. मार्च 2012 में उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालने के बाद से अब तक तीन साल का समय तय कर चुके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल में संगठनात्मक ढांचे का जो स्वरूप होना चाहिए वह साकार नहीं हो पाया है. किसी भी पार्टी संगठन की रीढ़ जहां कार्यकर्ता होते हैं, वहीं पार्टी की मजबूती के लिए संगठन में एकजुटता का होना नितांत आवश्यक होता है, लेकिन कुछ जिलों में इसका घोर अभाव देखने में आता है. मसलन अति पिछड़े जनपद मिर्जापुर को ही लें. मिर्जापुर जिले की पांच विधान सभा सीटों में से तीन पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है. जबकि लोकसभा की सीट अबकी बार भाजपा-अपना दल गठबंधन के पाले में है. जिले की नगर विधान सभा सीट से प्रदेश के बेसिक शिक्षा एवं बाल पुष्टाहार राज्यमंत्री कैलाश चौरसिया विधायक हैं. इस सीट से उन्होंने तीसरी बार विजय हासिल की है. इसी प्रकार चुनार विधान सभा से समाजवादी पार्टी से जगदम्बा पटेल पहली बार जीत कर विधानसभा पहुंचे हैं. जबकि छानबे विधानसभा सीट से भाईलाल कोल विजयी हुए हैं. जिले की मंझवा और मड़िहान सीट सपा के हाथ से निकल गई. इसमें भी गुटबाजी को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है. पार्टी सूत्रों की मानें तो मंझवा सीट 2012 के विधान सभा चुनाव में निश्चित ही सपा की झोली में होती, लेकिन पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी का ही नतीजा रहा कि यह सीट हाथ से निकल गई. समाजवादी पार्टी ने पूर्व नौकरशाह राजेन्द्र पांडेय को यहां से मैदान में उतारा था, जिन्हें पराजय का सामना करना पड़ा और खुद उन्होंने अपनी पराजय के लिए पार्टी के ही कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराते हुए भितरघात का खुला आरोप लगाया था. इस जिले के पार्टी संगठन के क्रियाकलापों से लेकर गुटबाजी और खेमेबाजी की आवाज समय-समय पर उठती रही है. लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल पाया. प्रदेश नेतृत्व भी इस मुद्दे पर कुछ गंभीर नहीं दिखा. यही कारण है कि कहने को तो जिले में एक ही पार्टी संगठन है लेकिन यहां तीन गुट काम करते हैं. अभी पिछले दिनों पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने राजधानी स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित जिला, महानगर अध्यक्षों व महामंत्रियों की बैठक में पेंच कसते हुए मंत्री, विधायक व पदाधिकारियों को सामंजस्य बैठाकर संगठन में कार्य करने की हिदायत दी थी. मुलायम ने कहा कि उन्हें सब पता है कि कौन मंत्री, विधायक क्या कर रहा है. सपा प्रमुख ने बैठक में उपस्थित मुख्यमंत्री एवं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने कही. बावजूद इसके, यह जमीनी सच्चाई है कि मिर्जापुर जिले में पार्टी का संगठनात्मक ढांचा तीन गुटों में बंटा हुआ है. एक गुट लोहिया ट्रष्ट से संचालित होता है, जिसके मुखिया सपा जिलाध्यक्ष शिवशंकर यादव हैं. हालांकि इस पर पार्टी संगठन की मुहर भी लगी हुई है. दुसरा गुट जिला कार्यालय से तकरीबन दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित रेलवे स्टेशन के समीप नगर विधायक एवं बेसिक शिक्षा एवं बाल पुष्टाहार राज्यमंत्री कैलाश चौरसिया के कैम्प कार्यालय से संचालित होता है. अब बात करें तीसरे गुट की तो इसका संचालन पूर्व जिलाध्यक्ष आशीष यादव के विशुंदरपुर स्थित आवास से संचालित होता है. ऐसे में सोचा जा सकता है कि सपा सुप्रीमो के 2014 के मिशन को जो पलीता लगा वह कहीं ऐसा न हो कि 2017 के मिशन को भी नुकसान कर जाए. जिले में तीन गुटों में बंटी समाजवादी पार्टी पर नजर डालें तो वर्ष 2008 में समाजवादी पार्टी नेतृत्व ने कड़े निर्णय लेते हुए तत्कालीन सपा जिलाध्यक्ष शिवशंकर यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था. वह इसलिए क्योंकि पार्टी ने 2009 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए दस्यु सरगना ददुआ के छोटे भाई बालकुमार पटेल को मिर्जापुर लोकसभा सीट से पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया था. इसके विरोध में बगावत के स्वर सुनाई देने लगे थे. बात जैसे ही पार्टी नेतृत्व के कानों तक पहुंची, बिना किसी देरी के जिलाध्यक्ष रहे शिवशंकर सिंह यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था. कहा जाता है कि यह कार्रवाई तब पार्टी के ही एक विधायक के कहने पर हुई थी और शिवशंकर को हटाकर जिलाध्यक्ष की कुर्सी पर आशीष यादव की ताजपोशी करा दी गई थी. समय बीतने के साथ ही मजबूत पैठ बनाने में कामयाब हुए आशीष यादव को भी 2013 में एक झटके में जिलाध्यक्ष पद से हटाकर जिलाध्यक्ष पद पर अशोक यादव की ताजपोशी करा दी गई. कहा जाता है कि आशीष यादव को भी जिलाध्यक्ष पद से हटाने का तानाबाना किसी और ने नहीं बल्कि उसी ने बुना था जिसने उन्हें अध्यक्ष बनाने में महती भूमिका निभाई थी. यह सबकुछ इतनी जल्दी में और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव के जनपद आगमन के दौरान हुआ कि लोगों को सोचने-समझने का समय ही नहीं मिल पाया. आशीष यादव के हटने और अशोक यादव के आने के बाद भी शह-मात का खेल जारी रहा. अशोक यादव भी बहुत ज्यादा दिन जिलाध्यक्ष पद पर बने नहीं रहे. लोकसभा चुनाव 2014 से पूर्व आखिरकार अशोक यादव को भी हटना पड़ा और पुनः समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष की कमान पूर्व जिलाध्यक्ष शिवशंकर सिंह यादव के हाथों में आ गई. लोगों को उम्मीद थी कि अब शायद पार्टी में चल रही गुटबाजी पर लगाम लग जाएगी, लेकिन लोगों का सोचना गलत साबित हुआ और जिले में अब एक नहीं बल्कि तीन सामानान्तर संगठन चल रहे हैं. सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने प्रदेश मुख्यालय में पिछले दिनों हुई बैठक में साफ तौर पर कहा कि हमें रिपोर्ट मिली है कि प्रदेश के अधिकतर जिलों में मंत्री, विधायक और जिलाध्यक्षों तथा अन्य पदाधिकारियों में तालमेल नहीं है और ये सभी आपस में ही एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं. सपा प्रमुख का यह कहना बिल्कुल सही है. इस स्थिति से मिर्जापुर की सपा इकाई अछूती नहीं है. शायद ही कभी तीनों गुट एक मंच, एक स्थान पर दिखे होगें. बीते माह समाजवादी चिंतक डॉ. राम मनोहर लोहिया के जन्मदिवस समारोह पर सपा प्रमुख जहां लोहिया के बताए रास्ते पर चलने और एकजुटता की बात कह रहे थे, वहीं मिर्जापुर में नजारा इससे जुदा रहा. कार्यक्रम तो एक ही व्यक्ति के नाम रहा लेकिन लोहिया जयंती मनाने वाले गुट और स्थान अलग-अलग रहे. इसी से समझा जा सकता है कि पार्टी पदाधिकारियों पर सपा प्रमुख की हिदायतों का कितना असर है.

राज्यमंत्री कैलाश चौरसिया

जिलाध्यक्ष शिवशंकर यादव

पूर्व जिलाध्यक्ष आशीष यादव

मुख्यमंत्री के निर्देश भी ताक पर

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद सपा प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सूबे में सपाइयों की बढ़ती हुड़दंगबाजी देखते हुए न केवल नाराजगी जाहिर की थी बल्कि निर्देश भी जारी किए थे. होर्डिंग, बैनरबाजी, गाड़ियों पर पार्टी के झंडे से परहेज करने की हिदायत दी गई थी. लेकिन इससे कोई बाज नहीं आया. मुख्यमंत्री सह प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशों की किसी ने कोई परवाह नहीं की. कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी तक इसे अपनी शान के खिलाफ मानकर चल रहे है. झंडा, पदनाम आदि का उपयोग तो किया ही जा रहा है, वाहनों पर हूटरों का भी प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है. पार्टी के पदाधिकारियों का तो पूछना ही नहीं है उनके वाहनों पर हूटर का बजना तो मानो आम बात हो गई है. आम जनता ठगी सी रह जाती है जब लग्जरी गाड़ियों के काफिले संग नेता के वाहन हूटर बजाते हुए गुजरते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर यह किस नेता का काफिला है. प्रशासन भी सब जानते हुए इस ओर से ध्यान नहीं देता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाने पर विवाद

ब्यूरो कार्यालय

भारतीय टीम के धुरंधर बल्लेबाज विराट कोहली को उत्तराखंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाये जाने के बाद प्रदेश सरकार में बड़ा विवाद पैदा हुआ, जिसके बाद अब कांग्रेस में भी इसे लेकर विवाद हो गया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने यह कह कर विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाने पर सवाल खड़ा किया है कि गंगा और हिमालय से बड़ा उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर कोई हो ही नहीं सकता. किशोर उपाध्याय का यह भी कहना है कि यह भी देखा जाना चाहिए कि ब्रांड एम्बेसडर बनाने से प्रदेश को कोई लाभ होता है या नहीं. उल्लेखनीय है कि हाल में ही प्रदेश सरकार ने विराट कोहली को प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की थी. विवाद तब खड़ा हो हुआ, जब प्रदेश के पर्यटन मंत्री दिनेश धनै ने विराट कोहली को उत्तराखंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की जानकारी होने से सिरे से इनकार कर दिया. गौरतलब है कि प्रदेश की तमाम सरकारें प्रदेश की विभिन्न योजनाओं के लिए देश की नामचीन हस्तियों को ब्रांड एंबेसडर बनाने की घोषणा करती रही हैं, लेकिन इसका लाभ होता दिखता नहीं. भारतीय जनता पार्टी की निशंक सरकार के जमाने में सरकार ने गंगा की स्वच्छता के लिए स्पर्श गंगा नामक कार्यक्रम शुरू किया था और इसका ब्रांड एंबेसडर बॉलीवुड अभिनेत्री व भाजपा सांसद हेमामालिनी को बनाया था. बाद में सूचना अधिकार के माध्यम से एक दिलचस्प जानकारी सामने आई थी कि एक नृत्य कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर हेमामालिनी को सरकार द्वारा 31 लाख रुपये का भुगतान किया गया था. प्रदेश की हरीश रावत सरकार भी अब इसी राह पर चल पड़ी है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के विवादस्पद बयान और पर्यटन मंत्री दिनेश धनै द्वारा यह कहा जाना कि उन्हें विराट कोहली को प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसड्र बनाए जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है. अब इससे प्रदेश सरकार द्वारा विराट कोहली ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा पलीता लगना अब तय है. मुख्यमंत्री हरीश रावत ने खुद इस विवाद से पल्ला झाड़ लिया और मीडिया के सर इसका ठीकरा फोड़ दिया. हरीश रावत के इस बयान से अब प्रदेश के लोग हैरान हैं. लोगों का कहना है कि कोई क्रिकेटर इस हिमालयी राज्य को क्या दिला सकता है. फिर सरकार इस पर क्यों पैसा बरबाद करना चाहती है. ■

लापरवाही की भेंट चढ़ा पर्यटन विभाग

रेनू शर्मा

उत्तराखंड को विकास की पटरी पर लाने के लिए प्रदेश को पर्यटन राज्य की पहचान दिलाने के लिए मुख्यमंत्री हरीश रावत हर स्तर पर प्रयास करते नजर आते हैं. लेकिन इस विभाग की लापरवाही के कारण पर्यटन विभाग की करीब 50 करोड़ से अधिक की राशि लेप्स हो गयी, जिसका प्रभाव पर्यटन योजनाओं पर पड़ा है. करोंड़ो की राशि डूबने के बाद विभागीय मंत्री दिनेश धनै अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया और अब पर्यटन विभाग के अधिकारियों से नाराजगी जताने ढोंग कर रहे हैं. पिछले साल पर्यटन विभाग के अधिकारी बार-बार बजट को लेकर रोना रोते रहे कि बजट नहीं होने से पर्यटन से जुड़ी परियोजनाओं को पूरा करने में बाधाएं उत्पन्न हुई हैं. लेकिन बजट मिलने के बाद विभागीय अधिकारी इसका उपयोग करने में पूरी तरह से असफल रहे. अफसरों की लापरवाही के कारण एडीबी के तहत मिले 32 करोड़ की राशि पर्यटन विभाग समय पर खर्च नहीं कर पाया और शेष 18 करोड़ से अधिक की राशि केन्द्रपोषित योजनाओं की है जो खर्च नहीं हो पाई है, जिसका नतीजा यह हुआ कि न ही केवल राज्य पोषित बल्कि केन्द्र पोषित दोनों ही योजनाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं. नए पर्यटक स्थलों के चयन के अलावा साहसिक पर्यटन व ग्रामीण पर्यटन तो पटरी से उतर चुका है. पर्यटन विभाग के सचिव डा. उमा कांत पनवार का इस बारे में अपना ही तर्क है. डा. पनवार का कहना है कि तकनीकी कारणों की वजह से करोड़ों की राशि लेप्स हुई है. पर्यटन मंत्री दिनेश धनै इस बात को स्वीकार करते हैं कि विभाग के अधिकारी यदि सतर्क रहते तो इस तरह की नौबत ही नहीं आती. सूबे की जनता अब मंत्री जी से सवाल कर रही है कि यदि आप जो अब हाय तोबा मचा रहे हैं, वही समय से इन अफसरों की लगाम कसते तो निश्चित रूप से इस धन का सदुपयोग हो गया होता. और राज्य का पर्यटन विभाग सज सवर गया होता. करोड़ों के बजट का डूबना इस बात को दर्शाता है कि राज्य के मंत्री और अफसर शाही की लापरवाही की वजह से कहीं न कहीं चारधाम यात्रा इस बार निश्चित रूप से प्रभावित होगी. क्योंकि विभाग अब भी इस बात का इंतजार कर रहा है कि वित्त विभाग चारधाम यात्रा के मद्देनजर कुछ अतिरिक्त फंड पर्यटन विभाग को मुहैया कराएगा. विकास के लिए दिए गए सरकारी धन का समय से प्रदेश के हित में खर्च न कर पाना पूरी हरीश सरकार की नाकामी को उजागर कर रहा है. ■

कुख्यात अपराधी अमित भूरा गिरफ्तार

रेनू शर्मा

उत्तराखंड कुख्यात अपराधी भूरा अपने इंटरनेट शौक के कारण पुलिस की गिरफ्त में आया. अपनी इसी गलती के कारण भूरा पुलिस के गिरफ्त में आया. जानकारी के मुताबिक देहरादून से प्रकाशित एक हिंदी अखबार के ई-पेपर पर अपनी खबर पढ़ने के कारण भूरा पकड़ा गया. उसने उस नंबर पर इंटरनेट ब्राउज कर दिया, जिसके हार्टस्पाट से वह दूसरे फोन का वाट्सएप चलाता था. मामले की जांच में जुटे वरिष्ठ अधिकारी ने दो सप्ताह पहले भूरा की गिरफ्तारी के संकेत दिये थे. उक्त अधिकारी ने बताया था कि भूरा की तरफ से गलती का इंतजार कर रही पुलिस टीम को अहम सुराग मिल गया. इस सुराग के बाद भूरा के लोकेशन के बारे में जानकारी जुटाई गई. इस जानकारी को पंजाब पुलिस तक पहुंचाया गया. उसके बाद पुलिस को यह सफलता मिली. भूरा के तकनीकी सलाहकारों ने भी उसे पूरी तरह से प्रशिक्षित किया था. इसकी वजह से ही वह तकनीकी इस्तेमाल के बाद भी पकड़ में नहीं आ रहा था. उसने सबसे पहले एक सिम कार्ड का इस्तेमाल शुरू किया. उसके आधार पर उसने एक वाट्सएप अकाउंट चालू किया. उसके बाद उस सिम कार्ड को तोड़ कर फेंक दिया. फिर दूसरे मोबाइल फोन में नया सिम डाला. दूसरे वाले फोन में भूरा ने इंटरनेट सेवा चालू कराया. दूसरे मोबाइल फोन के वाईफाई से वह पहले वाले फोन पर इंटरनेट चलाता रहा. इस दौरान उसने वाट्सएप समेत कई तकनीनी सुविधाओं का इस्तेमाल किया. वह वाट्सएप पर वॉयस रिकार्ड कर अपने गुर्गों के संपर्क में था. ऐसा करने से पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही थी. इस बीच भूरा ने वह गलती कर दी, जिसका पुलिस लंबे समय से इंतजार था. भूरा ने दूसरे फोन पर इंटरनेट ब्राउज किया और उसने दूसरे फोन पर देहरादून से प्रकाशित एक हिंदी अखबार का पेज खोला. इस पेज पर उसने अपने बारे में खबरें पढ़ीं. उधर, इंटरनेट कूकिज का इस्तेमाल कर पुलिस ने दूसरे वाले फोन का ब्राउजिंग डाटा हासिल कर लिया. इसमें पुलिस ने पाया कि इस फोन पर सिर्फ भूरा से संबंधित खबरें ही ज्यादा देर तक पढ़ी जा रही हैं. फिर पुलिस ने उस फोन से भूरा के कनेक्शन का पता लगाया. इस सूचना को तुरंत डेवलप कर लोकेशन का पता किया. इस लोकेशन के बाद भूरा के पंजाब में मौजूदगी का पता चला. फिर इस सूचना को पंजाब पुलिस को दिया गया, जिसके बाद यह सफलता मिली. उत्तराखंड पुलिस के प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका भूरा सिर्फ मोबाइल फोन के चक्कर में जानलेवा हमला कर चुका था. यह ऐसा हमला था जिसने उसे जेल पहुंचा दिया. इसके बाद भूरा अपराध की दुनिया में आगे बढ़ता रहा. भूरा ऐसा नाम है जिसके सुनने के बाद पुलिसवालों के मन में भी भय पैदा होता है. जिसने गिरफ्तारी के बाद पुलिस वालों को भी धमकी दी थी. उसे पुलिस वाले कुख्यात सिरफिरे बदमाश के रूप में मानते हैं. देहरादून में उसका नाम पहली बार विशाल मेगामार्ट में डकैती के चलते आया था. उसने दिल्ली पुलिसकर्मी के बेटे तथा मेगामार्ट के मैनेजर को मिलाकर डकैती की योजना को अंजाम दिया. भूरा को लेकर लोगों में भय का माहौल तब बढ़ गया जब उसने रुड़की जेल के बाहर गैंगवार में तीन को मौत के घाट उतार दिया. रुड़की में हुई गैंगवार में कुख्यात अन्य बदमाश चीनू पंडित की हत्या के लिए उसने हमला किया. इस दौरान चीनू पंडित तो बच गया अन्य तीन बदमाश मारे गये. भूरा के आपराधिक इतिहास पर नजर रखने वाले बताते हैं कि उसने 15 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रखा था. आपसी झगड़ में मोबाइल फोन गवांने के बाद उसे वापस पाने के चक्कर में उसने कातिलाना हमला किया. फिर वह गिरफ्तार होकर जेल गया जहां उसकी मुलाकात कुख्यात बदमाशों से हुई. फिर उसे अन्य बदमाशों की शह मिलती गयी और वह आग बढ़ता गया. बताया जाता है कि उसके खिलाफ वर्तामान में 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं. भूरा पहले दूसरों के लिये अपराध करता था. बाद में उसने खुद के लिये उगाही के साथ-साथ सुपारी लेकर हत्या भी करने लगा था.

भूरा के फरारी की कहानी

5 अगस्त 2014को रुड़की जेल के बाहर चीनू पंडित और उसके साथियों पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में भूरा शामिल था. इसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी. उत्तराखण्ड पुलिस ने भूरा को 9 अगस्त को गिरफ्तार किया, तब से वह दून जेल में था. 14 दिसंबर की शाम छह बजे पांच पुलिसवाले इसे बागपत कोर्ट में पेशी पर ले गए. 15 दिसंबर की सुबह पुलिस अमित भूरा को लेकर टटीरी रेलवे स्टेशन पर पहुंची. जहां से वे आटो रिक्शा से बागपत के लिए निकले. बागपत मेन चौक पर दो और युवक ऑटो रिक्शा में बैठ गए और फिर कुछ आगे चलकर आटो रिक्शा सवार युवक पुलिसवालों की आंखों पर मिर्च का स्प्रे छिड़कर भूरा को छुड़ाकर भाग निकले. इस दौरान बदमाश पुलिसवालों की दो एके-47 और एक एसएलआर भी लूट ले गए. ■

feedback@chauthiduniya.com

> उत्तर प्रदेश का शासन तंत्र कितना त्वरित एक्शन लेता है, इसकी बानगी देखिए. प्राकृतिक आपदा से किसानों के मरते और तबाह होते हुए हो महीने से अधिक समय हो गया. लेकिन मुख्यमंत्री का सात अप्रैल को निर्देश जारी होते ही मुख्य सचिव एकदम से सक्रिय हो गए. उन्होंने फरवरी मार्च में हुई ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से फसलों के नुकसान का स्थलीय निरीक्षण कराने, सत्यापन कराने और प्रभावित किसानों को दी गई राहत सहायता की समीक्षा के साथ-साथ किसानों की मौत का कारण जानने के लिए मंडलवार वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय तीन समितियों का गठन कर दिया.

राहत पर आफत

मौत के मंजर में कुशासन का खंजर

प्रभात रंजन दीन

प्राकृतिक आपदा से किसानों की बदहाली का मसला क्षुद्र राजनीति के कारण बदबूदार भी होता जा रहा है. किसान आत्महत्या कर रहे हैं, फसलों की तबाही के कारण किसानों की सदमे से मौतें हो रही हैं. लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार शुरुआत से इसे झूठा साबित करने में लगी रही. किसानों को तत्काल मदद करने के बजाय शासन-प्रशासन यह कहता रहा कि घरेलू कलह और कर्जे के कारण किसान मर रहे हैं. ऐसे निर्लज्ज तर्क देने वाली सरकार के मुखिया अखिलेश यादव ने सात अप्रैल को मुख्य सचिव आलोक रंजन को निर्देश दिया कि किसानों की बेतहाशा हो रही मौत की वजहों का वे पता लगाएं और उसकी रिपोर्ट पेश करें. सरकार अभी भी किसानों की मौत के कारण ही तलाश रही है, किसानों के परिवार तक राहत कब तक पहुंचेगी यह ईश्वर भी नहीं बता सकता. अखिलेश यादव ने प्रदेश में ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से हुई फसलों की क्षति का स्थलीय निरीक्षण और सत्यापन करने को भी कहा है. मुख्यमंत्री के इस ताजा निर्देश से ही पता चल जाता है कि किसानों को उनकी बदहाली से उबारने के लिए राज्य सरकार अब तक क्या कर रही थी. प्रदेश के किसानों की बदहाली का जायजा लेने आए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सात अप्रैल को ही आगरा में स्पष्ट कहा कि यूपी में किसानों की जाति पूछ-पूछ कर मुआवजा दिया जा रहा है. आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति कितनी दारुण है.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आगरा के अछनेरा में किसानों से मुलाकात की और आश्वासन दिया कि इस मुसीबत की घड़ी में केंद्र सरकार किसानों के साथ खड़ी है. केंद्र सरकार की तरफ से किसानों की हर संभव मदद की जाएगी. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आरोप लगाया कि यूपी में जाति देखकर किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है. उन्होंने कहा केंद्र सरकार किसानों तक सीधे मदद पहुंचाने की कोशिश करेगी और सहायता राशि किसानों के खातों तक सीधे पहुंचेगी. बेमौसम बारिश से बर्बाद हुई फसल का किसानों को उचित मुआवजा मिलेगा. केंद्रीय मंत्री के आश्वासनों और किसानों की मौत की राज्य सरकार द्वारा की जा रही खुफियागीरी से आम जनता की तकलीफ कम नहीं होने वाली. क्योंकि जमीनी हकीकत यही है कि प्रभावित किसानों के पास मुआवजा नहीं पहुंच पा रहा है. अभी तो मुख्यमंत्री का निर्देश पाने के बाद प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन किसानों की मृत्यु के कारणों की समीक्षा के लिए मंडलवार वरिष्ठ अधिकारियों की तीन समितियों का गठन करेंगे और उनकी जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा करेंगे. तब तक हर साल आने वाली बाढ़ की तरह कोई दूसरी प्राकृतिक या राजनीतिक आपदा आ जाएगी और पहली वाली आपदा में हवा में बंटी राहत को धो-पोंछ कर ले जाएगी.

उत्तर प्रदेश का शासन तंत्र कितना त्वरित एक्शन लेता है, इसकी बानगी देखिए. प्राकृतिक आपदा से किसानों के मरते और तबाह होते हुए हो महीने से अधिक समय हो गया. लेकिन मुख्यमंत्री का सात अप्रैल को निर्देश जारी होते ही मुख्य सचिव एकदम से सक्रिय हो गए. उन्होंने फरवरी मार्च में हुई ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से फसलों के नुकसान का स्थलीय निरीक्षण कराने, सत्यापन कराने और प्रभावित किसानों को दी गई राहत सहायता की समीक्षा के साथ-साथ किसानों की मौत का कारण जानने के लिए मंडलवार वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय तीन समितियों का गठन कर दिया. उन्होंने गठित समितियों के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश भी दे दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में तत्काल जाकर व्यापक भ्रमण एवं समीक्षा कर उसकी रिपोर्ट पेश करें. राग दरबारी का यह दृश्य उत्तर प्रदेश सरकार की असलियत है.

किसानों की मौत का कारण नहीं जानने वाली भोली-भाली उत्तर प्रदेश सरकार सियासत करना खूब जानती है. उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र को 15 मार्च को ही पत्र लिख कर सूचित कर दिया था कि चक्रवाती तूफान के कारण हुई अतिवृष्टि-ओलावृष्टि से कृषि फसलों के नुकसान की राशि एक हजार करोड़ रुपये से अधिक है. यूपी सरकार ने 25 मार्च को कुल 31 जिलों में हुई कृषि क्षतियों को सम्मिलित करते हुए 744.28 करोड़ की धनराशि का मेमोरेंडम भी केंद्र सरकार को भेज दिया था. सात अप्रैल को जब केंद्रीय मंत्री की टीम किसानों की बदहाली का जायजा लेने उत्तर प्रदेश पहुंच गई, तब राज्य सरकार ने आनन-फानन राज्य आपदा मोचक निधि से 301.41 करोड़ रुपये स्वीकृत कर प्रभावित जिलों में भेज दिए. फिर किसानों को दी गई राहत का निरीक्षण करने के पूर्व के आदेश का क्या मतलब और औचित्य है? बहरहाल, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किसानों को दी जा रही राहत राशि का सत्यापन वरिष्ठ अधिकारियों से कराने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कृषि उत्पादन आयुक्त से कहा कि वे अधिकारियों को नामित करते हुए उनके माध्यम से सत्यापन कराएं. ■

feedback@chauthiduniya.com

राहत और मुआवजे का क्रूर सच

फसलों के भारी नुकसान पर किसानों को जो मुआवजे दिए भी गए उनका क्रूर सच जान लीजिए. कानपुर देहात के अमरौधा गांव के किसान सर्वेश कुमार को 750 रुपये का चेक मुआवजे के बतौर दिया गया. कानपुर की ही पुष्पा देवी को मंडलायुक्त इफ्तिखारुद्दीन ने 1450 रुपये का चेक देकर गौरवान्वित महसूस किया. यह तो राहत की तसली पर पक रहे चावल का एक दाना भर है. एक दाना टटोलिए तो पूरे भात का भूत पता चल जाएगा. किसानों की फसलों के भारी नुकसान के एवज में किसी को दो सौ तो किसी को पांच सौ और हजार रुपये का मुआवजा दिया जा रहा है, उस पर तुर्रा यह कि सीएम साहब ने कहा है कि सभी जिलों के जिलाधिकारी किसानों को सीधे चेक से पैसा न दें बल्कि खुद मौके पर कैम्प लगाकर यह राशि बांटें. दो सौ चैर सौ रुपये का चेक बांट रहे जिलाधिकारियों से मुख्यमंत्री ने साफ-साफ कहा है कि वे किसानों की ज्यादा से ज्यादा मदद करें. साथ ही सीएम ने किसानों को बांटी जा रही राहत राशि का वरिष्ठ अफसरों से सत्यापन कराने का भी निर्देश दिया है. यह एक चुटकुले की तरह है जो दुखद और वीभत्स-हास्य की तरह है. एक तरफ किसानों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा. दूसरी तरफ सम्बन्धित जिलों के प्रशासन द्वारा किसानों की मौत की आधिकारिक पुष्टि किए जाने के बावजूद सरकार इस पर राजी नहीं हो रही. अब अन्नदाता खुद अपना पेट भरने के लिए दूसरे का मुंह देख रहा है. सरकार केवल कागजी योजना और मुंहबोले निर्देश देने में ही जुटी है. प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन का एक बयान यह भी आया था कि मुआवजा केवल उन्हीं 35 किसानों के परिवार को मिलेगा जो आत्महत्या कर चुके हैं. जब सरकार के मुखिया किसानों की आत्महत्या की बात मानते ही नहीं तो मुख्य सचिव ने आत्महत्या की बात कैसे कबूल की. अब आप मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का एक आदेश देखिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस किसान की 50 प्रतिशत या उससे ज्यादा फसल बर्बाद हुई है, उसी किसान को मुआवजा मिलेगा. यानी, जिस किसान की फसल 49 या 48 प्रतिशत बर्बाद हुई है, उसके लिए सरकार का कोई औचित्य नहीं है. इन स्थितियों से कई सवाल उठते हैं. लेकिन सवाल अतार्किक सरकारी फैसलों, या सरकारी फैसलों के विचित्र विरोधाभास का भी नहीं है. अहम सवाल उत्तर प्रदेश की हास्यास्पद शासन-व्यवस्था का है.

सरकार किसानों की मौत को आत्महत्या नहीं मानती है

चौथी दुनिया के बीते हफ्ते के अंक में यह लिखा गया था कि खबर लिखे जाने तक उत्तर प्रदेश के 65 किसान अपनी जान दे चुके थे. खबर प्रकाशित होने तक मृत्यु की संख्या बढ़ने का अंदेशा जताया गया था. ऐसा ही हुआ. किसानों की मौत का आंकड़ा सौ के करीब पहुंच चुका है. आधिकारिक तौर पर पूछें तो सरकार को किसानों की मौत के बारे में कोई जानकारी ही नहीं. सनद रहे, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह वर्ष किसान-वर्ष के रूप में घोषित है. 20 मार्च को विधानसभा में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के आत्महत्या करने की बात को सिरे से नकार दिया था. सरकार ने 25 किसानों की मौत को स्वीकार किया लेकिन आत्महत्या की बात नहीं मानी. सरकार किसानों की मौतों को उनकी बीमारी या घरेलू कलह बताती रही. उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की मौतों का हिसाब ही नहीं जुटा पा रही है. सरकार फसलों के नुकसान को किसानों की मौत की वजह नहीं मानती. विचित्र सरकारी तर्क है कि बेमौसम बरसात और ओले गिरने से किसानों की मौत हुई है. सरकार कहती है किसी भी किसान ने आत्महत्या नहीं की है.

कोयले की काली कमाई का कड़वा सच

विजय पाण्डेय

नॉर्दर्न कोल फिल्ड लिमिटेड की कोयला परियोजनाओं से निजी औद्योगिक घरानों को ढुलाई किए जाने वाले कोयले की भीषण घटतौली का धंधा चल रहा है. इसमें बाट-माप विभाग की मिलीभगत है. इस धंधे के कारण सैकड़ों वाहन स्वामी भुखमरी की कगार पर आ चुके हैं. एनसीएल परियोजना के धर्म कांटे व निजी कम्पनियों के धर्म काटों में 200 से 500 किलो का अन्तर आ रहा है, जिसकी वजह से ढुलाई में प्रयुक्त वाहनों के कोयले का वजन घट रहा है. निजी कम्पनियां अपने कांटों को सही न कराकर कोयले के घटे हुए वजन का अंतर वाहन के किराए से काट लिया जाता है. वर्तमान समय में अनपरा, शक्तिनगर, रेनूकूट, डाला, चोपन आदि के हाइवे वाहन स्वामी इस घटतौली-गोरखधंधे का शिकार हो रहे हैं. परियोजना प्रबंधन से लेकर निजी कम्पनियों तक सैकड़ों बार गुहार लगाई गई किन्तु न तो बाट माप विभाग द्वारा इसको संज्ञान में लिया गया और न ही एनसीएल या निजी कम्पनी प्रबंधन ने इस पर ध्यान दिया. अब हालात यह है कि बड़े पैमाने पर वाहन स्वामियों पर रोड टैक्स, फिटनेस व इन्श्योरेंस का बढ़ता बोझ उनके लिए परेशानी का कारण बन गया है . रोड टैक्स व परमिट न लेने की दशा में सरकार को भी भारी नुकसान हो रहा है. खबर यह भी यह है कि निजी कम्पनियों के कुछ एजेंट वाहनों के कागज न होने की स्थिति में पुलिस व आरटीओ की इन्ट्री लेकर ट्रांस्पोर्टरों के माध्यम से कोयले का परिवहन किया जा रहा है. इस घटतौली के खेल में एनसीएल के कुछ अधिकारी व निजी कम्पनियों के बीच सौदेबाजी है. धर्म कांटे के नियमानुसार कैलीब्रेशन हर तीन माह पर होता है, लेकिन सोनभद्र के औद्योगिक क्षेत्र में कांटों का कैलीब्रेशन वर्षों से नहीं हो रहा और उसका खामियाजा ट्रकर्स भुगत रहे हैं. कोयला परियोजनाओं से प्रतिदिन लगभग 300 से 400 गाड़ी कोयले का परिवहन निजी औद्योगिक घरानों में किया जाता है.

हिंडाल्को इंडस्ट्रीज द्वारा कोयला डिस्पैच की जाने वाली सभी गाड़ियों को सीसी टीवी कैमरे से होकर गुजारा जाता है, फिर भी कोयले के वजन में 200 से 500 किलोग्राम तक का वजन कम हो रहा है. कम होने वाले कोयले की कटौती की रकम की मोटी कमाई से निजी कम्पनियां व ट्रांस्पोर्टर मालामाल हो रहे हैं. सूत्रों का कहना है कि बाहर डिस्पैच होने वाले वाहनों से कोयला लोड कराने का एनसीएल के अधिकारी वाहन स्वामी से 200 से 500 रुपये प्रति ट्रक वसूल करते हैं. एनसीएल से बाहर जाने वाली गाड़ियों को पैसा लेकर ओवरलोड होने की दशा में भी डिस्पैच कर दिया जाता है.

परियोजना प्रबंधन से लेकर निजी कम्पनियों तक सैकड़ों बार गुहार लगाई गई किन्तु न तो बाट माप विभाग द्वारा इसको संज्ञान में लिया गया और न ही एनसीएल या निजी कम्पनी प्रबंधन ने इस पर ध्यान दिया. अब हालात यह है कि बड़े पैमाने पर वाहन स्वामियों पर रोड टैक्स, फिटनेस व इन्श्योरेंस का बढ़ता बोझ उनके लिए परेशानी का कारण बन गया है .

पिछले दिनों सोनभद्र दौरे पर आए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को ट्रक स्वामियों के एक समूह ने ज्ञापन सौंपने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे. घटतौली से आजिज जाकर ट्रक स्वामियों ने परियोजना व दुद्धी स्थित बाट-माप विभाग की मिलीभगत के खिलाफ बीड़ा उठाया है. स्थानीय वाहन मालिकों ने मुख्यमंत्री से इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर इसमें लिप्त अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. ■